

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 1977/पौष 10, 1899
No. 53] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 1977/PAUSA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate pagling is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

आदेश

ORDER

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1977

New Delhi, the 23rd November, 1977

क्र०आ० 3981—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 87-कन्जीराप्पाली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अब्राहम चाको, कदमपुझा, पाराथोडे, इलाय्यूर कन्जीराप्पाली, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रवेशित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्पन्न सूचनाएं दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उनके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री अब्राहम चाको को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आवेग की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० केरल-वि०सं०/87/77]

S.O. 3981.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Abraham Chacko, Kadamapuzha, Parathode P.O. Kanjirappally, a contesting candidate for general election to the Kerala Legislative Assembly held in March, 1977 from 87-Kanjirappally constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Abraham Chacko to be disqualified for being chosen a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/87/77]

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1977

क्र०आ० 3982—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 67-कोडुनाल्लूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार

श्री नेलीपाराम्बिल वासु, नेलीपाराम्बिल वीडु, पी वेम्बल्लुर डाकघर बाया इरीयाव कोडुग्गल्लुर, जिला तिरुचुर, केरल राज्य, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री नेलीपाराम्बिल वासु का समर्थ के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[ग० के०-वि०म०/७७/७७]

ORDER

New Delhi, the 28th November, 1977

S.O. 3982—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nelliparambil Vasu, Nelliparambil Veedu, P Vemballur P O, via Eriyad, Kodungallur, Tiruchur District, Kerala State, a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in March, 1977 from 67-Kodungallur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Nelliparambil Vasu to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. KL-LA/67/77]

आदेश

का० प्र० 3983—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 को हुए विधान सभा के निर्वाचन के लिए 5-मद्रासलम (अ०ज०आ०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोदे रामैया, बाल फोडपेटा कुनावथम डाकघर भद्राचलम तालुक, जिला ब्रह्मभम (अन्ध्र प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मोदे रामैया को समर्थ के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[न० प्र०-वि०स०/५/७७]

आई०के०के० मेनन, सचिव

ORDER

S.O. 3983—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sode Ramaiah, Walfordpeta Kunavaram P.O., Bhadrachalam Taluk, Khammam District, (Andhra Pradesh), a contesting candidate for the general election held in March, 1977 to the House of the People from 5, Bhadrachalam (ST) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sode Ramaiah to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No AP-LD/5/77]

I. K. K. MENON, Secy.

गृह मंत्रालय

मारुति जांच आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 19 नवम्बर 1977

का० प्र० 3984—मारुति जांच आयोग (जिसे इसमें आगे आयोग कहा गया है) जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तारीख 11-8-1977 की अधिसूचना संख्यांक 613(ई) द्वारा और आगे उपरिर्तित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तारीख 20 जुलाई, 1977 की अधिसूचना संख्यांक का० प्र० 573(ई) के साथ पठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तारीख 30 मई, 1977 की अधिसूचना संख्यांक का० प्र० 377(ई) द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 के अधीन गठित किया गया है, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) और जांच आयोग (केन्द्रीय) नियम, 1972 (जिन्हें इसमें क्रमशः अधिनियम और नियम कहा गया है) की क्रमशः धारा 8 और नियम 5 के उपनियम (8) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का तथा उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करने हुए अपने प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए इनके द्वारा निम्नलिखित आदेश करता है—

1 नाम—इस आदेश का नाम मारुति जांच आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) आदेश, 1977 है।

2 आयोग की कार्यवाही साधारणतः अंग्रेजी भाषा में होगी। किन्तु आयोग अपने विवेकानुसार किसी भी बैठक के दौरान इस बात की अनुज्ञा दे सकेगा कि कार्यवाही हिन्दी में की जाए। आयोग को याचिकाएँ और अन्य लिखित निवेदन हिन्दी में या अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं।

परन्तु यदि कोई याचिका या शपथपत्र हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में है तो आयोग उसे तब अनुज्ञा कर सकता है जब उसके साथ उसका हिन्दी या अंग्रेजी में अधिप्रमाणित अनुवाद हो।

3 कार्यालय का पता—जब तक और आगे आदेश नहीं दिया जाता है, आयोग का मुख्यालय 10 जनपथ, नई दिल्ली में होगा और सभी पत्र इसी पते पर मारुति जांच आयोग के सचिव को तब तक भेजने जाने चाहिए जब तक उस पते में परिवर्तन की अधिसूचना प्रकाशित नहीं की जाती।

4. काम के घटे :—आयोग का कार्यालय केन्द्रीय सरकार के अवकाश दिनों और बन्द दिनों को छोड़कर सभी दिन पूर्वाह्न 10-00 बजे से 1-15 बजे अपराह्न तक और अपराह्न 2-00 बजे से 5-15 बजे अपराह्न तक खुला रहेगा। किन्तु पक्षवादी और जनता के साथ कामकाज का समय काम वाले दिन पूर्वाह्न 10.30 बजे और 4.30 बजे अपराह्न के बीच होगा (इसमें 1.30 अप० से 2.00 बजे अप० तक भोजन का समय छोड़ दिया जाएगा)।

5. प्रवेश का अधिकार :—आयोग के कार्यालय परिसर में प्रवेश पाम द्वारा विनियमित होगा जो प्रवेश के पूर्व स्वागत कक्ष से प्राप्त किया जा सकता है।

6. बैठकों का स्थान :—आयोग अपनी बैठके साधारणतया नई दिल्ली में ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो वह उचित समझे।

7. बैठकों के समय आदि का अधिगूचित किया जाना :—आयोग की बैठकों की तारीखें, समय और स्थान समय-समय पर अधिगूचित किए जाएंगे।

8. यदि लोक हित में यह समीचीन या आवश्यक है कि कोई बैठक नई दिल्ली से बाहर की जाए तो उसकी विधिवत सूचना किसी उचित रीति से पहले ही की जाएगी।

9. सार्वजनिक सुनवाई :—आयोग द्वारा की जाने वाली सुनवाई जन-साधारण के लिए खुली रहेगी किन्तु जब आयोग किसी विशेष वस्तु या व्यक्तियों अथवा किसी विषय वस्तु के संबंध में यह निदेश देना ठीक समझे कि उसकी सुनवाई बन्द कमरे में होगी तब वह जनसाधारण के लिए खुली नहीं रहेगी।

परन्तु जब यह आवश्यक प्रतीत हो कि उस न्यायालय कक्ष में जहाँ आयोग सार्वजनिक सुनवाई करने का आशय रखता है या कर रहा है, वर्णकों के प्रवेश को विनियमित किया जाए तब आयोग विनिश्चित आदेश द्वारा आवश्यक निदेश जारी कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जारी किए गए ऐसे किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो उसे अनिवार्य माना जा सकेगा।

परन्तु यह और कि किसी भी वर्णक को आयोग के न्यायालय कक्ष में कोई अटैची या ब्रीफकेस या बैग या अन्य आधान या पैकेट जिसमें रखा हुई वस्तु दिखायी नहीं देती है अथवा कोई हथियार, उपकरण या किसी प्रकार की अन्य कोई वस्तु या कोई उपस्कर जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी पैदा हो सकती है या जो आयोग की कार्यवाही के व्यय स्थिर रूप से संचालन में बाधा डाल सकती है, अपने साथ नहीं ले जाने दिया जाएगा।

10. किन्तु यह निर्बंधन विधि पुस्तकों और ऐसे ही अन्य प्रकाशनों को जो खुले आधान में हो, लागू नहीं होगा।

11. दर्शकों को उस न्यायालय कक्ष के भीतर जहाँ आयोग अपनी बैठकें करता है, किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) की फोटो लेने की अनुमति नहीं होगी।

12. विषय वस्तु से अवगत व्यक्तियों के शपथ पत्र :—आयोग कार्यवाही के किसी भी स्तर पर ऐसे व्यक्तियों से जिनकी बाबत उसकी यह राय है कि उन्हें उन बातों से जिनकी आयोग के समक्ष जांच की जा रही है, सुसंगत तथ्यों की जानकारी है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे तथ्यों के कथन या शपथपत्र दाखिल करें। आयोग जिस शपथपत्र को दाखिल करने की अपेक्षा करता है उस पर ऐसे प्राधिकारी के समक्ष शपथ ली जाएगी जो शपथ दिलाने के लिए वैध रूप से समक्ष है।

13. शपथपत्रों की आवश्यक बातें :—आयोग के समक्ष दाखिल किए जाने वाले शपथपत्र को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :—

(1) अच्छा होगा कि वह हिन्दी या अंग्रेजी में हो और यदि वह हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में है तो उसके साथ

उसका हिन्दी या अंग्रेजी अनुबाद होना चाहिए जो किसी अधिवक्ता या प्रथम दर्जे मजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्रमाणित हो;

(2) वह प्रथम पृष्ठ में लिखा होना चाहिए और पैराग्राफों में विभाजित होना चाहिए जो क्रमवार संख्यांकित हों। तथ्य का प्रत्येक साक्ष्यवान तथ्य एक पृष्ठ पर ही विषय वस्तु होनी चाहिए;

(3) उसमें अभिसाक्षी का सही वर्णन, उपजीविका और निवास स्थान दिया होना चाहिए; और

(4) उसका निम्नलिखित रीति से संस्थापित होना चाहिए :—
“संस्थापित किया जाता है कि—

(क) इस शपथपत्र के पैराग्राफों में किए गए कथन मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं;

(ख) इस शपथपत्र के पैराग्राफों में किए गए कथन उस जानकारी पर आधारित हैं जो मुझे से मिली है और जिसके संबंध में मेरा विश्वास है कि वह सही है;

स्पष्टीकरण :—जहाँ ऐसी जानकारी उस जानकारी पर आधारित है जो :

(i) किसी व्यक्ति से प्राप्त हुई है वहाँ ऐसे व्यक्ति का नाम, वर्णन, उपजीविका और सही पता शपथपत्र में विनिश्चित किया जाएगा;

(ii) किसी दस्तावेज या अभिलेख से प्राप्त हुई है वहाँ उस दस्तावेज या अभिलेख का विनिश्चित और स्वरूप तथा ऐसी दस्तावेज या अभिलेख की अभिरक्षा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति का नाम, वर्णन और पता शपथपत्र में विनिश्चित किया जाएगा

(iii) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हुई है वहाँ ऐसी जानकारी का स्रोत शपथपत्र में प्रकट किया जाएगा।

(ग) इस शपथपत्र के पैराग्राफों में किए गए कथन मेरे विश्वास के अनुसार सही हैं।

(घ) इस शपथपत्र के पैराग्राफों में किए गए कथन आयोग को मेरे निवेदन हैं।

(5) यदि अभिसाक्षी शपथपत्र में किए गए पूरे कथन या उसके किसी भाग के लिए किसी दस्तावेज पर निर्भर करता है तो वह मूल दस्तावेज या उसका सम्यक् रूप से अनु-प्रमाणित प्रति शपथपत्र के साथ दाखिल की जाएगी। यदि ऐसी दस्तावेज की मूल प्रति अभिसाक्षी के कब्जे या नियंत्रण में नहीं है तो वह उस दस्तावेजों की जिन पर निर्भर करने का उसका आशय है, महत्वपूर्ण अन्तर्वस्तुओं का, उस व्यक्ति के, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में ऐसी दस्तावेज हैं, नाम, वर्णन और सही पते का उल्लेख करेगा। किन्तु जहाँ दस्तावेज, शासकीय अभिलेख हैं, वहाँ उस दस्तावेज की विशिष्टियों, उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण रखने वाले विभाग या बैंक या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या व्यक्ति या अधिकारी का उल्लेख किया जाएगा।

(6) जहाँ आवश्यक हो उसके साथ उन साक्षियों की सूची होगी जिनकी परीक्षा, अभिसाक्षी शपथपत्र में किए गए कथनों के समर्थन में करना चाहता है। ऐसी सूची में निम्नलिखित बातें होंगी :

(क) ऐसे प्रत्येक साक्षी की पूरी विशिष्टियाँ और उसका सही पता;

(ख) वे तथ्य जिसके संबंध में प्रत्येक साक्षी से यह आशा की जाती है कि वह अपने परीक्षण में उसे या उन्हें साबित करेगा; और

(ग) वे कारण जिनसे प्रत्येक साक्षी से शपथपत्र प्राप्त करने की बजाए उनकी मौखिक परीक्षा को प्रार्थना की गई है।

- (7) उस पर ऐसे प्राधिकार के समक्ष शपथ ली जाएगी जो शपथ दिलाने के लिए वैध रूप से समक्ष है।
- (8) जहाँ तक संभव हो उसके साथ उसकी पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ हानि चाहिए जो सुपाठ्य हों।
- (9) किसी कम्पनी, निगम, सोसाइटी या ऐसे हूँ: अन्य व्यक्ति की ओर से अभिप्रेत शपथ पत्र की दशा में शपथ पत्र पर कम्पनी, निगम निकाय, सोसाइटी के सचिव या अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा जिसे ऐसी कम्पनी, निगम निकाय, सोसाइटी के निदेशक बोर्ड या प्रबंध निकाय या अन्य व्यक्ति इस निर्मित प्राधिकृत करे।

14. डाक द्वारा भेजे गए या वस्ती दिए गए शपथ पत्र की रसदें:—जब भी कोई शपथ-पत्र डाक से प्राप्त होता है; उसके भेजने वाले को, साथ में भेजे गए पत्र में दिए गए पत्र पर उसकी अभिलिखित डाक से भेजी जाएगी। यदि कोई शपथ पत्र आयोग के कार्यालय में उसे प्राप्त करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को स्वयं दिया जाता है तो उस शपथ पत्र को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को उसकी रसद दी जाएगी।

15. आयोग, साधारणतया, ऐसे किसी व्यक्ति का जिस पर किसी अधिकारित न्यायाचार, अनियमितता या अनुचित पक्षपात के, जो आयोग के समक्ष जांच की विषयवस्तु है, करने या उसमें भाग लेने का अथवा उससे संबंधित किसी कार्य या छोड़ करने में या अन्य रूप में उससे सम्बंध होने या उसमें संसर्ग होने का आरोप है, ऐसे आरोप का उत्तर देने के लिए बुला सकेगा। उत्तर, साधारणतया आयोग के समक्ष मौखिक शपथ के रूप में दिए जाएंगे किन्तु आयोग लिखित रूप में और यदि उचित समझा जाए तो ऐसे व्यक्ति द्वारा शपथपत्र में शपथ लेकर किए गए कथन की अनुज्ञा दे सकेगा।

16. साक्ष्य:—यदि नियम 5(2) के अधीन जारी की गई सूचना के उत्तर में प्राप्त सभी कथनों का परीक्षा करने के पश्चात् आयोग आवश्यक समझता है तो वह कथन दखिल करने वाले किसी व्यक्ति को मौखिक साक्ष्य देने के लिए और अपनी प्रतिपरीक्षा करने के लिए बुला सकेगा और ऐसे व्यक्ति का शपथ-पत्र मुख्य परीक्षा के रूप में माना जाएगा। साक्षी के रूप में कस: अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए शपथपत्र भी मुख्य परीक्षा के रूप में माने जाएंगे।

परन्तु शपथ पत्र के अभिसाक्ष: सहित किसी भी व्यक्ति को मौखिक परीक्षा का अधिकार नहीं होगा।

17. आयोग के समक्ष उपस्थित व्यक्ति का साक्ष्य—आयोग, अपने विवेकानुसार, ऐसे किसी व्यक्ति की जो उसकी किसी बैठक के दौरान बर्षक के रूप में या अन्यथा आयोग के समक्ष उपस्थित है, साक्षी के रूप में परीक्षा कर सकेगा यदि आयोग की राय में ऐसा व्यक्ति उप तथ्यों से अवगत प्रतित होता है जिनका संबंध आयोग के विचारार्थ विषयों के घटना से परिचित प्रतित होता है जिसका आयोग के समक्ष जांच की विषय वस्तु से कुछ संबंध हो सकता है।

18. साक्षी को पुन: बुलाने का अधिकार:—आयोग, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर ऐसे किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा या पुन: बुला सकेगा जिसकी साक्षी के रूप में परीक्षा हो चुकी है या जिसने शपथ-पत्र या तथ्यों का कथन प्रस्तुत किया है और उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो वह उचित समझे और उसका अतिरिक्त कथन अभिलिखित कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसी किसी व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार नहीं होगा जिसे उपर्युक्त शक्ति के अनुसरण में समन किया गया है या पुन: बुलाया गया है किन्तु आयोग कोई स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए उससे प्रश्न करने की अनुज्ञा अपने विवेकानुसार दे सकेगा।

19. अनावश्यक साक्षी को समन करने से इंकार करना:—आयोग को यह अधिकार होगा कि वह किसी मामले में किसी साक्षी की परीक्षा करने

से इंकार कर दे यदि उसकी यह राय है कि उस साक्षी का साक्ष्य असंगत या अनावश्यक है अथवा यदि साक्षी का नाम, विलम्ब करने या तंग करने के प्रयोजन से दिया गया है।

20. मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करने का ढंग:—यदि आयोग नियम 5(2)(क) के अधीन मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करने का विनिश्चय करता है तो पहले वह आयोग के समक्ष जांच की विषय वस्तु के संबंध में केन्द्रिय सरकार का साक्ष्य, यदि कोई हो, और उस विषय वस्तु के संबंध में, अभिकथन का अभियोजन करने वाले अन्य व्यक्तियों का साक्ष्य अभिलिखित करेगा।

21. आयोग को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेकानुसार, किसी व्यक्ति को मौखिक परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के लिए बुलाने से इंकार कर दे और उसकी बजाए उसे दिए गए परिप्रश्नों के माध्यम से शपथपत्र पर उसकी परीक्षा करे।

22. अन्वेषक अधिकार की रिपोर्ट के सबूत का ढंग:—जब आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 5क(1) के अधीन इस निर्मित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किए गए अन्वेषण की रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तब यदि आयोग उचित समझता है तो वह ऐसे अधिकारी या अधिकारियों की परीक्षा कर सकेगा जिसने/जिनोंने अन्वेषण किया है और उसके पश्चात् वह उस रिपोर्ट को उसमें अन्तर्विष्ट तथ्यों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर सकेगा:

परन्तु आयोग, अपने विवेकानुसार, रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के सहो होने के बारे में और यदि अन्वेषक अधिकारी या अभिकरण द्वारा कोई निष्कर्ष निकाले गए है तो उनके बारे में अपना समाधान करने की दृष्टि से ऐसे अन्वेषक अधिकारी या अभिकरण द्वारा इकट्ठा की गई दस्तावेजों, उद्धरणों, प्रतिनिधियों और अन्य सामग्री का और उन व्यक्तियों के कथनों का जिनका ऐसे अन्वेषक अधिकारी या अभिकरण में परीक्षा की है, उस रिपोर्ट को साक्ष्य के तीर पर अन्तिम रूप से ग्रहण करने से पूर्व, परिशीलन कर सकेगा। इस विनियम की कोई बात आयोग को ऐसे किसी व्यक्ति को, जो अन्वेषक अधिकारी या अभिकरण के समक्ष अपना अभिसाक्ष्य दे चुका है या अन्य व्यक्ति को जिसके कष्ट या शक्ति में ऐसी कोई दस्तावेज या अन्य सामग्री है जो आयोग के जांच की विषय-वस्तु से मंगत है या जिसका अभिसाक्ष्य अन्यथा आवश्यक है और आगे परीक्षा के लिए समन करने से प्रवारित नहीं करेगी।

23. ऊपर निर्दिष्ट अन्वेषण की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सामग्री पर विचार करने पर आयोग यह निवेश दे सकेगा कि किसी विशेष मुद्दे या मुद्दों के संबंध में और आगे अन्वेषण ऐसी रीति से किया जाए तां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वह उचित समझता है। तब अन्वेषक अधिकारी या अभिकरण, निवेदानुसार, और आगे अन्वेषण करेगा और अन्वेषण की अतिरिक्त रिपोर्टें ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयाजन के लिए आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाए।

24. साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों का लागू न होना:—यद्यपि साक्ष्य अधिनियम और अन्य विधियों के ऐसे तर्कों की उपबंध जो न्यायालयों को साक्ष्य अभिलिखित करने और उसे ग्रहण करने के लिए समर्थ बनाते हैं, आयोग के समक्ष साक्ष्य के अभिलेखन को या उसकी ग्राह्यता को शासित या परिमित नहीं करेगी तथापि साक्ष्य अधिनियम के मूल उपबंधों में अन्तर्निहित नैतिक न्याय के मूल सिद्धान्तों का, जहाँ तक संभव हो, मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के रूप में पालन किया जाएगा।

25. प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कथन का अभिलिखित किया जाना:—आयोग किसी कथन को स्वयं अभिलिखित करने की बजाय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा, जिसके या जिनके समक्ष ऐसे कथन अभिलिखित किए जा सकेंगे। आयोग कथनों को टेपिकार्ड पर या इसी प्रकार के अन्य उपकरण पर अभिलिखित करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगा।

26. साक्ष्य में मूल दस्तावेजों का ग्रहण किया जाना :—यदि मूल साक्ष्य और पत्र-व्यवहार केन्द्रीय या राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालयों की, जिनके अन्तर्गत सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थान, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, बैंक और गृहकारी सोसाइटियाँ भी हैं, फाइलों में हैं तो आयोग आवश्यक अभिलेखों का निरीक्षण करने और, यथावसि, साक्ष्य/पत्र-व्यवहार आदि की अधिप्रमाणिकता के बारे में अपना समाधान कर लेने के पश्चात् उन्हें, किसी साक्षी के अभिसाक्ष्य या किसी व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा के खर्च या सपोषण के प्रयोजन के लिए उनका उपयोग करने की दृष्टि से, साक्ष्य में ग्रहण कर सकेगा।

27. रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज :—मूल रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज, या रजिस्ट्रीकरण विभाग द्वारा जारी की गई उनका प्रमाणित प्रतियाँ, उनके निष्पादन के विधियत् सभू की अवस्था किए बिना निम्न स्वीकार कर ली जाएंगी।

28. प्रतिपरीक्षा का अधिकार :—उन मामलों में जिनमें मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किया जाता है, आयोग के समक्ष सभी पक्षकारों को और ऐसे व्यक्तियों को जो अधिनियम की धारा 8ख में निर्दिष्ट हैं, साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिया जाएगा।

29. आयोग किसी तथ्य विवादात्मक का मौखिक साक्ष्य के बिना, अपने विवेकानुसार, निपटारा कर सकेगा।

30. सुनवाई का क्रम :—आयोग अपने समक्ष आए गए विषयों की सुनवाई अपने समक्ष विचारणीय विषय के संबंध में किसी विशिष्ट तथ्य से या क्रमानुसार करने के लिए बाध्य नहीं है।

31. आयोग नियम 5(2) के अधीन दी गई सूचना के उत्तर में कथनों के प्राप्त होने पर, उन विचारणीय विषयों पर या तो अलग-अलग अथवा सन्तुष्टि में, जैसा वह उचित समझे, आगे कार्यवाही कर सकेगा।

32. आदेशिकाओं पर हस्ताक्षर करने के अधिकार का प्रणयोजना :—आयोग के सचिव को आयोग के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन जारी किए गए समर्थों और अन्य आदेशिकाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए, नियम 4(2) और नियम 4(6) के अधीन प्राधिकृत किया गया है।

33. आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यक्ति या पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर किसी याचिका, शपथ या अन्य दस्तावेज से किसी बात को हटा या निकाल सकेगा या आयोग को प्रस्तुत की गई किसी ऐसी दस्तावेज को वापस कर सकेगा जो आयोग की राय में असंगत या अनावश्यक रूप से संतापकारी, अवलील या कलंकारमक है।

34. विनियमों का संशोधन या परिवर्तन करने की शक्ति का भारभित होना :—आयोग, जब के दौरान किसी भी समय, जब वह आवश्यक और या उचित समझे, प्रक्रिया के इन विनियमों में से किसी को परिवर्तित करने, उपान्तरित करने, निकालने या उसमें जोड़ने का अपना अधिकार भारभित रखता है। आयोग, ऐसे विषयों पर जो प्रक्रिया के इन विनियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, अधिनियम और नियमों से सुसंगत अनुपूरक निर्देश और विनियम, उनकी आवश्यकता पड़ने पर जारी करेगा।

[सं० 1/3/77—सी०आई०एम०]

आयोग के आदेश से,
जे० एम० नालवाणी, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
COMMISSION OF INQUIRY ON MARUTI AFFAIRS
ORDER

New Delhi, the 19th November, 1977

S.O. 3984.—In exercise of the powers conferred on it by Section 8 of the Commissions Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) and sub-rule (8) of Rule 5 of the Commissions of Inquiry (Central) Rules, 1972 (hereinafter referred to as the Act and the Rules respectively) and all other powers enabling it, the Commission of Inquiry on Maruti Affairs constituted under section 3 of the Act by the Notification of the Government of

India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 375(E) dated the 30th May 1977 read with notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 573(E) dated the 20th July 1977 as further modified by the Ministry of Home Affairs Notification No. 613(L) dated the 11th August 1977 (hereinafter referred to as the Commission) hereby makes the following order to regulate its procedure :

1. Title.—This Order may be called the Commission of Inquiry on Maruti Affairs (Regulation of Procedure) Order, 1977.

2. The proceedings of the Commission shall ordinarily be conducted in the English language. However, the Commission may, in its discretion, during the course of any sitting allow the proceedings to be conducted in Hindi. Petitions and other submissions in writing can be made to the Commission either in Hindi or in English language :

Provided that a petition or an affidavit in a language other than Hindi or English can be entertained by the Commission if it is accompanied by an authenticated translation in Hindi or English.

3. Official address.—Unit further orders, the headquarters of the Commission is at No. 10, Janpath, New Delhi, and all communications should be addressed to the Secretary to the Commission of Inquiry on Maruti Affairs at that address till a change in address is notified.

4. Hours of working.—The office of the Commission shall be open between 10 A.M. and 1.15 P.M. and 2 P.M. and 5.15 P.M. on all days other than holidays and closed days observed by the Central Government. However, the hours during which business may be transacted with the parties and the public shall be between 10-30 A.M. and 4-30 P.M. (excluding the lunch interval from 1.30 P.M. to 2.00 P.M.) on any working day.

5. Right to admission.—Entry to the office premises of the Commission shall be regulated by passes which can be obtained at the Reception office before entry.

6. Place of sittings.—The Commission shall ordinarily hold its sitting at New Delhi at such place or places as it may deem appropriate.

7. Time etc. of sitting to be notified.—The dates, timings and venue of the sittings of the Commission will be notified from time to time.

8. If it is expedient or necessary in public interest to hold any sitting outside New Delhi, due notice will be given in advance in an appropriate manner.

9. Public Hearings.—The hearing of the Commission will be open to the public except when the Commission thinks fit to direct that proceedings in respect of a particular person or persons or any specific subject matter shall be heard in camera :

Provided that when it appears necessary to regulate the entry of visitors to the court room where the Commission intends to hold or is holding public sittings, the Commission may, by a specific order, issue necessary directions. Any person failing to comply with any such direction issued by or under authority of the Commission is liable to be treated as a trespasser :

Provided further that no visitor will be permitted to carry inside the court-room of the Commission any attache or brief-case or a bag of any container or package contents whereof are not visible, or any weapon, instrument or other object or substance of any kind or any equipment which can create or lead to disturbance of any kind or otherwise cause interference in the orderly conduct of the proceedings of the Commission.

10. Law books and other similar publications in open containers will not however be affected by the above restriction.

11. Visitors will not be permitted to take photographs of any person(s) inside the court premises where the Commission holds its sittings.

12. Affidavits from persons acquainted with the subject matter.—The Commission may, at any stage of the proceedings, require persons, who in its opinion, have knowledge of facts relevant to matters under inquiry before the Commission, to file statements of facts or affidavits. An affidavit required

by the Commission to be filed shall be sworn before an authority legally empowered to administer oath.

13. Essential requirements of affidavits.—An affidavit to be filed before the Commission shall satisfy the following conditions :

- (1) it shall preferably be in Hindi or English languages and, if it is in a language other than Hindi or English, it shall be accompanied by a translation thereof in Hindi or English duly authenticated by an Advocate or a Magistrate of the first class;
- (2) it shall be in the first person and divided into paragraphs, to be numbered consecutively, each material statement of fact being made the subject matter of a separate paragraph;
- (3) it shall include therein the correct description, occupation and place of abode of the deponent; and
- (4) it shall be verified in the following manner :

“Verified that —

- (a) the statements made in paragraphs....of this affidavit are true to my own knowledge ;
- (b) the statements made in paragraphs.....of this affidavit are based on the information derived by me from.....which is believed by me to be true ;

Explanation : where such information is based on any information derived :

- (i) from an individual, the name, description, occupation and correct address of such individual, shall be specified in the affidavit ;
 - (ii) from any document or record, the particulars and nature of the document or record, and the name, description and address of the person having the custody or control of such document or record shall be specified in the affidavit ;
 - (iii) from any other source, the source of such information shall be disclosed in the affidavit ;
- (c) the statements made in paragraphs.....of this affidavit are true to my belief;
 - (d) the statements made in paragraphs.....of this affidavit are my submissions to the Commission.
- (5) in case the deponent relies for the whole or any part of his statement in the affidavit on any document, the original document, or a duly attested copy thereof, shall be filed along with the affidavit. In case the original of such document is not in the possession or control of the deponent, he shall indicate the material contents of the documents intended to be relied upon and the name, description and the correct address of the person having custody or control of such document. Where, however, the document is an official record, the particulars of such document, the Department or Bank or public sector undertaking or the person or officer in custody and control thereof shall be indicated ;
 - (6) it shall be accompanied, where necessary, by a list of witnesses whom the deponent wishes to examine in support of the statements made in the affidavit, indicating :
 - (a) the full particulars and correct address of each such witness;
 - (b) the fact or facts which each witness is expected to prove in his examination; and
 - (c) the reasons why, instead of obtaining an affidavit from each witness, his oral examination is prayed for.
 - (7) It shall be sworn before an authority legally empowered to administer oaths;
 - (8) It shall be accompanied, as far as possible, by five legible spare copies thereof;

- (9) In the case of an affidavit purporting to be on behalf of a company, corporation, society or other similar person, the affidavit shall be signed by the Secretary of the company, body corporate, society or other person or by such other individual as the Board of Directors or the Management Body of such company, body corporate, society or other person may authorise in this behalf.

14. Receipts for affidavits sent by post or by hand.—Whenever an affidavit is received by post, an acknowledgement will be sent by post to the sender at the address given in the forwarding letter. If an affidavit is handed in person at the office of the Commission to a person duly authorised to receive the same, the person presenting it shall be given a receipt therefor.

15. The Commission will ordinarily call upon any person charged with committing or participating in the commission or otherwise being concerned in or privy to the commission of any act or omission connected with any of the alleged malpractices, irregularities or undue favours which are the subject matter of inquiry before the Commission, to make his reply to such charge. The reply shall ordinarily be made in a statement viva voce before the Commission. But the Commission may allow statement in writing and, if considered appropriate, sworn by each person in an affidavit.

16. Evidence.—If the Commission considers it necessary, after examination of all statements received in response to the notices issued under Rule 5(2), it may call upon any person filing a statement to give oral evidence and submit himself to cross-examination, his affidavit being treated as examination-in-chief. Affidavits furnished by any other person as a witness will also be treated as examination in chief :

Provided that no person, including a deponent of an affidavit, shall have a right to oral examination.

17. Evidence of person present before the Commission.—The Commission may, in its discretion, examine any person as a witness who is present before the Commission during the course of any sitting either as a visitor or otherwise, if in the opinion of the Commission, such person appears to be conversant with the facts relating to any of the matters covered by the terms of reference of the Commission or acquainted with any transaction or incident which may have some connection with the subject matter of the inquiry before the Commission.

18. Power to summon or recall the witnesses.—The Commission may at any stage of the proceedings summon or recall any person who may have been examined as a witness or may have submitted an affidavit or a statement of facts and may put such questions to him as it may think fit and record his further statement. No person shall have the right to cross-examine such person who may have been summoned or recalled in pursuance of the above power but the Commission may in its discretion allow questions to be put to him for seeking any clarification.

19. Refusal to summon unnecessary witness.—The Commission shall have the right to refuse to examine any witness in any case in which it is of opinion that the evidence of the witness is irrelevant or unnecessary or if he has been cited for the purpose of delay or vexation.

20. Mode of recording oral evidence.—In a case where the Commission decides to record oral evidence under Rule 5(2)(a), it shall first record the evidence by the Central Government, if any, and other persons prosecuting an allegation with regard to the subject matter of inquiry before the Commission.

21. The Commission shall have the right, in its discretion, to refuse to call any person for oral examination or cross-examination and instead, to examine him on affidavit through interrogatories delivered to him.

22. Mode of proof of report of investigating officer.—When the report of the investigation undertaken by the officers authorised in this behalf by the Commission under section 5A(I) of the Act is received, the Commission may, if it so deems proper, examine the officer or officers, who conducted the investigation and thereafter admit the report as evidence of the facts contained therein :

Provided the Commission may, in its discretion, with a view to satisfying itself about the correctness of the facts set forth

in the report and the conclusions, if any, arrived at by the investigating officer or agency, peruse the documents, extracts, copies and other materials collected by the investigating officer or agency and the statements of persons examined by such investigating officer or agency before finally accepting the report as evidence. Nothing in this regulation shall preclude the Commission from summoning any person who may have tendered his testimony before the investigating officer or agency for further examination or any other person who may have in his possession or power any document or other material which may be relevant to the subject matter of inquiry before the Commission or whose testimony may be otherwise necessary.

23. On a consideration of the material contained in the report of investigation referred to above, the Commission may direct that further investigation may be made on any specific point or points and in such a manner as it deems appropriate having regard to the facts and circumstances of the case, and thereupon the investigating officer or agency shall undertake further investigation as directed and submit a further report of investigation in such time as may be allowed by the Commission for this purpose.

24. Provisions of Evidence Act not applicable.—Although the technical provisions of the Evidence Act and other laws enabling Courts of Law to record and admit evidence shall not govern or limit the recording of evidence before the Commission or its admissibility, the fundamental principles of natural justice underlying the primary provisions of the Evidence Act, shall be observed as guide as far as possible.

25. Recording of statement by authorised person.—Instead of the Commission personally recording the statement of witnesses the Commission may appoint a person or persons before whom such submission may be recorded. The Commission may also authorise recording of the statements on a tape-recorder or other similar equipment.

26. Admission or Original documents in evidence.—Where original evidence and correspondence are in the files of Ministries/Departments of the Central or State Governments and their attached/subordinate offices including government controlled institutions, public sector undertakings, banks and co-operative societies, the Commission may, after inspection of the necessary records and satisfying itself about the authenticity of the evidence/correspondence etc., as the case may be, admit the same in evidence with a view to utilising it for the purpose of contradiction or corroboration of the testimony of any witness or cross-examination of any person.

27. Registered documents :—Registered documents, in original, or their certified copies issued by the Registration Department shall, as a rule, be admitted without requiring formal proof of their execution.

28. Right to cross examine :—In cases where oral evidence is recorded, all parties before the Commission and such persons as are referred to in section 8B of the Act, shall be given an opportunity to cross-examine the witness.

29. The Commission may, at its discretion, dispose of any issue or fact on affidavits without any oral evidence.

30. Order of hearing :—It shall not be incumbent on the Commission to take up hearing of matters brought before it in any particular order or adseriatum in relation to its terms of reference.

31. The Commission may on receipt of statements in response to notices under Rule 5(2) proceed with such of the terms of reference, either singly or in groups, as it may deem appropriate.

32. Authority to sign processes delegated :—Secretary to the Commission has been authorised under rules 4(2) and 4(6) to sign summons and any other process issued by or under the authority of the Commission.

33. The Commission may, either on its own motion or on an application made by any person or party, delete or expunge any matter from any petition, affidavit or other documents, or return any document presented to the Commission, which in the opinion of the Commission, is irrelevant or needlessly offensive, scurrilous or scandalous.

34. Powers to amend, alter etc. regulations reserved :—The Commission reserves its right to alter, modify, delete or add to

any of these regulations of procedure at any time during the inquiry as and when it considers necessary and/or appropriate. On matters not covered by these Regulations of Procedure, supplementary directions or regulations consistent with the Act and the Rules will be issued by the Commission as and when need for the same arises.

[No. 1/3/77-CIM]

By order of the Commission

J. M. LALVANI, Secy.

कानून और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1977

क्र. 3985. —दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित प्रवर्धों को उन प्रवर्धों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किया जाता है, अर्थात् :—

(क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 477 के अधीन दंडनीय अपराध; और

(ख) ऊपर खण्ड (क) में वर्णित अपराध या अपराधों, तथा उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न उन्नी संयवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के बारे में या के सम्बन्ध में प्रयत्न, बुद्धि और प्रयत्न।

[संख्या 228/13/77-एवीडी-2]

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 9th December, 1977

S.O. 3985.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, namely :—

(a) Offences punishable under section 447 of the Indian Penal Code (45 of 1860); and

(b) attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, one or more of the offences mentioned in clause (a) above and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/13/77-AVD.II]

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1977

क्र. 3986. —खण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कटक के एडवोकेट श्री जी.एस. बोहिदार को डा. एच. के. मेहता के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के रेगुलर केस सं. 6/73-सी आई यू (ए) की विशेष जज भुवनेश्वर के स्थायालय में अभियोजन कार्यवाई का मंचानन करने के लिए विशेष लोक-अभियोजन नियुक्त करती है।

[सं. 225/38/77-एवीडी-(II)(i)]

New Delhi, the 13th December, 1977

S.O. 3986.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri G. S. Bohidar, Advocate, Cuttack, as a Special Public Prosecutor for conducting the prosecution of the Delhi Special Police Establishment Regular Case No. 6/73-CIU(A) against Dr. H. K. Mehta in the court of the Special Judge, Bhubaneswar.

[No. 225/38/77-AVD(II)(i)]

का० भा० 3987.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा फटक के एडवोकेट श्री जी०एस० बोहिदार को डा० एच० के० महुताव और श्री एस० के० रहमान के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के रेगुलर केस सं० 7/73-सी०आई०यू०(ए) की विशेष जज, भुवनेश्वर के न्यायालय में अभियोजन कार्यवाही का संचालन करने के लिए विशेष लोक-प्रभियोजन नियुक्त करती है।

[सं० 225/38/77-एवीडी-2(ii)]

टी० के० सुब्रामणियन, अवसर सचिव

S.O. 3987.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri G. S. Bohidar, Advocate Cuttuck, as a Special Public Prosecutor for conducting the prosecution of the Delhi Special Police Establishment Regular Case No. 7/73-CIU(A) against Dr. H. K. Mehtab and Shri M. K. Rahman in the court of the Special Judge, Bhubaneswar.

[No. 225/38/77-AVD. (II)(ii)]

T. K. SUBRAMANIAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1977

का० भा० 3988.—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 (1948 का 15) की धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक मंडल की सिफारिश पर, एतद्वारा, उन बाण्डों पर देय ब्याज की दर 8% (छह प्रतिशत) बापिक निर्धारित करती है, जो उक्त निगम द्वारा 23 दिसम्बर, 1977 को जारी किये जायेंगे और 23 दिसम्बर, 1987, को परिपक्व होंगे।

[सं० का० 2(19)-आई०एफ० I/77]

एम० दण्डपाणि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

Banking Division

New Delhi, the 14th December, 1977

S.O. 3988.—In pursuance of sub-section (2) of section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government on the recommendation of the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India, hereby fixes 6 per cent (six per cent) per annum as the rate of interest payable on the bonds to be issued by the said Corporation on the 23rd December, 1977 and maturing on the 23rd December, 1987.

[No. F. 2(19) IF. I/77]

M. DANDAPANI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1977

का० भा० 3989.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 की धारा 3 की उपधारा (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एतद्वारा अकीविड पंचायत समिति, चित्तकापारम वाया अकीविड, पश्चिम गोदावरी (आंध्र प्रदेश) के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री आई० अश्वनुराम राजू को श्री पी०एस० राजगोपाल नायडू के स्थान पर, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) की दिनांक 7 फरवरी, 1974 की अधिसूचना संख्या एफ० 9-4/45/73-बी०ओ० 1-6 के अंतर्गत हुई थी, 8 दिसम्बर, 1977 से प्रारम्भ होकर 7 दिसम्बर, 1980 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिये किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये केनरा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ० 9/28/77-बी०ओ०-1]

New Delhi, the 8th December, 1977

S.O. 3989.—In pursuance of sub-clause (e) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri I. Atchutarama Raju, Ex-Vice President of Akiividu Panchayat Samiti, Chinakapavaram, Via Akiividu, West Godavari (Andhra Pradesh) as a Director of the Canara Bank for a period of three years commencing on the 8th day of December, 1977 and ending with the 7th day of December, 1980 to represent the interests of farmers in the place of Shri P. S. Rajagopal Naidu appointed under the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Banking) No. F. 9-4/49/73-BO. I-6, dated the 7th February, 1974.

[No. F. 9/26/77-BO. I]

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1977

का० भा० 3990.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 की धारा 3 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एतद्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) की दिनांक 15 फरवरी, 1974 की अधिसूचना संख्या एफ० 9-4/49/73-बी०ओ० 1-9 के अन्तर्गत नियुक्त निदेशकों के स्थान पर, उक्त धारा 3 की उपधारा (क) और (च) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये 9 दिसम्बर, 1977 से प्रारम्भ होकर 8 दिसम्बर, 1980 को समाप्त होने वाली 3 वर्ष की अवधि के लिये, सिडिको बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. श्री बी० रत्न सभापति | किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व |
| अध्यक्ष | करने के लिये धारा 3 की |
| द आंध्र प्रदेश को-ऑपरेटिव | उपधारा (क) के अनुसरण में। |
| सेन्ट्रल एग्रीकल्चरल | |
| डिवलपमेंट बैंक लि० | |
| 3-4-447/448, शंकर भवन | |
| बरकतपुरा, हैदराबाद-500027 | |
| (आंध्र प्रदेश) | |
| 2. डा० के० एस० सूर्यनारायण | धारा 3 की उपधारा (च) के |
| प्रोफेसर व कृषि अर्थशास्त्र विभाग | अनुसरण में |
| के अध्यक्ष, | |
| आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी, | |
| हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)। | |

[संख्या एफ० 9/29/77-बी०ओ०-1]

New Delhi, the 9th December, 1977

S.O. 3990.—In pursuance of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints the following persons as Directors of the Syndicate Bank for a period of three years commencing on the 9th day of December, 1977 and ending with the 8th day of December, 1980, in the place of the Directors appointed under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Banking) No. F. 9-4/49/73-BO. I-9, dated the 15th February, 1974, to represent the interests of the persons specified in sub-clauses (e) and (f) of the said clause 3 :—

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Shri B. Ratna Sabhapathy | Representing the |
| Chairman, the Andhra Pradesh | interest of farmers |
| Co-operative Central Agricultural | in pursuance of sub |
| Development Bank Ltd., | clause (e) of clause 3. |
| 3-4-447/448, Sahakara Bhavan, | |
| Backatpura, Hyderabad-500027. | |
| (Andhra Pradesh) | |
| 2. Dr. K.S. Suryanarayana, | In Pursuance of sub- |
| Prof. & Head of the Deptt. of | clause (f) of clause 3. |
| Agricultural Economics. | |
| Andhra Pradesh Agricultural | |
| University, Hyderabad, | |
| (Andhra Pradesh) | |

[No. F. 9/29/77-BO. I]

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1977

New Delhi, the 12th December, 1977

का० प्रा० 3991—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के खण्ड 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एतद्द्वारा दिसम्बर, 1977 के बारहवें दिन से प्रारम्भ होकर दिसम्बर, 1980 के ग्यारहवें दिन को समाप्त होने वाली 3 वर्ष की अवधि के लिये, उक्त खंड 3 के उपखंड (घ), (ङ) और (च) में निविष्ट व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) की दिनांक 7 फरवरी, 1974 की अधिसूचना संख्या एफ० 9-4/497/3 बी० प्रो० 1-10 के अधीन नियुक्त निदेशकों के स्थान पर, यूनियन बैंक आफ इंडिया के निदेशकों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है :—

1. श्री जय भाई यू० पटेल
अध्यक्ष, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट
कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
7 कल्पना समिति,
नवरंगपुरा, अहमदाबाद, (गुजरात)
उक्त बैंक के जमाकर्ताओं
के हितों का प्रतिनिधित्व
करने के लिये खंड 3 के
उपखंड (घ) के अनुसरण में।
2. श्री परमपाल सिंह मान,
उपाध्यक्ष, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव
फ्रूट डिवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड,
29, सेक्टर 9-ए
चण्डीगढ़
कृषकों के हितों का प्रतिनिधित्व
करने के लिए खण्ड 3 के
उपखंड (ङ) के अनुसरण में।
3. श्री राम बाबू आर्य,
निदेशक, आगरा फुटवेयर,
प्राइवेट लिमिटेड, 56/140 नंगला
फकीरचन्द,
आगरा-282001 (उत्तर प्रदेश)
कारिगरों के हितों का प्रतिनिधित्व
करने के लिये खंड 3 के
उपखंड (ङ) के अनुसरण में।
4. श्री एम० एन० अमरसी,
"ग्रीन फील्ड",
ओवल के सामने, 134,
एम० कर्वे मार्ग,
बम्बई-400020 (महाराष्ट्र)
खण्ड 3 के उपखंड (च) के अनु-
सरण में।
5. श्री हबीब मारिकर,
प्रबंध निदेशक,
मारिकर (मोटर्स) लिमिटेड,
त्रिवेंद्रम (केरल)
खण्ड 3 के उपखंड (च) के अनु-
सरण में।
6. डा० जी० गोपाल रेड्डी,
अध्यक्ष, महात्मा गांधी लिफ्ट इरिगेशन,
कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,
डक्कनना गव्हीपल्ली, तालुका हजूरनगर,
जिला नलगोंडा (आंध्र प्रदेश)
खण्ड 3 के उपखंड (च) के
अनुसरण में।
7. श्री बी०एम० शान्तमूर्ति,
चाटई अकाउन्टेन्ट,
मेसर्स शांतिमूर्ति एंड कम्पनी,
चाटई अकाउन्टेन्ट,
एम०एस०बी० स्ट्रट ट्रस्ट बिल्डिंग,
(गोता टाकीज के पीछे)
टैंक बन्द रोड ईस्ट,
बंगलूर-560004 (कर्नाटक)
खण्ड 3 के उपखंड (च) के
अनुसरण में।
8. श्री प्रकाश शर्मा,
प्रोपराइटर, मेसर्स एसोसिएटेड,
टाइल्स एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज,
अशोक भवन, दालबाजार,
ग्वालियर-474001 (मध्य प्रदेश)
खण्ड 3 के उपखंड (च) के
अनुसरण में।

[सं० एफ० 9/30/77-बी०प्रो०-1]

बलदेव सिंह, संयुक्त उच्च

S.O. 3991.—In pursuance of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints the following persons as Directors of the Union Bank of India for a period of three years commencing on the 12th day of December, 1977 and ending with the 11th day of December, 1980, in the place of the Directors appointed under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Banking) No. F. 9-4/49/73-BO, I-10, dated the 7th February, 1974, to represent the interests of the persons specified in sub-clause (d), (e) and (f) of the said clause 3 :—

1. Shri Jashbhai U. Patel, Representing the interests
Chairman, the Ahmedabad of depositors of the said
District Cooperative Bank Bank—in pursuance of sub-
Ltd., 7, Kalpana Society, clause (d) of clause 3.
Navrangpura, Ahmedabad,
(Gujarat).
2. Shri Parmpal Singh Mann, Representing the interests of
Vice-Chairman, the Punjab farmers in pursuance of
State Cooperative Fruit sub-clause (c) of clause 3.
Development Federation
Ltd., 29, Sector 9-A,
Chandigarh.
3. Shri Ram Baboo Arya, Representing the interests
Director, Agra Footwear of artisans in pursuance
Pvt. Ltd., 56/140, Nagla of sub-clause (e) of clause 3.
Faqr Chand, Agra-
282001. (Uttar Pradesh).
4. Shri M.N. Amrsey, In pursuance of sub-clause
'Green Fields', 134, M. (f) of clause 3.
Karve Marg, Opp. Oval,
Bombay-400020. (Maha-
rashtra).
5. Shri Habeeb Marikar, In pursuance of sub-clause
Managing Director, Mari- (f) of clause 3.
kar (Motors) Ltd., Tri-
vandrum. (Kerala).
6. Dr. G. Gopal Reddy, In pursuance of sub-clause
Chairman, Mahatma Gandhi (f) of clause 3.
Lift Irrigation Coop.
Society Ltd. P.O. Gaddi-
palli, Taluq Hazur-Nagar,
Dist. Nalgond (Andhra
Pradesh).
7. Shri B.M. Shanthamurthy, In pursuance of sub-clause
Chartered Accountant, (f) of clause 3.
M/s. Shanthamurthy &
Co., Chartered Account-
tants, S.S.B. Mutt Trust
Building, (Behind Geetha
Talkies) Tank Bund Road
East, Bangalore-560009.
(Karnataka).
8. Shri Prakash Sharma, In pursuance of sub-clause
Proprietor, M/s. Associated (f) of clause 3.
Tiles & Cement Industries,
Ashok Bhavan, Dal Bazar,
Gwalior-474001 (Madhya
Pradesh).

[No. F. 9/30/77 O.I]

BALDEV SINGH, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक
(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)
(केन्द्रीय कार्यालय)

बम्बई, 24 नवम्बर, 1977

क्र.सं. 3992.—रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 73 की उपधारा (3) के अनुसरण में तथा दिनांक 7 अक्टूबर, 1972 की अधिसूचना सं. एफ.ई.आर.ए. 256/72-आरबी का अतिक्रमण करने हुए—

(क) किसी भी व्यक्ति को किसी धर्मादा ट्रस्ट या शैक्षणिक संस्था या प्रतिष्ठान या किसी विदेशी सरकार से छात्रवृत्ति या वृत्तिका के रूप में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की अनुमति देता है ताकि वह किसी अध्ययन का पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण या दोनों ही पूरा कर सके।

यह अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि जो व्यक्ति उपर्युक्त प्रकार से विदेशी मुद्रा प्राप्त करता हो और रिजर्व बैंक द्वारा जिसे या जिसके लाभ के लिए इस उद्देश्य से विदेशी मुद्रा मंजूर की गयी हो कि वह भारत के बाहर होने वाले अपने व्यय के किसी भ्रंश की पूर्ति कर सके या जिसने ऐसी मंजूरी के लिए आवेदन किया हो या आवेदन करने का हवाला रखता हो उसे इस प्रकार प्राप्त की गयी विदेशी मुद्रा के विवरण देते हुए उसके प्राप्त किये जाने से तीस दिन के भीतर रिजर्व बैंक को सूचना देनी चाहिए ;

(ख) किसी भी व्यक्ति को भारत के बाहर धारित प्राप्तियों पर आय के रूप में या उत्तराधिकार, निपटारा या दान के रूप में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की अनुमति देता है ;

(ग) किसी व्यक्ति को भारत में न रहने वाले किसी व्यक्ति से भारत में या भारत के बाहर प्रदान की गयी सेवाओं के लिए या किसी वैध देयता के शोधन में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की अनुमति देता है ;

यह अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि जो व्यक्ति धारा (ख) या धारा (ग) में उल्लिखित प्रकार से विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है, यदि वह भारतीय नागरिक है और वह भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है तो वह विदेशी मुद्रा के प्राप्त होने से सात दिन के भीतर और किसी अन्य मामले में उसके प्राप्त होने से तीस दिन के भीतर दिनांक 15 जून, 1977 को केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 839 (एफ.ई.सी/73) में निर्धारित प्रकार से बिक्री के लिए प्रस्तुत करेगा या करवायेगा।

यह अनुमति आगे इस शर्त पर दी जाती है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति के मामले में उसके द्वारा भारत के बाहर प्रदान की गयी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में अर्जित विदेशी मुद्रा अधिकृत व्यापारी की बिक्री के लिए प्रस्तुत करने या करवाने की बाध्यता उस पर तब तक नहीं आयेंगी जब तक वह भारत के बाहर का निवासी नहीं रह जाता और यह शर्त केवल ऐसी विदेशी मुद्रा की राशि पर लागू होगी जो उसके भारत के बाहर का निवासी न रहने पर उसके स्वामित्व में हो।

यह अनुमति इस शर्त पर भी दी जाती है कि जब ऐसी कोई विदेशी मुद्रा भारत में लायी जाए या भेजी जाए तब, यथास्थिति, उसे लाने वाला या प्राप्त करने वाला प्राधिकृत व्यापारी, यथास्थिति, उसे लाने या प्राप्त करने की तारीख से सात दिन समाप्त होने से पहले दिनांक 15 जून, 1977 को केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 839

(एफ.ई.सी/73) के अनुसरण में प्राधिकृत व्यक्ति को बिक्री के लिए प्रस्तुत करेगा या करवायेगा।

[सं. एफ.ई.आर.ए. 47/77-आर.बी.]

RESERVE BANK OF INDIA
(Exchange Control Department)
(Central Office)

Bombay, the 24th November, 1977

S.O. 3992.—In pursuance of sub-section (1) of Section 8 and sub-section (3) of Section 73 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) and in supersession of the Notification No. FERA. 256/72-RB. dated 7th October, 1972, the Reserve Bank is pleased—

(a) to permit any person to acquire foreign exchange by way of scholarship or stipend from a charitable trust or educational institution or foundation or from a foreign government to enable him either to undergo a course of studies or training or both ;

Provided that a person who acquires foreign exchange as aforesaid and to whom or for whose benefit foreign exchange has been sanctioned by the Reserve Bank for meeting any part of his expenses outside India or who has applied or intends to apply for such sanction, shall make a report to the Reserve Bank, giving details of the foreign exchange so acquired, within thirty days of acquisition ;

(b) to permit any person to acquire foreign exchange by way of income on assets held outside India or by way of inheritance, settlement or gift ;

(c) to permit any person to acquire from any person not in India, foreign exchange by way of remuneration for services rendered whether in or outside India, or in settlement of any lawful obligation ;

Provided that a person who acquires foreign exchange as in clause (b) or in clause (c) shall, if he is an Indian citizen and receives foreign exchange in India, within seven days from its receipt, and, in any other case, within thirty days from its receipt, offer it or cause it to be offered for sale to the person, and in the manner laid down in the Central Government's Notification No. GSR 839 (F. 1/3/EC/73) dated 15th June, 1977 ;

Provided further that in the case of a person resident outside India, the obligation to offer or cause to be offered for sale to an authorised dealer foreign exchange earned by such person by way of remuneration for services rendered outside India, shall not arise until such person ceases to be resident outside India and shall extend only to the amount of such foreign exchange owned by him when he ceases to be resident outside India ;

Provided also that when any such foreign exchange is brought or sent into India, the person bringing in or, as the case may be, receiving it, shall, before the expiry of seven days from the date on which it is brought or, as the case may be, received, offer it for sale or cause the same to be offered for sale to any authorised dealer, and in the manner, laid down in the Central Government's Notification No. GSR 839 (F. 1/3/EC/73) dated 15th June, 1977.

[No. FERA 47/77-RB]

क्र.सं. 3993.—रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में और दिनांक 7 अक्टूबर, 1972 की अधिसूचना सं. एफ.ई.आर.ए. 257-72-आरबी का अतिक्रमण करते हुए, किसी भी व्यक्ति को भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति के आदेश पर या उसकी ओर से कोई भी ऐसी अवस्थिति प्राप्त करने की अनुमति देता है—

(क) जो उक्त व्यक्ति द्वारा भारत में उसके ठहरने की अवधि के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी को विदेशी मुद्रा की बिक्री से प्राप्त रुपया निधियों में से रुपये में की गयी हो ;

(ख) जो भारत के बाहर स्थित किसी बैंक पर द्वारा जारी पोस्टल ऑर्डर या ऐसे बैंक पर द्वारा जारी पोस्टल मनी ऑर्डर के रूप में की गई हो;

(ग) जो भारत के बाहर स्थित बैंक के नाम अतिरिक्त चेकों या भारत के बाहर जारी बैंक ड्राफ्ट या यात्री चेकों के रूप में की गई हो,

(घ) जो भारत के बाहर से सीधे ही उसके द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा नोटों में की गई हो:

परन्तु उक्त अद्ययगी इस शर्त के अधीन की जायेगी कि दिनांक 15 जून, 1977 को केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना सं० जी०एस०आर० 839 (एफ०1/3/ईसी/73) के अनुसरण में इस प्रकार प्राप्त विदेशी मुद्रा उसकी प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाए या कराई जाए।

[सं० एफ०ई०आर०ए० 48/77-आर०बी०]

के० एस० कृष्णस्वामी, उप गवर्नर

S.O. 3993.—In pursuance of clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) and in supersession of the Notification No. F.E.R.A. 257/72-R.B. dated 7th October, 1972, the Reserve Bank is pleased to permit any person to receive any payment by order or on behalf of a person resident outside India—

(a) made in rupees during such person's stay in India, out of the rupee funds provided by sale by such person, of foreign exchange to an authorised dealer in India;

(b) by means of postal order issued by a post office outside India or by a postal money order issued by such post office;

(c) by means of cheques drawn on banks situated outside India or bank drafts or traveller's cheques issued outside India;

(d) in foreign currency notes received by him directly from out of India,

subject to the condition that any foreign exchange received shall, within seven days of receipt of the same, be offered for sale or caused to be offered for sale in accordance with the Central Government's Notification No. GSR 839 (F. 1/3/EC/73) dated 15th June, 1977.

[No. F.E.R.A. 48/77-R.B.]

K. S. KRISHNASWAMY, Dy. Governor.

(राजस्व और बैंकिंग विभाग)

(राजस्व पक्ष)

नई दिल्ली, 13 जून, 1977

आय-कर

का०आ० 3994.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "वर्ष प्राफ नार्थ इंडिया, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1974-75 और 1975-76 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 1817/का०सं० 197/191/76-अ०क०(ए०1)]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

(Department of Revenue and Banking)

(Revenue Wing)

New Delhi, the 13th June, 1977

INCOME-TAX

S.O. 3994.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act,

1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Church of North India, New Delhi" for the purpose of the said section for the assessment years 1974-75 and 1975-76.

[No. 1817/F. No. 197/191/76-IT(AI)]

M. SHASTRI, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1977

का०आ० 3995.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) (ii) के अधीन तमिलनाडु आई रिलीफ एसोसिएशन, मदुराई को अधिसूचना सं० 237 (का०सं० 203/44/77-आई०टी०ए०II) तारीख 11 दिसम्बर, 1972 द्वारा, 11 दिसम्बर, 1972 से दिया गया अनुमोदन विहित प्राधिकारी, अर्थात्, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की सिफारिश पर 10 जून, 1977 से वापस लिया जाता है।

[सं० 1872/का०सं० 203/84/77-आई टी ए II]

New Delhi, the 15th July, 1977

S.O. 3995.—It is hereby notified for general information that the approval given under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 to the Tamil Nadu Eye Relief Association, Madurai, by notification No. 237 (F. No. 203/44/72-ITA. II) dated 11th December, 1972 with effect from 11th December, 1972 is withdrawn with effect from 10th June, 1977 on the recommendation of the prescribed authority, the Indian Council of Medical Research, New Delhi.

[No. 1872/F. No. 203/84/77-ITA.II]

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1977

का०आ० 3996.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए, सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली से अनुमोदित किया है।

- | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का नाम : | अंतर्वहन हजिनों के आंशिक स्थानापन्न ईंधन के रूप में मेथमाल |
| 2. प्रायोजक : | गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कम्पनी लिमिटेड, फर्टीलाइजर नगर, जिला, बड़ोदा |
| 3. कर्ता : | पेट्रोलिएम संस्थान, देहरादून |
| 4. प्रारंभ की प्रस्तावित तारीख : | अक्टूबर, 1977 |
| 5. पूर्ण होने की अनुमानित तारीख : | अप्रैल, 1979 |
| 6. अनुमानित व्यय : | 1,95,000 रु० |

पेट्रोलिएम संस्थान, देहरादून सी०एस०आई०आर० का एक एकक है जिसे भूतपूर्व वित्त विभाग की अधिसूचना सं० 34 तारीख 23 नवम्बर, 1946 द्वारा आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 10(2)(iii) के अधीन अनुमोदित किया गया है।

[सं० 1950/(का०सं० 203/115/77 आई टी ए II)]

New Delhi, the 3rd September, 1977

S.O. 3996.—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved

for the period specified below for the purposes of sub-section (2A) of section 35 of the Income-tax Act, 1961, by the Secretary, the Department of Science & Technology, New Delhi.

1. Name of the Scientific Research Programme: Methanol as a part substitute Fuel for Internal Combustion Engines.
2. Sponsored by: Gujarat State Fertilizers Co. Ltd., Fertiliser Nagar, Distt. Baroda.
3. To be undertaken by: Institute of Petroleum, Dehradun.
4. Proposed date of commencement: October, 1977.
5. Anticipated date of completion: April, 1979.
6. Estimated Expenditure: Rs. 1.95.000.

The Institute of Petroleum, Dehradun is a Unit of C.S.I.R., which has been approved u/s. 10(2)(xiii) of the Income-tax Act, 1922, vide late Finance Department Notification No. 34 dated the 23rd November, 1946.

[No. 1956/F. No. 203/115/77-ITA. II]

नई दिल्ली, 20 सितम्बर 1977

का०प्रा० 3997.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में आने वाली संस्थाओं के वर्ग में निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

- (1) यह कि उक्त बोमैन पार्लेटेक्निक एंड रिसर्च सेंटर आफ बोमैन एजुकेशन सोसाइटी, नागपुर, प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान (कृषि/पशुपालन/मत्स्यपालन एवं औषधि से भिन्न) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का हिसाब पृथक् से रखेगा।
- (2) उक्त विश्वविद्यालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी क्रिया कलापों की एक वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं।

संस्था

महिला शिक्षा संगठन, नागपुर द्वारा संचालित बोमैन पार्लेटेक्निक एंड रिसर्च सेंटर, नागपुर।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1977 से 31 अगस्त, 1980 तक प्रभावी होगी।

[सं० 1976/का० सं० 203/125/77-आईटी ए II]

जे० पी० शर्मा, उप सचिव

New Delhi, the 20th September, 1977

S.O. 3997.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, the Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" in the area of other natural or applied sciences, subject to the following conditions:—

- (i) that the Women's Polytechnic and Research Centre of Women's Education Society, Nagpur will maintain a

separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural or applied science (other than Agriculture/Animal Husbandry/Fisheries and Medicines).

- (ii) That the said Centre will furnish the Annual Return of its Scientific Research activities to the prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30th April, each year.

INSTITUTION

Women's Polytechnic and Research Centre run by Women's Education Society, Nagpur.

This notification takes effect from 1st September, 1977 to 31st August, 1980.

[No. 1976/F. No. 203/125/77-ITA. II]

J. P. SHARMA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 1977

आय-कर एवं धनकर

का०प्रा० 3998.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 45) की धारा 80D की उपधारा (1) के खण्ड (ii) और धारा 193 के परन्तु के खंड (ii) और धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (XXIV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त खण्डों के प्रयोजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में माधनों की वृद्धि के लिए, किन्हीं स्कीमों के अनुसरण में राज्य विप्लव बोर्डों, कृषि उद्योग निगमों, आवास बोर्डों (ग्रामीण आवासन के लिए) सरकारी प्रसंस्करण और विपणन समितियों और राज्य द्वारा प्रायोजित अन्य अनुमोदित संस्थाओं द्वारा 1 जनवरी, 1977 और 31 दिसम्बर, 1981 के बीच पुरोधत डिबेंचर बिनडिस्ट करती है:

परन्तु यह कि ऐसे डिबेंचर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, अर्थात्:—

- (1) मूल धन के प्रतिगंदाय या व्याज के भंडार के लिए उन्हें सरकार द्वारा प्रत्याभूत नहीं किया गया हो;
- (2) वे व्यक्तियों को हों, जिसके अन्तर्गत दो या अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं परोधत किए गए हों;
- (3) वे इस शर्त के अधीन पुरोधत किए गए हों कि वे खंड (ii) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं किए जाएंगे;
- (4) उन पर व्याज प्रति वर्ष 12 प्रतिशत से अनधिक होगा।

[सं० 2006 का० सं० 178/31/76-आईटी(ए-I)]

ओ०बी० कुर्विला, अपर सचिव

New Delhi, the 10th October, 1977

INCOME-TAX & WEALTH-TAX

S.O. 3998.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of Sub-section (1) of Section 80L, and Clause (iib) of the proviso to Section 193 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and clause (XXIV) of Sub-Section (1) of Section 5 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby specifies the debentures issued by the State Electricity Boards, the Agro Industries Corporations, Housing Boards (for rural housing); Cooperative Processing and Marketing Societies and other approved State sponsored institutions between 1st January, 1977 and 31st December, 1981, in pursuance of any scheme for raising resources in rural areas, for the purpose of the said clauses:

Provided that such debentures satisfy the following conditions, namely:—

- (i) they are not guaranteed by any Government as to the repayment of the principal or payment of interest;

- (ii) they are issued only to individuals including two or more individuals jointly;
- (iii) they are issued subject to the condition that they cannot be transferred to any person other than mentioned in clause (ii);
- (iv) they carry interest at a rate not exceeding 12 per cent per annum.

[No. 2006/F. No. 178/31/76-IT(AI)]

O. V. KURUVILLA, Additional Secy.

आदेश

स्टाम्प

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1977

का०प्रा० 3999.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो हरियाणा वित्तीय निगम द्वारा प्रोमिसरी नोटों के रूप में जारी किए जाने वाले एक करोड़ दस लाख रुपये मूल्य के बन्ध-पत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभावी है।

[सं० 39/77-स्टाम्प—फा०सं० 33/80/77-बि०कर]

ORDER

STAMPS

New Delhi, the 9th December, 1977

S.O. 3999.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes to the value of one crore and ten lakhs of rupees to be issued by Haryana Financial Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 39/77-Stamp—F. No. 33/80/77-ST]

का०प्रा० 4000.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को उक्त निगम द्वारा प्रोमिसरी नोटों के रूप में जारी किये जाने वाले तीन करोड़ पचासी लाख रुपये अधिक मूल्य के बन्ध-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क के मुद्दे प्रभावी केवल दो लाख सट्ठासी हजार सात सौ पचास रुपये का समेकित स्टाम्प शुल्क संघाय करने की अनुज्ञा देती है।

[सं० 40/77-स्टाम्प-फा०सं० 33/81/77-बि०कर]

एस० डी० रामस्वामी, अव्वर सचिव

S.O. 4000.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) the Central Government hereby permits the Maharashtra Industrial Development Corporation to pay consolidated stamp duty of two lakhs, eighty-eight thousand, seven hundred fifty rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of promissory notes of the face value of three crores eighty five lakhs of rupees to be issued by the said Corporation.

[No. 40/77-Stamp—F. No. 33/81/77-ST]

S. D. RAMASWAMY, Under Secy.

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1977

का०प्रा० 4001.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) (दसवां संशोधन) नियम, 1977 है।

- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में उपाबद्ध प्रकरण 14 में, मद 5 के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“5क. यदि आवेदनकर्ता विधवा/विधुर है, तो सेवा पेंशन की राशि जो वह पति/पत्नी की मृत्यु की तारीख को प्राप्त कर रहा है”।

[संख्या फा० 13(30)-संस्था V(क)/77]

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 9th December, 1977

S.O. 4001.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) (Tenth Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Form 14 appended to the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, after item 5, the following item shall be inserted, namely:—

“5A. If the applicant is a widow/widower the amount of service pension which she/he may be in receipt on the date of death of the husband/wife”.

[No. F. 13(30)-EV(A)/77]

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1977

का०प्रा० 4002.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभागों में सेवारत व्यक्तियों की बाबत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 32 में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(3) उप नियम (1) और (2) के अधीन किए गए स्थापन अन्तिम माने जाएंगे और इस पर पुनः विचार तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि आगे चलकर ऐसी शर्तों को नियमित करने वाले किसी नियमों या आदेशों के निकाले जाने से ऐसा करना आवश्यक न हो जाए, जिनके अधीन सेवा पेंशन के लिए अहित होता है।”

3. उक्त नियमों से उपाबद्ध प्रकरण 23 में, “यह स्थापन अंशक सेवा के अन्तिम स्थापन के अध्वधीन है जो सरकारी मेथक की सेवानिवृत्ति के समय किया जाएगा,” शब्दों के स्थान पर “उप-नियम (1) और (2) के अधीन किए गए स्थापन अन्तिम माने जाएंगे और इस पर पुनः विचार तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि आगे चलकर ऐसी शर्तों को नियमित करने वाले किसी नियमों या आदेशों के निकाले जाने से ऐसा करना आवश्यक न हो जाए, जिसके अधीन सेवा पेंशन के लिए अहित होती है।” शब्द अंक और कांठक रखे जाएंगे।

[संख्या 1(2)-संस्था V(क)/77]

एस० एस० एल० महाजा, अव्वर सचिव

New Delhi, the 12th December, 1977

S.O. 4002.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) (Eleventh Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, (hereinafter referred to as the said rules) in rule 32, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(3) The verification done under sub-rules (1) and (2) shall be treated as final and shall not be reopened except when necessitated by the subsequent change in the rules and orders governing the conditions under which the service qualifies for pension.”

3. In Form 24 appended to the said rules, for the words “This verification is subject to final verification of qualifying service which shall be made at the time of the retirement of the Government servant”, the words, brackets and figures “The verification done under sub-rules (1) and (2) shall be treated as final and shall not be reopened except when necessitated by a subsequent change in the rules and orders governing the conditions under which the service qualifies for pension” shall be substituted.

[No. 4(2)-EV(A)/77]

S. S. L. MALHOTRA, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1977

आय-कर

क्रा०आ० 4003.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 679 (फा० सं० 187/2/74 आई० टी० (ए 1) तारीख 20 जुलाई, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

कम सं० 21, 21क और 21ख के सामने स्तंभ (1), (2) और (3) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी :

आय-कर आयकृत	मुख्यालय	प्रधिकारिता
(1)	(2)	(3)
21 तमिलनाडु-1	मद्रास	1. नगर सिकल 1, मद्रास 2. नगर सिकल-3, मद्रास 3. नगर सिकल-5, मद्रास 4. कम्पनी सिकल-1, मद्रास 5. हुण्डी सिकल 1, मद्रास 6. विशेष भन्वेषण सिकल-1, मद्रास 7. विशेष सर्वेक्षण सिकल, मद्रास, 1
21क—तमिलनाडु-II	मद्रास	1. संपदा-शुल्क-एवं-आयकर सिकल, मद्रास

(1) (2)

(3)

2. संपदा-शुल्क-एवं-आयकर सिकल, थंजवूर

3. संपदा-शुल्क-एवं-आयकर सिकल, मधुरई

4. संपदा-शुल्क-एवं-आयकर सिकल, कोयम्बटूर

5. नगर सिकल-II, मद्रास

6. कम्पनी सिकल-II, मद्रास

7. वेल्पोर सिकल

8. कृष्ण गिरि सिकल

9. कम्पनी सिकल, मलेम

10. सिकल I, मलेम

11. सिकल II, मलेम

21ख—तमिलनाडु-III मद्रास

1. विशेष भन्वेषण सिकल-II, मद्रास

2. नगर सिकल-7, मद्रास

3. विदेश-भन्तुभाग, मद्रास

4. ताम्बरम सिकल

5. कार्थीपुरम सिकल

6. कुम्भाकोणम सिकल

7. थंजवूर सिकल

8. नागापट्टिनम सिकल

9. कम्पनी सिकल, त्रिविरापल्ली

10. नगर सिकल I, त्रिविरापल्ली

11. नगर सिकल-II, त्रिविरापल्ली

12. कारूर सिकल

13. पुडुकोट्टई सिकल

यह अधिसूचना 1-9-1977 से प्रभावी होगी ।

[सं० 1947/फा०सं० 188/6/77-आई टी (ए-1)]

एम० शास्त्री, प्रवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 1st September, 1977

INCOME TAX

S.O. 4003.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the schedule appended to its Notification No. 679 (F. No. 181/2/74-JT(A1) dated 20th July, 1974 as amended from time to time.

Existing entries under columns (1), (2) and (3) against Sl. Nos. 21, 21A and 21B shall be substituted by the following entries :

Commissioner of Income Tax	Headquarters	Jurisdiction	(1)	(2)	(3)
	(1)	(2)	(3)		
21 Tamil Nadu-I	Madras	1. City Circle-I, Madras. 2. City Circle-III, Madras. 3. City Circle-V, Madras. 4. Companies Circle-I, Madras. 5. Hindi Circle-I, Madras. 6. Special Investigation Circle-I, Madras. 7. Special Survey Circle, Madras.			11. City Circle-II, Tiruchirapalli. 12. Karur Circle. 13. Pudukottai Circle.
			2. This Notification shall take effect from 1-9-1977. [No. 1947/F. No. 188/6/77-IT(AI)] M. SHASTRI, Under Secy.		
			नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1977 आय-कर		
21A Tamil Nadu-II	Madras	1. Estate Duty-cum-Income tax Circle, Madras. 2. Estate Duty-cum-Income tax Circle, Thanjavur. 3. Estate Duty-cum-Income tax Circle, Madurai. 4. Estate Duty-cum-Income tax Circle, Coimbatore. 5. City Circle-II, Madras. 6. Companies Circle-II, Madras. 7. Vellore Circle. 8. Krishnagiri Circle. 9. Company Circle, Salem. 10. Circle-I, Salem. 11. Circle-II, Salem.			का० प्रा० 4004.—सर्वसाधारण कं. जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मात्र इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परामर्श के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35घ की उपधारा (2) के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया है। संस्था इंटर कंसल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता यह अनुमोदन 1 अप्रैल, 1977 से प्रभावी होगा। [सं० 1994/का० सं० 203/173/76-आई टी ए II] जे० पी० शर्मा, सचिव
			New Delhi, the 24th September, 1977 INCOME-TAX S.O. 4004.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Central Board of Direct Taxes for the purposes of clause (a) of sub-section (2) of Section 35D of the Income-tax Act, 1961, in the fields of Engineering and Technological consultancy. INSTITUTION INTER CONSULT INDIA PRIVATE LTD., CALCUTTA. The approval takes effect from 1st April, 1977. [No. 1994/F. No. 203/173/76-ITA. II] J. P. SHARMA, Secy.		
21B Tamil Nadu-III	Madras	1. Special Investigation Circle-II, Madras. 2. City Circle-VII, Madras. 3. Foreign Section, Madras. 4. Tambaram Circle. 5. Kancheepuram Circle. 6. Kumbakonam Circle. 7. Thanjavur Circle. 8. Nagapattinam Circle. 9. Company Circle, Tiruchirapalli. 10. City Circle-I, Tiruchirapalli			

(समाहृतलय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,)

मद्रुरै, 23 सितम्बर, 1977

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का० प्रा० 4005—1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इस अधिसूचना द्वारा संलग्न सारणी के स्तम्भ 4 में बताए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहृतलय, मद्रुरै में तैनात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को, अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कथित सारणी के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट नियमों और स्तम्भ 5 में उपबर्णित सीमाओं और शर्तों के अधीन अप्राधिकृत शक्ति जालित करणों पर तैयार किए गए सूची कपड़ों की बाबत विशेष कार्यविधि से संबंधित समाहृता की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार प्रदान करता हूँ। इस संबंध में पहले प्रत्यायोजित की गई शक्तियां उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाएं।

1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के अधीन विद्युत शक्ति शामिल अप्राधिकृत कर्यों पर बनाए गए सूची कपड़ों के बावत विशेष कार्यविधि से संबंधित, समाहर्ता की शक्तियों का प्रत्यायोजन दिखाने वाली सारणी

क्रम सं०	समाहर्ता को प्रदान शक्तियों का स्वरूप	नियम सं०	उस अधिकारी का पद जिसे शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं	सीमाएं यदि कोई हों	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6
अप्राधिकृत शक्ति चाबित कर्यों पर बनाए गए सूची कपड़े					
1.	विशेष कार्यविधि के अन्तर्गत कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रथम वि०का०आ० स्वीकार करना।	96-1(1)	सहायक समाहर्ता	—	—
2.	क्रमिक रूप से 12 कैबिण्ट मशीनें की अवधि के लिए प्रथम वि०का०आ० स्वीकार करना।	96-2	सहायक समाहर्ता	(इससे कम अवधि के लिए वि०का०आ० स्वीकार करने के सम्बन्ध में केवल समाहर्ता ही प्राधिकृत होंगे।)	
3.	उन अभिनिर्माताओं को, जो उस अवधि के दौरान विशेष कार्यविधि से लाभ उठाने में असफल रहे हैं, जिसके लिए उन्हें उक्त प्रणाली से लाभ उठाने की अनुमति दी गई है, विशेष कार्यविधि के अन्तर्गत काम करने से रोकने की अवधि निश्चित करना।	96-1(3)	सहायक समाहर्ता कें० उ० शुल्क	—	—
4.	(क) वि०का०आ० प्रपत्र में तबीकरण आवेदन पत्र स्वीकार करना।	96-1(4)	अधीक्षक कें० उ० शुल्क	यदि 15 दिन से अधिक देर नहीं हुई है तो उसे दरगुजर करना।	
	(ख) ऐसे निर्माताओं को जो तबीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, विशेष प्रणाली के अंतर्गत काम करने से रोकने की अवधि निश्चित करना और/या उनकी गलती दरगुजर करना।	96-1(4)	यथोपरि सहायक समाहर्ता कें० उ० शु०	यदि 15 दिन से अधिक देर हुई है तो दरगुजर करना।	
5.	निमाही/वार्षिक रूप से धनराशि न जमा करने को या शुल्क वस्तुओं के सम्बन्ध में ए-आर-6 प्रपत्र में तबीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में हुई देर को, दर गुजर करना।	96-के(2)	अधीक्षक कें० उ० शु०	तैमामिक रूप से धनराशि जारी करने और निमाही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में अधिक से अधिक 2 दिन एवं वार्षिक रूप से धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में अधिक से अधिक 10 दिन की देर नहीं हुई है तो इस देरी को दरगुजर करना।	
			सहायक समाहर्ता	ऊपर बतायी गई अवधि से अधिक देरी हुई है तो उसे दरगुजर करना।	
6.	ऐसी कारखानों को, जो बन्द हो गए थे किन्तु अब पुनः निर्माण करना शुरू कर दिया है, विशेष कार्यविधि से लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करना।	96-एम एम	सहायक समाहर्ता कें० उ० शु०	6. ऐसी कारखानों को, जो बन्द हो गए थे	

[अधिसूचना सं० 3/77/सी सं० V/19/30/13/77-के० उ०-2]

एम० एम० सुब्रह्मण्यम, समाहर्ता

(The Madurai Central Excise Collectorate)

Madurai, the 23rd September, 1977

CENTRAL EXCISES

S.O. 4005.—In exercise of the powers conferred on me by Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby empower the

Central Excise Officers of the Madurai Central Excise Collectorate mentioned in Column 4 of the Schedule attached to exercise within their respective jurisdiction, the powers of the Collector under the Rules specified in Column 3 of the said Schedule, relating to the special procedure in respect of Cotton fabrics produced on unauthorised powerlooms, subject to the conditions and limitations set out in Column 5 thereof. Powers already delegated may be treated as modified to this extent.

Schedule showing the delegation of Collector's powers under the Central Excise Rules 1944 relating to the special procedures in respect of Cotton fabrics produced on Unauthorised Powerlooms.

S. No.	Nature of powers conferred on Collector	Rule No.	Rank of officers to whom powers are delegated	Limitations if any	Remarks
1	2	3	4	5	6
Cotton Fabrics produced on unauthorised Powerlooms					
1.	To accept first ASP for grant of permission to work under the Special Procedure.	96I(1)	Assistant Collector	—	—
2.	To accept 1st ASP for a period of 12 consecutive calendar months.	96I(2)	Assistant Collector	(For shorter period Collector will be the appropriate authority)	—
3.	To determine the period for which a manufacturer may be precluded from working under the Special Procedure for failure to avail of such procedure during the period for which permission has been granted to him.	96I(3)	Assistant Collector of Central Excise.	—	—
4.	(a) To accept renewal application in form A.S.P.	96I(4)	Superintendent of Central Excise.	—	—
	(b) To condone and/or to determine the period for preclusion from working under the Special Procedure in respect of a manufacturer who fails to make an application for renewal.	96I(4)	-do-	(For condoning delays not exceeding 15 days).	—
			Assistant Collector of Central Excise	For condoning delays exceeding 15 days.	—
5.	To condone failure to make application for renewal of excisable goods in form AR6 or to make Quarterly annual deposits.	96K(2)	Superintendent of Central Excise.	For condoning delays not exceeding 2 days in case of Quarterly application and quarterly deposits and delays not exceeding 10 days in the case of annual applications and annual deposits.	—
			Asst. Collr.	For Condoning delays exceeding the above limits.	—
6.	To grant permission to avail special procedure for closed factories resuming production.	96MM	Assistant Collector of Central Excise.	—	—

[Notification No. 3/77/C. No. V/19/30/13/77-CX.2]
M. S. SUBRAMANYAM, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर 1977

कां.प्र. 4006.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए लघु अभियांत्रिक वस्तुओं के निरीक्षण से संबंधित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या कां.प्र. 895, तारीख 21 फरवरी, 1976 124 GI/77—3

में संशोधन के लिए कथित प्रस्ताव, निर्यात (कवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या कां.प्र. 1555, तारीख 28 मई, 1977 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, भाग-2 खंड-3, उपखंड-(ii), तारीख 28 मई, 1977 में प्रकाशित किए गए थे जिनमें उन सभी लोगों से, जिनके इस आदेश से प्रभावित होने की संभावना है। आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से कम से कम पैंतालीस दिन के भीतर आक्षेप एवं सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 31 मई, 1977 को उपलब्ध करा दी गई थीं, और जनता से प्राप्त आशंको तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अतः अब, नियमित (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नियमित निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 895, तारीख 21 फरवरी, 1976 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त आदेश में, उपबंध-II में, शीर्षक 'II इस्पाती समान' के अंतर्गत उप शीर्षक '2 बाड़ के लिए गाल्वनीकृत इस्पात की काटेदार तार के लिए विनिर्देश के अंतर्गत'—

(1) पैरा 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

'1 काटेदार तार अच्छी व्यापारिक क्वालिटी के इस्पात की तार से विनिर्मित किया जाएगा लाइन तार की तनन मजबूती, जब उसका परीक्षण सुसंगत भारतीय मानक में विहित पद्धति के अनुसार किया जाए, तब, 40 कि०ग्रा० एफ मि०मी० 2 से कम नहीं होगी। लाइन तार तथा प्वाइंट तार खंड में बूझाकर होगी, पपड़ी तथा अन्य दोषों में मुक्त होगी और एक समान गाल्वनीकृत होगी लाइन-तार लगातार एक ही लम्बाई की हूंगी तथा उसकी लिचाई से पहले उसमें राइ में के बेल्ट के प्रतिरिक्त और कोई बेल्ट नहीं होंगे। दो क्रमवर्ती जोड़ों के बीच की दूरी 15 मीटर से कम नहीं होगी।'

(2) पैरा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'जब पर्याप्त लम्बाई वाली लाइन-तार को, पास-पास वाली कुण्डली का रूप देने के लिए, लाइन-तार, के तामिक व्यास के चार गुने व्यास वाले मैन्ड्रेल बेलनकार के चारों ओर 16 बार प्रति मिनट से अनुधिक की दर से लपेटा जाए तब जबसे की परत इस्पात के तार के साथ चिपकी रहेगी तथा संतोषजनक समझी जाएगी यदि इस प्रकार लपेटने या मोड़ने पर वह इस हद तक न झड़े और न बिटके कि तंगी जंगलियों से रगड़ने पर जस्त के हट जाने की संभावना हो। इसके लिए जंगलियों के नाखूनों का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा। लाइन तथा प्वाइंट तारों पर जस्ते की परत का भार वह होगा जिस पर विदेशी क्रेता तथा निर्यातकर्ता के मध्य सहमति हुई हो, किन्तु वह भार जब उसका परीक्षण सुसंगत भारतीय या राष्ट्रीय मानक विनिर्देश में विहित किसी पद्धति से किया जाए, तब, किसी भी दशा में 70 ग्राम मी० 2 से कम नहीं होगा।'

[सं० 6(14)-74-नि० मि० तथा नि० उ०]

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 24th December, 1977

S.O. 4006.—Whereas for the development of the export trade of India certain proposals for amending the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 895, dated the 21st February, 1976 relating to inspection of Light Engineering Products, were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, under the order of the Government of India in the Ministry of

Commerce No. S.O. 1555 dated the 28th May, 1977 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 28th May, 1977 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within forty five days from the date of publication of the Order in the Official Gazette;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 31st May, 1977;

And whereas objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, hereby makes the following amendment in the order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 895 dated the 21st February, 1976, namely :—

In the said order, Annexure II, under the heading "II BUILDER'S HARDWARE" under the sub-heading "2. Specification for Galvanised steel barbed wire for fencing".—

(i) for paragraph 1, the following shall be substituted, namely :—

"1. The barbed wire shall be manufactured from a good commercial quality steel wire. The tensile strength of line wire shall not be less than 40 kgs/mm² when tested by a prescribed method as in the relevant Indian Standard. The line wire and point wire shall be circular in section, free from scales and other defects and shall be uniformly galvanised. The line wire shall be continuous in length and shall not contain any welds other than those in the rod before it is drawn. The distance between two successive splices shall not be less than 15 meters".

(ii) for paragraph 4, the following shall be substituted namely :—

"When the line wire of sufficient length is wound round a cylindrical mandrel of diameter equal to four times the nominal diameter of line wire at a rate not exceeding 15 turns per minute to form close spirals, the zinc coating shall remain adhered to the steel wire and shall be considered as satisfactory if owing to such winding or bending it does not flake off nor crack to such an extent that there is possibility of removing any zinc by rubbing with bare fingers, the use of finger nail being not allowed. The weight of zinc coating on line and point wires shall be as agreed upon between the foreign buyer and the exporter but shall in no case be less than 70 gm/m² when tested by a method prescribed in the relevant Indian or National Standard specification."

[No. 6(14)/74-EI&EP]

आदेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1977

क्र० प्रा० 4007 - भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण के अधीन लाने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या क्र० प्रा० 5368 ता० 7 दिसम्बर, 1971 को अधिष्ठान्त करने हुए, कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी) नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 5 के उपनियम (2) की अपेक्षाानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय के आदेश, तारीख 22 जनवरी, 1977 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र तारीख 22 जनवरी, 1977 में प्रकाशित किए गए थे,

और उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी। उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर आक्षेप तथा सुझाव मांगे गए थे,

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता की 29 जनवरी, 1977 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः अब, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या क्र० प्रा० 771, तारीख 6 मार्च, 1965 तथा भारत सरकार के भूतपूर्व विशेष व्यापार मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या क्र० प्रा० 5368, तारीख 7 दिसम्बर, 1971 को अधिष्ठान्त करने हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण परिणाम से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, -

- (1) अधिसूचित करती है कि मछली तथा मछली से बनी वस्तुएं निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण के अधीन होंगी,
- (2) मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं के निर्यात, (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1977 के अनुसार, क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण के प्रकार की निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो ऐसी मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं का निर्यात से पूर्व लागू होगा,
- (3) इस आदेश के उपाबंध में दिए गए विनिर्देशों का, मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देनी है;
- (4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान, मछली से बनी वस्तुओं के निर्यात को तब तक प्रतिबन्ध करती है जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी) नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या स्थापित अधिष्करण द्वारा जारी किया गया इस आदेश का निरीक्षण प्रमाण पत्र न हो कि ऐसी मछली तथा मछली से बनी वस्तुएं मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं तथा निर्यात योग्य हैं।

2 इस आदेश की कोई भी बात धार्मी क्लेशों का भूमि जल या वायु मार्ग द्वारा मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं के उन नमूने के निर्यात को लागू नहीं होगी जिनका मूल्य किसी भी प्रकार के प्रति नमूने 500/- रु० से अधिक नहीं होगा।

3 इस आदेश के प्रयोजन के लिए 'मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं' से अभिप्राय होगा— सभी प्रकार के प्रशीतित झींगे (शिम्पस)

- | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (i) पूरी | —सिर तथा खोल सहित |
| (ii) सिर रहित | —सिर रहित, खोल सहित |
| (iii) गोम पखा-पुच्छ | —अन्तिम भाग तथा पुच्छ के ऊपर के सिवाय सिर तथा खोल सहित |
| (iv) शिरा रहित पखा-पुच्छ | —जैसा कि ऊपर (iii) में लेकिन भोजन नलिका निकाल दी गई। |
| (v) तितली पखा-पुच्छ | —जैसा कि ऊपर (iv) में, लेकिन काट कर खोली गई और अपेक्षित ढंग से रखी गई। |
| (vi) छिली हुई, कच्ची छिली हुई या छिली हुई शिरा रहित | —सिर तथा खोल पूरी तरह हटा दिए गए |
| (vii) छिली हुई तथा शिरा रहित | —जैसा कि ऊपर (vi) में लेकिन भोजन नलिका भी निकाल दी जाएगी। |
| (viii) पकाई हुई तथा छिली हुई | —जैसा कि ऊपर (vii) में लेकिन पकाते के पश्चात् |
| (ix) छिली हुई तथा पकाई हुई | —जैसा कि ऊपर (vi) में, लेकिन पकाई हुई |
| (x) छिली हुई शिरा रहित तथा पकाई हुई | —जैसा कि ऊपर (vii) में, लेकिन पकाई हुई भी |
| (xi) सारी, पकाई हुई | —जैसा कि ऊपर (i) में लेकिन पकाई हुई भी |

4 यह आदेश इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

उपाबंध

1 प्रशीतित झींगे के लिए विनिर्देश (झींगे)

क्र०सं०	विशेषमाण	के लिए अपेक्षाएं
	पूरी तथा सिर रहित खोल सहित	छिली हुई छिली हुई तथा शिरा रहित तथा तितली का प्रकार
1 खोल का रंग	ताजे पकड़े गए झींगे के प्राकृतिक रंग की विशेषता	ताजे पकाए गए झींगे के प्राकृतिक रंग की विशेषता
2 निर्जलन	सामान्यतः निर्जलन से मुक्त	सामान्यतः निर्जलन से मुक्त
3 मांस का रंग	ताजे झींगे की विशेषता	जातिगत रंग
4 खोल या मांस का काला बिबरण	सामान्यतः काले धब्बों से मुक्त	शून्य

1	2	3	4	5
5. मांस की बनावट	जमा हुआ तथा एक समान	जमा हुआ तथा एक समान	जमा हुआ तथा एक समान	जमा हुआ तथा एक समान
6. गंध	ताजे झींगों की विशेष गंध	कोई भी गंधी या बाह्य गंध नहीं होनी चाहिए	ताजे पकाए गए झींगों की गंध	
7. सुगंध	ताजे झींगों की विशेषता	जातिगत सुगंध	जातिगत सुगंध	
8. प्रति ग्रा० 37 सें० ग्र० से गिनी गई कुल जीवाणुओं की संख्या अधिकतम	10,00,000	10,00,000	1,00,000	
9. ग्रा० या इ० कोनी संख्या अधिकतम	20	20	शून्य	
10. कोकुलेज जीवित जीव-गुच्छाणु प्रति ग्रा० संख्या अधिकतम	100	100	100	
11. सैल्मोनेल्ला तथा एरीशिया	शून्य	शून्य	शून्य	

मांस में धूल, कीड़े या बाल, या अन्य बाह्य पदार्थ, तथा कोई विषैला तथा हानिकारक पदार्थ तथा निषेध रसायन तत्व नहीं होंगे।

प्रशोधित झींगे (झींगे)

भकेतन

प्रशोधित झींगों के साथ एक संकेत पच्ची बंधी रहेगी। संकेत पच्ची पर तैयार करने वाले का नाम, उत्पाद का प्रकार, तैयार करने का वर्ष, महीना तथा तारीख संकेत में दी गई होगी। अलग-अलग शुद्ध: प्रशोधित (अ० अ० सं० प्र०) पैकिंग की दशा में संकेत पच्ची भीतरी डिब्बों में रखी जाएगी। संकेत पच्ची का संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है।

'एक्स बाई एफ एस पी डी

7ए 05'

उक्त उदाहरण में:

क ख

प्र० झी०

छी० सि० अ०

7

ए

05

—तैयार करने वाले का संकेत नाम

— प्रशोधित झींगे

— उत्पाद का प्रकार तथा इस उदाहरण में यह छोटे हुए तथा सिरा सहित प्रकार को सूचित करती है।

— तैयार करने का वर्ष और इस उदाहरण में यह 1977 वर्ष को सूचित करता है।

— तैयार करने का महीना और इस उदाहरण में यह जनवरी महीने को सूचित करता है।

— तैयार करने की तारीख और इस उदाहरण में यह महीने के पात्रवें दिन को सूचित करता है।

निम्नलिखित से संक्षेपाक्षर उत्पाद के प्रकार तथा वर्ष के महीनों के लिए प्रयोग किए जाएंगे:—

उत्पादन के प्रकार	संक्षेपाक्षर
1. संपूर्ण	स०
2. सिर रहित	सि० र०
3. फेनट्रेल गोल	फे० गो०
4. फेनट्रेल सिरा रहित	फे० सि० र०
5. फेनट्रेल बटरफलाई	फे० बा०
6. छीली हुई तथा शिला-रहित या कच्ची छीली हुई	छी० सि० र० या क० छि०
7. छीली हुई तथा सिरा सहित	छी० सि० स०
8. पकाई हुई तथा छीली हुई	प० छी०
9. छीली हुई और पकाई हुई	छी० प०
10. छीली हुई, सिरा-रहित तथा पकाई हुई	छी० सि० र० प०
11. संपूर्ण पकाई हुई	स० प०
महीना	संक्षेपाक्षर
जनवरी	ए
फरवरी	बी
मार्च	सी
अप्रैल	डी
मई	ई
जून	एफ
जुलाई	जी
अगस्त	एच
सितम्बर	जे
अक्टूबर	के
नवम्बर	एल
दिसम्बर	एम

2. झीगा मछली का प्रशीतित पृष्ठ भाग या पृष्ठ भाग के मांस के लिए विनिर्देश

भामान्य	व्यापार नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्मों पर आधारित प्रकार	आकार वर्ग ग्र०प्र०स० वैकिंग (प्रति टुकड़ा ग्रामों में भार पर आधारित)	वर्ग ब्लाक ग्र० प्रति 450 ग्रामों में	जीवाणु विज्ञान विषयक मानक	वैकिंग तथा भंडारकरण
1	2	3	4	5	6	7	8
झीगा मछली का प्रशीतित पृष्ठ भाग ताजे झीगों से पू० मांगों से सख प्रशीतित से तैयार किया जाएगा। इसका संसाधन सफाई से रखे गए परिवर में किया जाएगा। गलाने पर माल आकृष्ट करने वाला विशिष्ट रूप रखने हुए साफ होगा तथा हर प्रकार से जमा हुआ, माबुत, अक्षत तथा दोषों से मुक्त होगा। मांस ताजे पकड़े गए झीगों के विशिष्ट रंग तथा गंध वाला होगा तथा उसमें रंग, रंगहीनता या दुर्गन्ध नहीं होगी। माल अंडों, रेत, गंदगी तथा दूसरे बाह्य पदार्थों से मुक्त होगा।	चट्टानी झीगों का पृष्ठ भाग	पैनुलीरम	1. बर्फीले सफेद से सफेद 2. हल्के गुलाबी से गुलाबी	909/अधिक 794/908 680/793 567/679 455/566 341/454 284/340 227/283 171/226 114/170 57/113 29/56 29 से कम	नागू नहीं होता	1. कुल जीवाणु संख्या प्रति ग्रा० अधिकतम 5,00,000 2. ई०कोवी, प्रति ग्रा० अधिकतम —20 3. कोएगुलेस जीवित जीव गुच्छाणुओं की संख्या प्रति० ग्रा० अधिकतम—100	झीगा मछली का पृष्ठ भाग अद्वैता सुरक्षित फिल्म में अलग-अलग स्पेटा जाएगा या प्रशीतित से पहले ब्लाकों में रखे जायेंगे। प्रशीतित उत्पाद समुद्री जहाज में ले जाने योग्य नलीदार कार्डबोर्ड के डिब्बों में पैक किया जाएगा। प्रशीतित मांस 180 से०से० या उससे कम तापमान वाले कमरे में इकट्ठा किया जाएगा।
	रेतीले झीगों का पृष्ठ भाग	थुनुस एस० पी०	1. बर्फीले सफेद से सफेद 2. हल्के सफेद से हल्का भूरा	171/अधिक 57/113 29/56 29 से कम	नागू नहीं होगा	4. सैल मोनेस्ला शून्य	
	गहरे समुद्री झीगों का पृष्ठ भाग	पेरुलम एस०पी०	1. बर्फीले सफेद से सफेद 2. हल्के गुलाबी से गुलाबी	171/अधिक 114/170 57/113 29/56 15/28	यू/4 4/8 9/15 16/20 21/25 26/30		

पूरे पृष्ठ भाग तथा पृष्ठ भाग के मांस, आकार, वर्ग तथा वैकिंग केला की अपेक्षाओं के अनुसार होगी।

प्रशीतित झीगे मछली

संकेतन

प्रशीतित झीगा मछली के डिब्बों के लिए संकेत पत्रियां भीतरी डिब्बों में रखी जाएंगी। ताजेप में संकेत पत्रियां बनाने के लिए उदाहरण नीचे दिया गया है—

'एस्क बाई एल टी डी एस

77 05'

उक्त उदाहरण में—

क ख	—तैयार करने वाले का संकेत नाम
झी० पृष्ठ	—झीगा मछली का पृष्ठ भाग

स० झी० पू.	उत्पादन का प्रकार और इस उदाहरण से यह गहरे समुद्री झींगे के पृष्ठ-भाग को सूचित करता है।
7	—तैयार करने का वर्ष और हम उदाहरण में यह वर्ष 1977 को सूचित करता है।
ए	—तैयार करने का महीना और इस उदाहरण से यह जनवरी महीने को सूचित करता है।
05	—तैयार करने की तारीख और इस उदाहरण में यह महीने के पांचवें दिन को सूचित करता है।

निम्नलिखित संक्षेपाक्षर उत्पादन के प्रकार तथा वर्ष के महीने के लिए प्रयोग किया जाएगा—

महीना	संक्षेपाक्षर
जनवरी	ए
फरवरी	बी
मार्च	सी
अप्रैल	डी
मई	ई
जून	एफ
जुलाई	जी
अगस्त	एच
सितम्बर	जे
अक्टूबर	के
नवम्बर	एल
दिसम्बर	एम

उत्पाद का प्रकार

संक्षेपाक्षर

बट्टानी झींगा या बट्टानी झींगा मछली पूरी रेतीली झींगा या रेतीली झींगा मछली पूरी	ब०झी०/ब०झी०पू०
गहरे समुद्री झींगा मछली	रे० झी०/रे० झी० पू०
झींगा मछली का मांस	म० झी०
	झी०मा०

3 प्रशोधित पामफिट के लिए विनिर्देश

सामान्य	व्यापारिक नाम	वैज्ञानिक नाम	प्रकार	आकार, वर्ग, अ०अ०म० वैकिंग (ग्रा० टुकड़ों से भार पर आधारित)	जीवाणु विज्ञान संबंधी मानक	वैकिंग तथा भंडारण
				श्रेणी नाम	ग्रा० से भार	
1	2	3	4	5	6	7
प्रशोधित पामफिट साफ, सम्पूर्ण (गोल) तथा ताजे पामफिट के सद्यः प्रशोधित से तैयार की जाएगी। सफाई से रखे गए परिवार में संसाधन किया जाएगा। सामग्री झींगे जमने वाली होगी।	प्रशोधित सिलवर पामफिट	1 पैमास एम० पी० 2 स्ट्रोमेड्स एस०पी०	मफेब पामफिट	बड़ी मध्यम छोटी	450 से अधिक 301 से 450 200 से 300	1 प्रति ग्राम कुल प्रशोधित पामफिट आर्द्रता सुरक्षित फिल्म में अलग-अलग लपेट दी जाएगी। प्रशोधित उत्पाद समुद्री जहाज में ले जाने योग्य लम्बीदार काई बोर्ड के डिब्बों में पैक किया जाएगा। प्रशोधित मांस एक कमरे से एकट्ठा किया जाएगा। जिसका तापमान 180 में०से० या कम होगा।
	प्रशोधित भूरी पामफिट	1 वेरास्ट्रीमेट्स एस०पी० 2 पैमास एस०पी०	भूरी पामफिट	बड़ी मध्यम छोटी	1000 से अधिक 701 से 1000 450 से 700	2 प्रति ग्रा० ई० कोली, अधिकतम—20 3 कोयलेज प्रशोधित जीव-गुच्छाणुओं की प्रति ग्राम, अधिकतम संख्या—100 4 सालमोनेल्वा शून्य

प्रशिक्षित पामफिट

संकेत

अलग-अलग मत्स्य प्रशिक्षित पामफिट वाले डिब्बों के लिए, संकेत पर्ची भीतरी डिब्बों के अन्दर रखी जाएगी। या संकेत पर्ची प्रशिक्षित उत्पाद की दशा में प्रशिक्षित खण्ड में चिपकी होगी। संक्षेप में संकेत पर्ची बनाने के लिए उदाहरण नीचे दिया गया है:—

‘एक्स बाई एफ पी डब्ल्यू’

7ए 05

उक्त उदाहरण में,

क ख	—तैयार करने वाले का संकेत नाम
प्र०पामी०	—प० पामफिट, म० —सफेद
7	— तैयार करने का वर्ष और इस उदाहरण में यह 1977 वर्ष को सूचित करता है।
ए	—तैयार करने का महीना और इस उदाहरण में यह जनवरी महीने को सूचित करता है।
05	—तैयार करने की तारीख और इस उदाहरण में यह महीने का पांचवां दिन सूचित करता है।

निम्नलिखित संक्षेपाक्षर उत्पादन के प्रकार तथा वर्ष के महीनों के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे:—

उत्पाद का प्रकार	संक्षेपाक्षर
सफेद पामफिट	म० पामी०
काली पामफिट	क० पामी०
भूरी पामफिट	भू० पामी०
महीना	संक्षेपाक्षर
जनवरी	ए
फरवरी	बी
मार्च	सी
अप्रैल	डी
मई	ई
जून	एफ
जुलाई	जी
अगस्त	एच
सितम्बर	जे
अक्तूबर	के
नवम्बर	एल
दिसम्बर	एम

4 प्रशिक्षित कटल फिश तथा स्क्वीड्स के लिए विनिर्देश

सामान्य	व्यापार नाम	वैज्ञानिक नाम	(मांस के रंग पर आधारित प्रकार)	आकार वर्ग पैक का प्रकार	संख्या	जीवाणु विज्ञान संबंधी मानक	पैकिंग तथा भण्डारीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8
कटल फिश तथा स्क्वीड्स के प्रशिक्षित धरत ताजे तथा कटल फिश तथा स्क्वीड्स से प्राप्त फिलेट्स को मत्स्य प्रशिक्षण द्वारा तैयार किया जाएगा। भाव विकृति, बिगड़ने निर्जलन को कोई चिन्ह नहीं दिखाएगा तथा स्याही तथा बासीपन से मुक्त होगा। ममाघत होगा साफ रखे गए परिसर में किया जाएगा।	कटल फिश	1. सेपिया जाति 2. सिपएला जाति 3. सिम्पलेक्टो- म्यूसिम एस०पी०	(i) सफेद (ii) दूधिया सफेद	(i) पूरी (ii) चपटी पैक (iii) रोल की हुई पैक (iv) आई० क्यू० अफ० पैक	5/10 11/20 21/30 3/4 5/6 7/8 9/10 81/120 121/160 161/200 201/300 301/अधिक	1. कुल जीवाणु संख्या प्रति ग्राम— 1,00,000 2. ई०कोली संख्या या ग्रा०, अधिकतम 10 10 3. कोएगुलेम जीवित जीव-गुण्ठाणुओं की प्रति ग्राम सं० अधिकतम—100 4. सालमोनेल्ला— शून्य	धरतें आर्द्रता सुरक्षित फिल्म में अलग-अलग लपेटी जाएगी या प्रशिक्षण से पहले ब्लाकों में रखी जाएगी प्रशिक्षित उत्पाद समुद्री जहाज में ले जाने योग्य 5-प्लार्टे नलीदार कार्ड बोर्ड डिब्बों में पैक किया जाएगा। प्रशिक्षित मास 180 से० ग्रे० या उससे कम तापमान वाले कमरे में इकट्ठा किया जाएगा।
	स्क्वीड्स	1. लोलाइगो जाति 2. सेपीट्यूधिस जाति 3. लोलाइलू जाति 4. इमुपरीमना जाति					

प्रशिक्षित कटल फिश तथा स्क्वीड्स

संकेतन

कटल फिश तथा स्क्वीड्स (अ०प्र०स०प्र०) रखने वाले बिन्दुओं के लिए संकेत पत्रों भीतरी बिन्दु में रखी जाएगी या संकेत पत्रों खण्डीय प्रशिक्षित उत्पादन की दशा में प्रशिक्षित खण्ड से बिपक्षी रहेगी। संकेत पत्रों को संक्षिप्त रूप में बनाने के लिए एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है:—

'एक्स वाई सी एफ/एस व्यू'

7ए 05

उक्त उदाहरण में,

क ख	—तैयार करने वाले का संकेत नाम
कौ०फि०स्क्वी०	—कटल फिश तथा स्क्वीड्स
7	—तैयार करने का वर्ष और इस उदाहरण में यह 1977 वर्ष को सूचित करता है।
ए	—तैयार करने का महीना और इस उदाहरण में यह जनवरी महीने को सूचित करता है।
05	—तैयार करने की तारीख और इस उदाहरण में यह महीने के पांचवें दिन को सूचित करता है।

निम्नलिखित संक्षेपाक्षर उत्पाद के प्रकार तथा वर्ष के महीनों के लिए प्रयोग किए जाएंगे —

उत्पाद का प्रकार	संक्षेपाक्षर
कटल फिश स्क्वीड्स	कौ०फि०स्क्वी०
स्क्वीड्स	स्क्वी०
पूरा	पू०
चपटा पैक	च०पै०
रोल किया हुआ पैक	रो०पै०
महीना	संक्षेपाक्षर
जनवरी	ए
फरवरी	बी
मार्च	सी
अप्रैल	डी
मई	ई
जून	एफ
जुलाई	जी
अगस्त	एच
सितम्बर	जे
अक्टूबर	के
नवम्बर	एल
दिसम्बर	एस

[स० 6(21)/76—नि०नि० तथा नि०प०]

ORDER

New Delhi, the 31st December, 1977

S.O. 4007.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Fish and Fishery Products to quality control and inspection prior to export, in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 771, dated the 6th March, 1965 and the notification of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 5368, dated the 7th December, 1971, were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India dated the 22nd January, 1977 under the Order of

the Government of India in the Ministry of Commerce dated the 22nd January, 1977;

And whereas objections and suggestions were invited within fortyfive days of the publication of the said Order from all persons likely to be affected thereby;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 29th January, 1977;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Com-

merce No. S.O. 771, dated the 6th March, 1965 and the notification of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 5368, dated the 7th December, 1971, the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby—

- (1) notifies that Fish and Fishery Products shall be subject to quality control and inspection prior to export;
- (2) specifies the type of quality control and inspection in accordance with the Export of Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1977 as the type of inspection which shall be applied to such fish and fishery products prior to their export;
- (3) recognises the specifications as set out in the Annexure to this Order as the standard specifications for fish and fishery products;

(4) prohibits the export, in the course of international trade of such fish and fishery products unless the same are accompanied by a certificate of inspection issued by an agency established or recognised by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that such fish and fishery products conform to the standard specifications and are exportworthy.

2. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of samples of fish and fishery products to prospective buyers, the value of which does not exceed Rs. 500 per sample of any type.

3. For the purpose of this order "Fish and Fishery Products" means—

All types of frozen prawns (Shrimps)–

- (i) Whole —Head and shell-on
- (ii) Headless —Head removed, shell-on
- (iii) Fantail round —Head and shell removed except on last segment and tail
- (iv) Fantail deveined —As in (iii) above, but the alimentary canal removed
- (v) Fantail butterfly —As in (iv) above, but split open and arranged in required pattern
- (vi) Peeled, raw peeled or peeled undeveined —Head and shell removed completely
- (vii) Peeled and deveined —As in (vi) above, but the alimentary canal also removed
- (viii) Cooked and peeled —As in (vi) above, but after cooking
- (ix) Peeled and cooked —As in (vi) above, but cooked
- (x) Peeled, deveined and cooked —As in (vii) above, but also cooked
- (xi) Whole, cooked —As in (i) above, but also cooked

4. This order shall come into force on the date of its publication in the official gazette.

ANNEXURE

1. Specifications for frozen prawns (shrimps)

Sl. No.	Characteristics	Requirement for		
		Whole type and Headless shell-on type	Peeled, Peeled and Deveined and Butterfly type	Cooked type
1	2	3	4	5
1.	Colour of shell	Natural colour characteristic of freshly caught prawn.	—	Natural colour characteristic of fresh cooked prawn.
2.	Dehydration	Reasonably free from dehydration.	Reasonably free from dehydration.	Reasonably free from dehydr.
3.	Colour of flesh	Characteristic of fresh prawn	Characteristic colour	Characteristic cooked colour
4.	Blackspots of shell or meat	Reasonably free from blackspots	Nil	Nil
5.	Texture of meat	Firm and consistent	Firm and consistent	Firm and consistent
6.	Odour	Characteristic odour of fresh prawn	Absence of any off odour or foreign odour	Odour of fresh cooked prawn
7.	Flavour	Characteristic of fresh prawn	Characteristic flavour	Characteristic flavour
8.	Total plate count at 37°C per gram, max.	10,00,000	10,00,000	1,00,000
9.	E. Coli count or gram, max.	20	20	Nil
10.	Coagulase positive staphylococcus count or gram max.	100	100	100
11.	Salmonella and Arizona	Nil	Nil	Nil

The material shall be free from dirt, insect or hair, or other objectionable extraneous matter, and from any poisonous and deleterious substances and prohibited chemical additives.

Frozen prawns (shrimps)

CODING

A code slip should be embedded on the frozen block. The code slip shall bear the marking of the name of processor in code, name and type of the product, year, month and date of processing. In case of individually quick frozen (IQF) packing, the code slip shall be placed inside the primary container. An illustration for making the code slips in the abbreviated form is given below :—

‘XYFSPD

7A 05’

where, in the above illustration :—

XY—name of the processor in code

FS—frozen shrimps

PD—type of product (here peeled and deveined type)

7—year of processing (here 1977)

A—month of processing (here January); and

05—date of processing (here—fifth day of the month).

The following abbreviations shall be used for type of product and months of the year :—

Type of the product	Abbreviation
1. Whole	WL
2. Headless	HL
3. Fantail round	FL
4. Fantail deveined	FLD
5. Fantail butterfly	FLBF
6. Peeled and undeveined or raw peeled	PUD OR RP
7. Peeled and Deveined	PD
8. Cooked and Peeled	CP
9. Peeled & Cooked	PC
10. Peeled, deveined and cooked	PDC
11. Whole cooked	WLC

Month	Abbreviation
January	A
February	B
March	C
April	D
May	E
June	F
July	G
August	H
September	J
October	K
November	L
December	M

2. Specifications for frozen lobsters or lobster meat

General	Trade name	Scientific name	Type depending upon species	Size-grade IQF pkg. (based on wt. in gms. per piece)	Grade block pkg. (now per 450 gms)	Bacteriological standard	Packing and storage
1	2	3	4	5	6	7	8
Frozen lobster tails shall be prepared by quick freezing the tails obtained from fresh lobsters. The processing shall be carried out in a premises maintained in hygienic manner. The material on thawing shall be clean having an attractive characteristic appearance and, shall in every way be in a sound, intact, undamaged condition and free from defects. The meat shall have the characteristic colour and odour of that of freshly caught lobsters and shall not have any discolouration or off odour. The material shall be free from eggs, sand, dirt and any other objectionable extraneous matter.	Rock Lobster	Panulirus sp.	1. Snow-white to white 2. Light pink to pink	909/Up 794/908 567/679 455/566 341/454 284/340 227/283 171/226 114/170 57/113 29/56 Under 29	Not Applicable	1. Total Plate count per gram, max.—5,00,000 2. E. coli per gram, max. 20 3. Coagulase positive Staphylococcus count or gram, max.—100. 4. Salmonella—nil	Lobster tails shall be wrapped individually in moisture proof film or arranged in blocks before freezing. The frozen products shall be packed in seaworthy corrugated cardboard boxes.
	Sand Lobster	Thunnus sp.	1. Snow-white to white 2. Off white to light brown	171/Up 57/113 29/56 Under 29	-do-		The frozen material shall be stored in a room maintained at 18°C tem. or less.
	Deep Sea lobster	Peurulus sp.	1. Snow-white to white 2. Light pink to pink	171/Up 114/170 57/113 29/56 15/28	U/4 4/8 9/15 16/20 21/25 26/30		

In the case of whole lobster and lobster meat, the size-grade and packing shall be as per the requirements of the buyer. (coding details given below)

FROZEN LOBSTERS

Coding

For the cartons containing frozen lobster, the code slip may be placed inside the primary container. An illustration for making the code slip in the abbreviated form is given below :—

'XYLTDS
7 A 05'

where, in the above illustration :—

XY—name of the processor in code

LT—lobster tails

DS—type of product (here—deep sea lobster)

7—year of processing (here 1977)

A—month of processing (here—Jan.)

05—date of processing (here—fifth day of the month)

The following abbreviations shall be used for type of product and months of the year :—

Type of product	Abbreviation
Rock lobster or Rock lobster whole	RL/RLW
Sand lobster or Sand lobster whole	SL/SLW
Deep sea lobster	DS
Lobster meat	LM

Month	Abbreviation
January	A
February	B
March	C
April	D
May	E
June	F
July	G
August	H
September	J
October	K
November	L
December	M

3. Specification for frozen pomfrets

General	Trade name	Scientific name	Type	Size-grade, IQF packing (based on weight) in gms/pcs)	Bacteriological standards	Packing and storage
				Grade designation	Wt. in gms.	
The frozen pomfrets shall be prepared by quick freezing the clean, wholesome (round) and fresh pomfrets. The processing shall be carried out in premises maintained in hygienic manner. The material shall be quick frozen.	Frozen Silver pomfret	1. Pampus sp. White 2. Stromateus pomfret sp.		Large	Above 450	The frozen pomfrets shall be wrapped in moisture-proof film. The frozen products shall be packed in seaworthy corrugated cardboard boxes. The frozen material shall be stored in a room maintained at or below 18°C temp.
				Medium	301 to 450	
				Small	200 to 300	
	Frozen Brown Pomfret	1. Parastro mateus sp. 2. Pampus sp. Black pomfret	Brown Pomfret	Large	Above 1000	
				Medium	701-1000	
				Small	450-700	
						1. Total plate count or gram max.—5,00,000 2. E. coli per gram max.—20. 3. Coagulase positive staphylococcus count or gram max.—100 4. Salmonella—nil

FROZEN POMFRETS

Coding

For the cartons containing frozen pomfrets, the code slips shall be placed inside the primary container, or the code slip shall be embedded in the frozen block in case of block frozen products. An illustration for making the code slip in the abbreviated form is given below:—

‘XYFPW

7A 05’

where, in the above illustration :—

XY—name of the processor in code

FP—frozen pomfrets

W—white

7—year of processing (here—1977)

A—month of processing (here Jan.)

05—date of processing (here fifth day of the month)

The following abbreviations shall be used for type of product, and months of the year.

Type of product	Abbreviation
White pomfret	W
Black pomfret	B
Brown pomfret	BR

Months	Abbreviation
January	A
February	B
March	C
April	D
May	E
June	F
July	G
August	H
Sept.	J
Oct.	K
Nov.	L
Dec.	M

4 Specifications for frozen cuttle fish and squids

General	Trade name	Scientific name	Type (depending upon the colour of meat)	Size grade		Bacteriological standards	Packing and storage
				Type of pack	Count kg.		
Frozen fillets of cuttle fish and squids shall be prepared by quick freezing the fillets obtained from fresh and wholesome cuttle fish & squids. The material shall not show any sign of deterioration, spoilage, dehydration, shall be free from ink and bruises. The processing shall be carried out in a premises maintained in a hygienic manner.	Cuttle fish	1. Sepia sp. (i) White 2. Sepiolla sp. (ii) Milky 3. Symplectoteuthis sp.	(i) Whole (ii) Flat pack (iii) Rolled pack (iv) IQF pack	U/10 11/20 21/30 3/4 5/6		1. Total plate count per gram, max.—1,00,000 2. E. Coli count or gram max.—10 3. Coagulase positive staphylococcus or gram. max.—100 4. Salmonella—nil	The fillets shall be wrapped individually in moisture—proof film or arranged in block before freezing. The frozen product shall be packed in atleast 5-ply seaworth corrugated cardboard cartons. The frozen material shall be stored in room maintained at or below—18°C temp.
	Squids	1. Loligo sp. 2. Sepioteuthis sp. 3. Loliolu sp. 4. Euprymna sp.		7/8 9/10 G/fillet 81/120 121/160 161/200 201/300 301/Up			

The material shall be quick frozen at a temp. not exceeding —30°C within 4 hrs. after filleting and dressing. The frozen fillets on thawing shall be clean, absolutely white or milky white in colour and shall be in a sound, intact, undamaged condition, and free from any visible defects. The product shall be free from objectionable foreign matter.

FROZEN CUTTLE FISH & SQUIDS

Coding

For the cartons containing frozen cuttle fish and squids, the code slips shall be placed inside the primary container, or the code slip shall be embedded in the frozen blocks in case of block frozen products. An illustration for making the code slips in the abbreviated form is given below.

'XYCFSQ
7A 05'

where, in the above illustration

XY—name of the processor in code

CF/SQ—Cuttle fish or squids

7—year of the processing (here—1977)

A—month of processing (here—Jan.)

05—date of processing (here—fifth day of the month)

The following abbreviations shall be used for type of product and months of the year :—

Type of product	Abbreviation
Cuttle fish/squids	CF
Squids	SQ
Whole	W
Flat pack	F
Rolled pack	R
Month	Abbreviation
January	A
February	B
March	C
April	D
May	E
June	F
July	G
August	H
Sept.	J
Oct.	K
Nov.	L
Dec.	M

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1977

क्रा.भा. 4008.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्यालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1964, तथा मेंढक की प्रशीतित टांगों के निर्यात (निरीक्षण) नियम 1971 को, सिवाय उन बातों के जो की जा चुकी हैं या की जाने से रद्द गई हैं, अधिकृत करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :— (1) इन नियमों का नाम मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं का निर्यात (क्यालिटी नियन्त्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1977 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रभूत होंगे।

2 परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि मदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्यालिटी नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है।

(ख) 'अधिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यता-प्राप्त या स्थापित अधिकरणों से से कोई अभिप्रेत है।

(ग) 'मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं' से अभिप्रेत है—

I (1) सभी प्रकार के प्रशीतित स्त्रीगे (स्त्रीगे)—

- (i) पूरी . . . मिर तथा खोल सहित
(ii) सिर रहित . . . मिर रहित, खोल सहित

[No. 6(21)/76-EI & EP]

- (iii) गोल पंखा तुच्छ . . . अंतिम भाग तथा पुच्छ के ऊपर के सिवाय मिर तथा खोल रहित
(iv) शिरा रहित, पंखा तुच्छ . . . जैसा कि ऊपर (iii) में, लेकिन भोजन तनिका निकाल दी गई।
(v) नितली पंखा पुच्छ . . . जैसा कि ऊपर (iv) में, लेकिन काट कर खोला गई और अपेक्षित ढंग से रखी गई।
(vi) छिली हुई, कर्छा छिली . . . मिर तथा खोल पूरी तरह हटा दिए, हुई या छिली हुई शिरा रहित गए।
(vii) छिली हुई तथा मिरा रहित . . . जैसा कि ऊपर (vi) में, लेकिन भोजन तनिका भी निकाल दी जाएगी।
(viii) पकाई हुई तथा छिली हुई . . . जैसा कि ऊपर (vi) में, लेकिन पकाने के बाद
(ix) छिली हुई तथा पकाई हुई . . . जैसा कि ऊपर (vi) में, लेकिन पकाई हुई।
(x) छिली हुई, शिरा रहित तथा पकाई हुई . . . जैसा कि ऊपर (vii) में, लेकिन पकाई हुई भी।
(xi) साबुत, पकाई हुई . . . जैसा कि ऊपर (i) में, लेकिन पकाई हुई भी।

II से प्राप्त सभी प्रकार के स्त्रीगे—

- (i) चट्टानी स्त्रीगे . . . (1) पेनुलिस होंमारस
(2) पेनुलिस आरनेटस
(3) पेनुलिस पाणपेहिषम
(ii) गहरे समुद्र वाले स्त्रीगे . . . पेनुलिस सीमेनार्ड
(iii) रेतीले स्त्रीगे . . . थूनुम जासि

III. सभी प्रकार के प्रशीतित बीजे जैसे—

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| (i) पैम्पस अरजेन्टस | } सफेद पामफ्रिट |
| (ii) स्टोमेटस सडनेसिस | |
| (iii) पैरास्टोमेटस नाइगर | धूरी पामफ्रिट |
| (iv) पैम्पस चाइनेसिस | काली पामफ्रिट या चाइनीस पामफ्रिट |

IV.

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| (i) सेपिया फेरानिस | |
| (ii) सेपिया एक्स्प्लिंटा | |
| (iii) सेपिया पस्टोनाई | |
| (iv) सेपिया लेवीनाना | कटल मछली की दशा में। |
| (v) पेपीला इन्टरमिस | |
| (vi) सेपीला इडियोलस | |
| (vii) मिम्पलैक्टोप्युस जाति | |

तथा

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| (i) लोलाइगो हाईवीकी | |
| (ii) लोलाइगो इन्डिका | |
| (iii) लोलाइगो एफ्रिनिस | स्क्वीड्स की दशा में |
| (iv) सीपियोटयडिस | |
| (v) लोलाइगो ड्यूवासे-नार्ड | |
| (vi) लोलीओलस इन्वेस्टीगेटीज | |
| (vii) ड्यूपरमना स्टनोडोटीला | |

इन्से प्रकृतित सभी प्रकार की प्रशीतित कटल मछली तथा स्क्वीड्स।

(घ) "मानक विनिर्देशों" से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 4008 तारीख 31/12/1977 के उपाबंध में दिए गए सीजे (शिम्पस), प्रशीतित बीजे मछली, प्रशीतित पामफ्रिट तथा प्रशीतित कटल मछली तथा स्क्वीड्स के विनिर्देश अभिप्रेत हैं।

3. बनावटी नियंत्रण

क. प्रसंस्करण यूनिटों की अपेक्षाएं :

अधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण यूनिट हों नियमित के लिए मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं को प्रसंस्कृत करने योग्य होंगे तथा अनुमोदित प्राप्त करने के लिए एक यूनिट के पास नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए।

(1) वातावरण, बनावट तथा अभिव्यास :

(क) प्रसंस्करण यूनिट के आस पास दलदल, कूड़े का ढेर या पशुश्रृंखला नहीं होंगे जो कि स्वच्छता के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं।

(ख) हवा से उड़कर आने वाली धूल से बचाने के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र के तात्कालिक सभी भागों पर कंक्रिट या तारकोल बिछा होगा या घास उगाई जाएगी।

(ग) प्रसंस्करण यूनिट एक स्याही भवन में होगा जहां वर्षा तथा हवा से उड़ने वाली धूल जैसे सामान्य जलवायु संबंधी खतरों से पर्याप्त सुरक्षा रहेगी।

(घ) विभिन्न अनुभागों का अभिव्यास इस ढंग से किया जाएगा जिससे काम को आसानी से किया जा सके और प्रसंस्करण अनुभाग से संभव दूषण को बचाया जा सके।

(2) प्रसंस्करण क्षेत्र :

(क) वह क्षेत्र जहां कच्चा माल प्राप्त तथा भंडारित किया जाता है उस क्षेत्र में विशुद्ध अलग होगा जिसमें उत्पाद अंतिम रूप से तैयार होता है या उसकी पैकिंग की जाती है जिससे कि तैयार उत्पाद दूषित होने से बच सके।

(ख) खाद्य वस्तुओं का संयोज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र तथा कक्ष उनसे अलग तथा भिन्न होंगे जिनमें अखाद्य सामग्री रखी जाती है।

(ग) जिन क्षेत्रों में सामग्री उठाई धरी जाती है वे निवास के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त क्षेत्र से बिल्कुल अलग होंगे।

(3) छत, दीवार तथा फर्श :

(क) उस कमरे की छत जहां माल या तो रखा जाता है या प्रसंस्कृत किया जाता है, दरारों तथा खूँसे जोड़ों से मुक्त होनी चाहिए जिसमें आसानी से सफाई की जा सकेगी।

(ख) छत में कुत्तक आश्रय के लिए कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए।

(ग) प्रसंस्करण क्षेत्र की दीवारें चिकनी तथा गड़्ढों और दरारों से मुक्त होनी चाहिए तथा ऐसी होनी चाहिए जिन्हें कम से कम 1.3 मीटर तक की ऊंचाई तक धोया जा सके।

(घ) फर्श अपारगम्य तथा असंश्लेष्य सामग्री से बना होना चाहिए तथा उसमें व्यर्थ के पानी को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त ढलान होना चाहिए।

(ङ) फर्श तथा दीवार इस ढंग से बने होने चाहिए कि सफाई आसानी से की जा सके।

(4) मक्खियों से बचाव, कीड़ों तथा जानवरों पर नियंत्रण :

(क) प्रसंस्करण क्षेत्र मक्खियों के बचाव के सभी प्रभावशाली-प्रयत्नों से युक्त होगा।

(ख) प्रसंस्करण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कीड़ों, कृंतकों, पक्षियों, बिलियों, कुत्तों तथा इसी प्रकार के जानवरों का प्रवेश रोकने के लिए साधन अपनाए जाएंगे।

(5) प्रकाश तथा संशानन :

(क) काम के सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रकाश होना चाहिए।

(ख) उत्पाद के ऊपर या उसकी तैयारी के किसी भी स्तर पर, लटकते हुए रोशनों के बल्व तथा फिक्सचर सुरक्षित प्रकार के होने चाहिए तथा टूटने की दशा में संदूषण को रोकने के लिए उन्हें अस्थिर सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

(ग) जिन कमरों में काम किया जाता है वहां तारों हवा को लाने के लिए, अवांछनीय गंध, भाप तथा धुएँ को दूर करने के लिए तथा उन्हें संयोजन से सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक या यांत्रिक संशानन प्रणाली की पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए।

(6) काम करने के लिए मेजें तथा बर्तन :

(क) प्रसंस्करण कार्य के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मेजें लकड़ी के अनिश्चित असंश्लेष्य, अनभिहारक की सामग्री की होंगी।

(ख) प्रसंस्करण मेजें इस तरह की बनावट तथा लगाई जाएंगी कि नीचे और आसपास के क्षेत्रों तक की सफाई की जा सके।

(ग) मेज की सतह स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम अथवा जंग रहित गाल्वनीजेटेड चांदर की होंगी तथा चिकनी होंगी और गड़्ढों या दरारों से मुक्त होंगी।

(घ) काम वाली मेजों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि काम सुगमता से किया जा सके।

(ङ) प्रसंस्करण के लिए सभी पात्र जैसे ट्रे, ट्रंक, बेट तथा बर्तन, लकड़ी के अनिश्चित असंश्लेष्य पदार्थ के होंगे तथा दरारों से मुक्त समतल सतह वाले होंगे।

(च) इन्सेमल किए गए बर्तनों को प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।

(छ) खोल वाली क्रेस्टेशिया को उठाने-धरने के लिये तार की जाली वाले पात्र प्रयोग में लाए जाएंगे।

(ज) सामग्री को उठाने-धरने के लिए बांस की टोकरियां प्रयोग में नहीं लाई जाएंगी।

(झ) अखाद्य तथा संदूषित सामग्री को प्रयोग में लाने वाले उपस्कर तथा बर्तन किसी चिन्ह या आकार या रंग से अंकित होंगे और अलग पहचाने जाएंगे ताकि यह खाद्य वस्तुओं को उठाने धरने के प्रयोग में न लाया जा सके।

(ञ) प्रसंस्करण के दौरान कालतु वस्तुएं कार्यस्थल से समय-समय पर हटायी जाएंगी तथा इस प्रयोजन के लिए रद्दी बर्तन पर्याप्त संख्या में रखे जाएंगे।

(7) यंत्र मशीन

(क) कार्य अधिक होने के समय उत्पादन को पूरा करने के लिए प्रशीतन क्षमता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए।

(ख) जिस प्रकार का प्रशीतन काम में लाया जाएगा वह उत्पाद की प्रकृति तथा पैक के प्रकार के लिए विशेष किस्म का होगा।

(ग) सामग्री अल्बि जमने वाली होगी।

(घ) ब्लाक प्रशीतन की दशा में सामग्री का तापमान 3 घंटे की अवधि में -40° से 0° के करीब पहुंचेगा।

(ङ) प्रशीतन उपकरण तापमान तथा दाब दिखाने के लिए जाली के साथ फिट किए जाएंगे।

(च) पकाने की सभी क्रियाएं भाप द्वारा की जाएंगी तथा दाब गेज मापक और थर्मामीटर के साथ भाप सह पात्र या भमके लगे होंगे।

(8) शीतागार तथा माल गोदाम

(क) शीतागार की स्थिति तथा डिजाइन इस प्रकार की होनी चाहिए कि यह संपूर्ण स्थापना के सामान्य अभिलेख के साथ मिल जाए तथा इसका प्रचालन संपूर्ण कार्य की प्रवाही पद्धति में खप सके।

(ख) प्रत्येक प्रशीतन यूनिट के साथ पर्याप्त क्षमता वाले शीतागार होने चाहिए।

(ग) शीतागार का उचित तापमान -18° से 0° अथवा कम होगा और वह अधिमानतः स्वचालित तापमान अभिलेखन यंत्र के साथ फिट होगा।

(घ) निरन्तर अभिलेखन थर्मामीटर के अभाव में, शीतागार का तापमान कम से कम 4 घंटे में मापा जाएगा तथा उचित अभिलेख रखे जाएंगे।

(ङ) शीतागार में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, तथा आसानी से हवा आने-जाने की सुविधा के लिए फर्श तथा साइडो पर उचित प्रयत्न होने चाहिए।

(च) शीतागार में प्रवेश की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्रवेश द्वारा खोलने पर तापमान में अधिक वृद्धि न हो जाए अन्यथा इसमें भंडारित सामान पर कुप्रभाव पड़ेगा।

(छ) उचित आकार के एक संलग्न कक्ष की भी निश्चित व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ज) शीतागार की प्रशीतक सतह को, उस पर बर्फ या हिम के अधिक जमने से बचाने के लिए, नियमित रूप से विहिमीकृत किया जाएगा अन्यथा प्रशीतन यंत्र की क्षमता गम्भीर रूप से प्रभावित हो सकती है।

(झ) विहिमीकरण के दौरान इस का ध्यान रखा जाएगा कि हिम/बर्फ का पिघल कर बना पानी भंडार किए हुए उत्पाद पर न पड़े।

(ञ) यदि कोई व्यक्ति शीतागार के अन्दर फंस जाए तो उनके लिए शीतागार में प्रभावी संकेत यंत्र लगे होंगे।

(ट) शीतागार में सफाई संबंधी अपेक्षाओं का उसी प्रकार पालन किया जाएगा जैसा कि सामग्री की व्यवस्था करने वाले अन्य स्थापनों में होता है।

(ठ) इन प्रयोजन के लिए, नियमित रूप से सफाई व्यवस्था रखी जाएगी ताकि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना सुनिश्चित हो सके।

(ड) जिन यूनिटों में पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव में कच्चा माल रात भर के लिए भंडारित किया जाना है वहाँ उपयुक्त आकार के एक ठंडे कमरे की, जिसका तापमान 1° सी या कम हो, व्यवस्था की जाएगी।

(ढ) जिन यूनिटों में ठंडे कमरे की सुविधा नहीं है, उनमें सामग्री को रात भर पर्याप्त बर्फ में रखा जाएगा।

(ण) सभी प्रक्षालक तथा रोगाणुनाशक अलग-अलग स्टोर किए जाएंगे।

(त) पैकेज वाली सामग्री को भंडार करने की सुविधाएं अलग होंगी।

(थ) प्राग बुझाने वाले यंत्रों के अतिरिक्त, जहरीले पदार्थ जैसे कृत्तकनाश, धूमक, कीटनाश या अन्य पदार्थ, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, पृथक बन्द कमरे में रखे जाएंगे। ऐसे सभी पदार्थों तथा यंत्रों की धरा-उठाई प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाएगी।

(9) जल तथा बर्फ

(क) पेय जल (हानिकारक रसायन तथा कीटाणु से रहित) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा।

(ख) यदि प्रसंस्करण के लिए प्रयोग किया गया जल संरक्षित जल प्रदाय योजना से भिन्न स्रोतों से लिया गया है तो उस की पेयता का प्रमाण-पत्र जो अभिकरण या अभिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य संस्थाओं द्वारा दिया गया हो, प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) यदि बायलर या अन्य सहायक सेवाओं के लिए पीने के अयोग्य जल की पूर्ति की जाती है तो सहायक जल वितरण तंत्र तथा पेय जल बाह्य तंत्र के बीच कोई क्रॉस संबंध नहीं होगा।

(घ) यदि संचय टंकी का प्रयोग किया जाता है तो उसे बाहरी संदूषणों से अच्छी तरह संरक्षित रखा जाएगा और वह पर्याप्त क्षमता वाली होगी।

(ङ) संचय टंकी 6 महीनों में कम से कम एक बार अच्छी तरह से माफ की जाएगी।

(च) प्रसंस्कृत कच्चे माल के प्रत्येक 1 कि०ग्रा० के लिए पेयजल की अपरत कम से कम 12 लिटर होंगी।

(छ) प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त जल में क्लोरीन का उपलब्ध न्यूनतम अंश 3 पी०पी०एम० स्तर पर रखा जाएगा।

(ज) चमकाने (ग्लेजिंग) तथा पुनः चमकाने (रीग्लेजिंग) के लिए प्रयुक्त जल 10 पी०पी०एम० स्तर पर क्लोरीन युक्त किया जाएगा।

(झ) केवल पेय जल से बनी बर्फ ही प्रयोग में लाई जाएगी और यदि बाह्य की बनी बर्फ प्रयोग की जाती है तो यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि वह पेय जल से बनाई गई है तथा दूषित नहीं है।

(ञ) यदि बर्फ तोड़ने की मशीन प्रयुक्त की जाती है तो साफ हाथों में रखी जाएगी।

(10) सफाई संबंधी सुविधाएं तथा नियंत्रण

(i) सफाई

(क) पैक की हुई सामग्री को छोड़कर, सभी वर्तन, ट्रे और मेज की सतह, जो सामग्री के सम्पर्क में आती है, पहले पहल सफाई करने वाले पदार्थों से साफ की जाएगी और अंत में न्यूनतम 50 पी०पी०एम० क्लोरीन वाले जल से साफ की जाएगी।

(ख) प्रसंस्करण हाल दिन का काम शुरू होने से पहले एक बार साफ किया जाएगा और फिर प्रत्येक कार्य-पारी के अंत में भी साफ किया जाएगा।

(ग) इसके अतिरिक्त, सफाई और धुलाई आवश्यकतानुसार बार-बार की जाएगी।

(ii) धुलाई की सुविधा

(क) प्रत्येक संस्करण हाल में प्रवेश द्वारों के पास साबुन तथा हाथ धोने की पर्याप्त सुविधाएं दी जाएगी।

(ख) पांव धोने का प्रबंध भी प्रवेश द्वार के पास किया जाएगा।

(iii) बाह्य मल तथा फालतू जल का निपटारा

(क) प्रसंस्करण परिसर में प्रयुक्त जल का निकालने के लिए जल-निकास की और उसे यूनिट से कम से कम 3 मीटर दूर किसी ताले में बालने की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।

(ख) कारखाने के अन्दर जल-निकास व्यवस्था ठीक से ठकी होगी।

(ग) कूत्तकों के प्रवेश को रोकने के लिए खुली तालियों के, जो दीवारों में से गुजरती है, शिबरा में धातु की जालियां लगाई जाएंगी।

(घ) मल, गन्दे पानी और कूड़े, कचरे के निपटारा की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि वह यूनिट और उसके पास-पड़ोस के लिए, सफाई संबंधी कोई समस्या उत्पन्न न करे।

(ङ) शौचस्थल में से गंदा जल इस ढंग से हटाया जाएगा कि मच्छियां उस तक पहुंच न सकें और यूनिटों को दिया जाने वाला पानी प्रदूषित न हो।

(च) किसी भी ढशा में परिसर में फालतू पानी या बर्षा का जल एकत्रित नहीं होना चाहिए।

(iv) शौच स्थल सुविधाएं

(क) इस सम्बंध में लागू विधि-अपेक्षाओं के अनुसार सैनीटरी प्रकार की पर्याप्त शौच सुविधाएं दी जाएगी।

(ख) शौच स्थल प्रसंस्करण क्षेत्रों से कुछ दूर अलग स्थित होंगे।

(ग) शौच स्थल का दरवाजा अपने आप बन्द होने वाला होगा तथा उसमें हाथ धोने का पात्र तथा साबुन होगा।

(घ) धोने के प्रयोजनों के लिए पेय जल इस्तेमाल किया जाएगा।

(11) कर्मचारियों का स्वास्थ्य तथा स्वच्छता

(क) संयंत्र के प्रबन्धक यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखेंगे कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का, जिसके बारे में यह ज्ञात हो कि वह संक्रामक रोग से पीड़ित है, यूनिट के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति न दी जाए।

(ख) ऐसी बीमारी का पता आसानी से लग सके इसके लिए प्रबन्धक उन कर्मचारियों की, जिन्हें यूनिट के क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी गई है, वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षा कराएगा।

(ग) प्रसंस्करण क्षेत्रों में काम करने वाले सभी व्यक्ति काम करते समय अपनी अत्यधिक सफाई रखेंगे।

(घ) प्रबन्धक प्रसंस्करण तथा पैकिंग क्षेत्रों में काम करने वाले कर्म-चारियों को स्वच्छकृत एप्रान तथा सिर की टोपियां देगा।

(ङ) कर्मचारी हमेशा, प्रत्येक अनुपस्थिति के पश्चात् विशेष रूप से प्रसंस्करण हाल में प्रवेश करने से पूर्व जब भी आवश्यक हो, अपने हाथ तथा पांव पेय-जल तथा साबुन से धोएगा।

(च) परिसर में धूंकना तथा किसी भी रूप में तम्बाकू का प्रयोग निषिद्ध होगा।

(छ) खाने के लिए भ्रम से किसी स्थान की व्यवस्था की जाएगी और अन्य स्थानों पर खाने की मनाही होगी।

(12) वाहन संबंधी सुविधाएं

(क) सब से अच्छा तो यह है कि कच्चा माल और तैयार माल केवल ऊपमारोधी या प्रणीत वाहनों में ले जाया जाए।

(ख) तैयार किया गया माल किसी भी ढशा में गैर-ऊपमारोधी वाहनों में नहीं ले जाया जाएगा।

(13) अभिलेखों का रखा जाना

मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं के प्रसंस्करण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करण कर्ता, परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा निहित एवं आवश्यक अभिलेख तथा रजिस्टर रखेगा, जो अभिकरण के अधिकारियों को, जब और जहाँ आवश्यकता होगी, उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ख) प्रसंस्करण यूनिटों का अनुमोदन

(1) (क) निर्यात के लिए मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं को प्रसंस्करण करने का इच्छुक प्रसंस्करण कर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना, लिखित रूप में, परिषद् द्वारा विहित प्रोफार्मा में, अभिकरण के निकटतम कार्यालय को देगा।

(ख) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, अभिकरण के अधिकारी प्रसंस्करण यूनिट में यह देखने के लिए जाएंगे कि यूनिट में प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं।

(ग) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में वे न्यूनतम सुविधाएं, जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट हैं, विद्यमान हैं तो अभिकरण यूनिट को अनुमोदित करेगा तथा उसे निर्यात के लिए मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं का प्रसंस्करण जारी रखने की अनुमति देगा।

(घ) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में न्यूनतम सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं तो प्रसंस्करण कर्ता को निर्यात के लिए मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं के प्रसंस्करण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) (क) प्रसंस्करण कर्ता को दिया गया अनुमोदन कम से कम 7 दिन का सूचना देने के बाद निम्न कारणों से वापिस लिया जा सकेगा, अर्थात् :—

(i) यदि उपकस्कर, मशीनरी और भण्डारण की सुविधाएं काम करने की अच्छी हालत में न हों।

(ii) यदि यूनिट की स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था संतोषजनक रूप से रखी गई हो।

(iii) यदि प्रति जांच के लिए, लिए गए नमूने निर्धारित मानकों के अनुसार न हों।

(iv) यदि प्रसंस्करण कर्ता ने इन नियमों के उपबन्धों या परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का उल्लंघन किया है या जानबूझकर उल्लंघन करने की कोशिश की है।

(ख) अनुमोदन की ऐसी वापसी प्रसस्करण कर्ता को निश्चित रूप में सूचित की जाएगी।

(3) (i) यदि प्रसस्करणकर्ता अनुमोदन को वापस लेने के निर्णय से व्यथित है तो यह नियम 5 में निविष्ट विशेषज्ञों के पैनल के समक्ष अपील दायर कर सकता है और ऐसे मामलों में उसे प्रसस्करण जारी रखने की अनुमति होगी।

(ii) यदि विशेषज्ञों के उक्त पैनल द्वारा दिया गया निर्णय प्रतिकूल हो तो प्रसस्करण कर्ता को मध्यवर्ती अवधि के दौरान सारी ही प्रसस्कृति सामग्री को निविष्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) जिस यूनिट का अनुमादन वापिस लिया गया है, वह कमियों का दूर करने के पश्चात् अभिकरण में नया अनुमोदन लेने के लिए नए बिन्दु से आरंभ करेगा।

(5) (क) यदि किसी भी समय किसी कारण से उत्पादन की अनु-रूपता को विनिर्देशों के अनुसार बनाए रखने में कठिनाई होती है, तो अभिकरण को सूचना देते हुए निर्यात के प्रसस्करण को रोक दिया जाएगा।

(ख) निर्यात के लिए प्रसस्करण तभी आरम्भ किया जायगा जब वह लिखित रूप से अभिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए।

ग प्रसस्करण

(1) प्रसस्करणकर्ता सक्षम तकनीकी कर्मचारियों के निरीक्षण में केवल अनुमोदित यूनिटों में ही प्रसस्करण करेगा।

(2) (क) प्रसस्करण यूनिट में आने वाली कच्ची सामग्री का निरीक्षण उसकी मात्रा, क्वालिटी और विज्ञातीय पदार्थ के लिए किया जाएगा और संप्रेषकों को समय-समय पर परिपद द्वारा विहित रीति से अभिलिखित किया जाएगा।

(ख) यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रसस्करण के लिए केवल ताजी और अच्छी कच्ची सामग्री ही प्रयोग की जाती है।

(3) कच्चे माल का चयन और उपरवर्ती प्रसस्करण, पैकिंग और भंडारण, निर्यात होने तक समय-समय पर अभिकरण के अधिकारियों द्वारा किए गए निदेशों के अनुसार सक्षम तकनीकी कर्मचारियों के पर्यवेक्षण में जारी रहेगा।

(4) (क) पूर्वोक्त नियम, जब भी आवश्यक हो, अभिकरण के अधिकारियों द्वारा और भागे जांच के अधीन रहेगी।

(ख) अभिकरण के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित माल प्रसस्कर या पैकिंग के किसी भी प्रक्रम पर यथास्थिति प्रसस्करण परिमर से हटा दिया जायगा/कमियां दूर कर दी जाएंगी।

(ग) अस्वीकृत माल का निपटान अभिकरण के समाधानप्रद ढंग से किया जायगा।

(5) विवाद की दशा में संबंधित कच्चा माल या तो ठीक ढंग से बर्फ में रखा जायगा या अलग से पहचान टैग या चिह्न के साथ प्रसस्कृत किया जायगा, और अन्तिम निपटान के लिए अलग रखा जायगा। इस निपटान का विनिश्चय अभिकरण के अधिकारियों के एक पैनल द्वारा निश्चित किया जाएगा।

(घ) निरीक्षण की प्रक्रिया:— (1) (क) इन नियमों के अधीन निरीक्षण योजना के लिए एक दिन का उत्पादन एक नियंत्रण यूनिट होगा।

(ख) एक नियंत्रण यूनिट में, वितरण के स्त्रोतों पर निर्भर करते हुए कई उप यूनिटें हो सकती हैं।

(ग) नमूने, परिपद द्वारा अधिकृत अनुदेशों के अनुसार, कच्चे माल के प्रसस्करण के विभिन्न चरणों में और अन्तिम उत्पाद में से लिए जाएंगे।

(घ) वे लॉट, जो अधिकृत मानकों के अनुरूप होंगे, अनुमोदित लॉट माने जाएंगे।

(2) मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं के परेषण का निर्यात करने का दृष्टिकोण निर्यात कर्ता, परिपद द्वारा विहित प्रोफार्मा में, अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा और ऐसी सूचना के साथ इस आशय का घोषणा पत्र देगा कि मछली तथा मछली को बनी वस्तुओं का परेषण का प्रसस्करण, इस संबंध में विहित प्रसस्करण के दौरान क्वालिटी नियंत्रण उपायों का उपयोग करके किया गया है और यह परेषण अनुमोदित लॉट में से लिया गया है।

(3) ऐसी सूचना प्रसस्करण परिमर से परेषण के पोतलदान के लिए भेजे जाने की तारीख से कम से 3 कार्य दिवस पूर्व अभिकरण के कार्यालय में पहुंचेगी।

(4) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, अभिकरण सामान्यतः केवल जैव-सांत्विक परीक्षणों के लिए नमूने लेगा और यदि अभिकरण का यह समाधान है कि निर्यात किया जाने वाला परेषण अधिसूचित मानकों के अनुरूप है और यदि खंड ग के उप-खंड (4) के अनुसार अभिलिखित नियमित जांच के परिणाम सतोषजनक हैं तो वह ऐसी सूचना प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस के भीतर, परेषण को निर्यात योग्य घोषित करने हुए निर्यातकर्ता को प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(5) (क) ऐसी दशा में जब अभिलिखित जांच पड़ताल के परिणाम के आधार पर वैसा करना आवश्यक हो या यदि अभिकरण यह अनुभव करे कि और विस्तृत जांच आवश्यक है तो वैज्ञानिक संबंधी परीक्षण सहित, विस्तृत परीक्षण के लिए परेषण में से और नमूने लिए जाएंगे।

(ख) ऐसी दशाओं में, निर्यात-वार्य होने का प्रमाण पत्र केवल परीक्षण के सतोषजनक परिणाम प्राप्त होने के पश्चात् ही दिया जायगा।

(6) जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है, वहां वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने से इकार करेगा और ऐसी अस्वीकृति की सूचना, उसके कारणी मूलक परीक्षणों की समाप्ति के तुरंत पश्चात् लिखित रूप में निर्यात कर्ता को देगा।

(7) नियंत्रण यूनिटों और उप यूनिटों की, जो विनिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं, अस्वीकृति तथा निपटान की पद्धति में सर्वधित सूचना देते हुए, पृथक अभिलेख रखे जायेंगे।

(8) (क) निरीक्षण के प्रयोजन के लिए, अभिकरण अधिकारी की सुसज्जत अभिलेखों और परिमर तक जहां मछली और मछली की वस्तुओं का प्रसस्करण पैकिंग तथा भंडारण से किया जाता है, पहुंच होगी।

(ख) प्रसस्करण कर्ता प्रसस्करण क्षेत्र के पार्श्व में, आवश्यक सुविधाओं सहित, एक पृथक निरीक्षण कक्ष की व्यवस्था करेगा।

4 निरीक्षण फीस

प्रत्येक परेषण के लिए, न्यूनतम 30 रुपये के अधीन रहते हुए, निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को निम्नलिखित दरों पर फीस, निरीक्षण फीस के रूप में, दी जाएगी, अर्थात्:—

(1) प्रशोधित झींगे—सभी प्रकार की	12 पैसे प्रति कि०ग्रा० या उसके भाग के लिए	
(2) प्रशोधित झींगे मछली	.40	--वही--
(3) प्रशोधित पामफिट	.15	--वही--
(4) प्रशोधित कटल फीश या स्क्रीड्स	15	--वही--

5 अपील

(i) नियम 3 के खंड ख के उप खंड (1) के अधीन अपनी यूनिट के लिए अनुमोदन देने से या नियम 3 के खंड घ के उपखंड (6) के अधीन निर्यातयोग्यता का, प्रमाण पत्र जारी करने से अभिकरण द्वारा इकार कर दिए जाने से,

(ii) नियम 3 के खंड ख के उप खंड (2) के अधीन यूनिट को दिए गए अनुमादन को वापिस लेने के अभिकरण के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके द्वारा ऐसे इकार की सूचना प्राप्त होने के

दस दिनों के भीतर हम प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल को जिसमें कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे अपील कर सकेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल के कुल सदस्यों के कम से कम दो विहार्ड सदस्य गैर-सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

(4) अपील, प्राप्ति होने के 15 दिन के भीतर, निर्यात दी जाएगी।

[म० 6(21)/76-नि०नि० तथा नि०प०]

सी०बी० कूहरेशी, उप निदेशक

New Delhi, the 31st December, 1977

S.O.4008.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the Export of fish and fish products (Inspection) Rules, 1964 and the Export of Frozen Lobster Tails (Inspection) Rules, 1971, except as respects things done or omitted to be done, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement :

- (1) These Rules may be called the "Export of Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1977.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);
- (b) "agency" means any of the agencies established or recognised under section 7 of the Act;
- (c) "Fish and Fishery Products" means :—
 - I. all types of frozen prawns (shrimps) :—
 - (i) Whole —Head and shell-on
 - (ii) Headless —Head removed, shell-on
 - (iii) Fantail round —Head and shell removed except on last segment and tail
 - (iv) Fantail deveined —As in (iii) above, but the alimentary canal removed
 - (v) Fantail butterfly —As in (iv) above, but split open and arranged in required pattern
 - (vi) Peeled, raw peeled or peeled undeveined —Head and shell removed completely
 - (vii) Peeled and deveined —As in (vi) above, but the alimentary canal also removed
 - (viii) Cooked and peeled —As in (vi) above, but after cooking
 - (ix) Peeled and cooked —As in (vi) above, but cooked
 - (x) Peeled, deveined and cooked —As in (vii) above, but also cooked
 - (xi) Whole, cooked —As in (i) above, but also cooked;
 - II. All types of frozen lobster obtained from—
 - (i) Rock lobster
 - (1) *Panulirus homarus*
 - (2) *Panulirus ornatus*
 - (3) *Panulirus polvohaous*

- (ii) Deep sea lobsters —*Peurulus sewelli*
- (iii) Sand lobsters —*Thunnus sp.*

III. All types of frozen pomfrets like—

- (i) *Pampus argenteus* } White pomfrets
- (ii) *Stremateus Sinensis* }
- (iii) *Parastomateus Niger* —Brown pomfret
- (iv) *Pampus Chinensis* —Black pomfret or Chinese pomfret

IV. All types of frozen cuttle fish and squids processed from :—

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> (i) <i>Sepia Pharaonis</i> (ii) <i>Sepia Aculeata</i> (iii) <i>Sepia Thurstoni</i> (iv) <i>Sepia Brevinana</i> (v) <i>Sepiella Inermis</i> (vi) <i>Sepiella Ldiolus</i> (vii) <i>Symplectoteuthis sp.</i> | } In the case of cuttle fish |
| and | |
| <ol style="list-style-type: none"> (i) <i>Loligo Hardwicki</i> (ii) <i>Loligo Indica</i> (iii) <i>Loligo Affinis</i> (iv) <i>Sepioteuthis</i> Arctipinnis (v) <i>Loligo Duvauceli</i> (vi) <i>Euprymna Stnodectyla</i> (vii) <i>Lololus Investigatoris</i> | } In the case of squids; |

- (d) "Standard specifications" means the specifications of frozen prawns (shrimps), frozen lobsters, frozen pomfrets and frozen cuttle fish and squids as laid down in the Annexure to the order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 4008, dated the 31-12-1977.

3. Quality Control

A. Requirements of processing units

Only those of the processing units approved by the agency shall be eligible for processing Fish and Fishery Products for export and a unit to qualify for approval shall have the minimum facilities as specified below :—

(1) Surroundings, construction and layout :

(a) The surroundings of the processing unit shall not have any swamps, dumps or animal housing nearby which might pose any sanitary problems.

(b) All the immediate approaches of the processing area shall be concreted or tarred or turfed to prevent wind-blown dust.

(c) The processing unit shall be housed in a building of permanent nature, affording sufficient protection from normal climatic hazards like wind-blown dust and rain.

(d) The layout of different sections shall be arranged in such a way as to facilitate the smooth flow of work and to prevent possible contamination from preprocessing section.

(2) Processing areas :

(a) The area in which the raw material is received and stored shall be so separated from the area in which the final product preparation or packing is conducted so as to preclude contamination of the finished products.

(b) Areas and compartments used for the storage of edible products shall be separate and distinct from those used for inedible materials.

(c) The material handling areas shall be completely separated from the area used for residential purposes.

(3) Ceiling, wall and floor :

(a) The ceiling of the room, where the material is either processed or stored, shall be free from crevices and open joints and lend itself for easy cleaning.

(b) The ceiling shall not offer any facility for rodent harbourages.

(c) The walls of the processing area shall be smooth and free from pits and cracks and shall be washable upto a height of min. 1.3 metres.

(d) The floor shall be of impermiabile and non-corroding material, and shall have sufficient sloping to drain away all the waste water.

(e) The floor and wall junctions shall be rounded off to facilitate easy cleaning.

(4) Fly proofing, vermin and animal control :

(a) The processing area shall be provided with effective fly-proofing arrangements.

(b) Measures shall be adopted to protect against the entry of other insects, rodents, birds, cats, dogs and the like into the processing areas.

(5) Lighting and ventilation :

(a) All the working areas shall be well lighted.

(b) Light bulbs and fixtures suspended over the product or at any stage of its preparation shall be of safety type or otherwise protected to prevent contamination in case of breakage.

(c) There shall be adequate facilities for natural or mechanical ventilation system to provide fresh air, remove undesirable odours, steam and smoke and prevent condensation in rooms where work is performed.

(6) Working tables and utensils :

(a) The tables used for processing work shall be of non-corrodible, non-reacting material other than wood.

(b) The processing tables shall be constructed and installed in such a way that the areas underneath and around are accessible to easy cleaning.

(c) The table tops shall be of stainless steel, aluminium, or rustfree G.I. Sheets, and shall be smooth and free from pits and crevices.

(d) The arrangement of working tables shall be such that smooth flow of work is ensured.

(e) All receptacles like trays, tanks, vats and utensils used for the processing shall also be of non-corrodible material other than wood, and shall also have smooth surfaces free from crevices.

(f) Enamelled utensils shall not be used.

(g) Wire mesh receptacles may be used only for handling shell-on crustacea.

(h) Bamboo baskets shall not be used for handling the material.

(i) The equipments and utensils used for inedible and contaminated material shall be separately identifiable by a mark or shape or colour so that these are not used for handling edible products.

(j) Waste material shall be frequently removed from the working areas during processing operation, and adequate waste receptacles shall be provided for this purpose.

(7) Machinery :

(a) The freezing capacity shall be adequate to meet the production in peak season.

(b) The type of freezing employed shall be specific to the nature of the product and type of pack.

(c) The materials shall be quick frozen.

(d) In the case of block freezing, the material shall attain a temperature around -40°C within the period of 3 hours.

(e) The freezing equipments shall be fitted with gauges to show the temperature and pressure.

(f) All cooking operations shall be carried out by steam and autoclaves or retorts shall be provided with pressure gauge or thermometer.

(8) Cold storage and warehousing :

(a) The location and design of the cold storage should be such that it is integrated into the general layout of the whole establishment and its operation incorporated into the flow pattern of the overall operation.

(b) Every freezing unit shall have cold storage of adequate capacity.

(c) The ideal temperature of the cold storage shall be -18°C or less, preferably fitted with automatic temperature recording device.

(d) In the absence of continuous recording thermometer the temperature of the cold storage shall be measured atleast every 4 hours and suitable records maintained.

(e) The cold storage shall be well lighted and shall have suitable arrangements on the floors and sides to facilitate free circulation of air.

(f) The entry into the cold storage should be so designed that on opening the entry door, the temperature shall not rise appreciably, as otherwise it would affect the stored product.

(g) An ante-room of suitable size shall invariably be provided.

(h) The cooling surfaces of the cold storage should be regularly defrosted in order to avoid excessive build up of ice or frost, which could seriously affect the efficiency of the cooling system.

(i) During defrosting operation, care shall be taken to prevent any frost, ice or melt water falling on the stored product.

(j) There shall be an efficient alarm system to render timely help to persons trapped inside.

(k) The cold storage shall be subject to the same sanitary requirements as in other material handling establishments.

(l) For this purpose, a regular cleaning schedule shall be maintained to ensure good hygienic conditions.

(m) units where the raw material has to be stored overnight for want of adequate processing facilities, a chill room of suitable size, maintained at a temperature of 1°C or less, shall be provided.

(n) In units where chill room facility is not available, the material shall be permitted, to be stored overnight, adequately iced.

(o) All detergents and disinfectants shall be stored separately.

(p) There shall be separate facility for storing packaging materials.

(q) Toxic substances such as rodenticides, fumigants, insecticides or other substances injurious to health, except fire fighting equipments, shall be kept in a separate locked room and all these substances and equipments shall be handled by trained personnel only.

(9) Water and Ice :

(a) There shall be plentiful supply of potable water (free from harmful chemical and bacteria).

(b) If the water used for processing is from sources other than a protected water supply scheme, a certificate of potability of the same from the agency or other approved institutions by the agency shall be produced.

(c) If non-potable water is supplied for boiler and other auxiliary services, there shall be no cross-connection between the auxiliary water system and the system carrying potable water.

(d) The storage tanks, if used, shall be sufficiently protected from extraneous contamination, and shall be of sufficient capacity.

(e) The storage tanks shall be properly cleaned, atleast once in 6 months.

(f) The consumption of potable water shall not be less than 12 lts. for every kilogram of raw material processed.

(g) The minimum available chlorine content in water used for processing shall be maintained at 3 ppm. level.

(h) The water used for glazing and reglazing shall be chlorinated to a level of 10 ppm.

(i) Ice made from potable water only shall be used and if ice from external sources is used, it shall be ensured that the same is made from potable water and is not contaminated.

(j) Ice crushing machines, if used, shall be kept in good sanitary conditions.

(10) Sanitary facilities and control :

(i) Cleaning

(a) All the utensils, trays and table surfaces, which come in contact with the material, except packaged material, shall be washed initially with a cleansing agent, and finally with water having a minimum concentration of 50 ppm chlorine.

(b) The processing hall shall be cleaned before the day's work starts and then at the end of each working shift.

(c) In addition, the cleaning and washing shall be done as frequently as necessary.

(ii) Washing facility

(a) Soap and adequate hand washing facilities shall be provided in each processing hall near the entrances.

(b) Arrangements to sanitise the feet shall also be made near the entrances.

(iii) Sewage and waste disposal

(a) There shall be adequate drainage facilities for carrying away water used in the processing premises and to discharge it into a channel atleast 3 metres from the unit.

(b) The drainage system inside the factory shall be properly covered.

(c) The openings of open drains, which pass through walls, shall be fitted with metal grills to prevent the entry of rodents.

(d) The arrangements for disposal of sewage, waste water and offal shall be such that it shall not cause any sanitary problem to the unit and the neighbourhood.

(e) The sewage from the toilet shall be disposed of in such a manner that the water shall not be accessible to flies and the unit's water supply not contaminated.

(f) On no account there shall be accumulation of water including waste or rain water in the premises.

(iv) Toilet facility

(a) Adequate toilet facilities of sanitary type shall be provided as per the legal requirements applicable in this regard.

(b) The toilets shall be located well isolated from the processing area.

(c) The toilets shall be provided with self-closing doors, and with wash basin and soap.

(d) Potable water shall be used for washing purposes.

(11) Personnel health and hygiene :

(a) Plant management shall take care to ensure that no person, while known to be affected with a communicable disease, is permitted to work in any area of the unit.

(b) In order to facilitate the detection of such disease, the management shall conduct atleast yearly medical examination of the personnel permitted to work in any area of the unit.

(c) All persons working in the processing area shall maintain a high degree of personal cleanliness while on duty.

(d) The management shall provide sanitised aprons and head gears to the employees working in the processing and packing areas.

(e) The workers shall wash their hands and feet with potable water and soap as often as necessary, and specially before entering the processing hall after each absence.

(f) Spitting and use of tobacco in any form shall be prohibited in the processing premises.

(g) A separate eating place shall be provided, and eating at other places shall be prohibited.

(12) Transportation facilities :

(a) It is ideal that the raw material as also the finished product are transported only in insulated or refrigerated vehicles.

(b) Under no circumstances finished product shall be carried in non-insulated vehicles.

(13) Maintenance of records :

Necessary registers and records, as prescribed by the Council from time to time, shall be maintained by the processor in order to ensure effective control on the processing of fish and fishery products, and these shall be made available to the agency officers as and when required.

B. Approval of processing units.

(1) (a) A processor intending to process fish and fishery products for export shall inform his intention to do so in writing, in the proforma prescribed by the Council, to the nearest office of the agency.

(b) On receipt of such information, the agency officers shall visit the processing unit in order to adjudge the facilities for processing available in the unit.

(c) If the unit is found to have the minimum facilities as specified in clause (A) the agency shall approve the unit and permit it to carry out processing of fish and fishery product for export.

(d) If the unit is found not to have the minimum facilities the processor shall not be allowed to process fish and fishery products for export.

(2) (a) The approval accorded may be withdrawn in respect of a processor for the following reasons, after giving a notice of minimum period of 7 days namely :—

(i) If the equipments, machinery and storage facilities are not in good working condition;

(ii) if the sanitary and hygienic condition of the unit is not maintained satisfactorily;

(iii) if samples drawn for counterchecks fail to meet the laid down standards;

(iv) if the processor has violated or deliberately attempted to violate the provisions of these rules or instructions issued by the Council from time to time.

(b) Such withdrawal of approval shall be intimated in writing to the processor.

(3) (i) Any processor aggrieved by the decision to withdraw approval may file an appeal before the panel of Experts referred to in Rule 5 and in such case he shall be allowed to continue processing.

(ii) In the event of an adverse decision by the said panel of experts, the processor shall not be allowed to export the entire material processed during the intervening period.

(4) A unit, whose approval has been withdrawn, may, after rectifying the defects make a fresh application to the agency for getting fresh approval.

(5) (a) If at any time there is any difficulty in maintaining the conformity of the products to the specifications for any reason the processing for export shall be suspended under intimation to the agency.

(b) The processing for export shall be resumed only after the same is approved by the agency in writing.

C. Processing

(1) The processor shall carry out processing only in approved units under the supervision of the competent technical personnel.

(2) (a) The raw material arriving in the processing unit shall be inspected for its quantity, quality and foreign matter and the observations recorded in the manner prescribed by the Council from time to time.

(b) It shall be ensured that only fresh and wholesome raw materials are used for processing.

(3) The selection of raw materials and its subsequent processing packing and storage, till export shall be carried out under the supervision of competent technical personnel as per directives given by the agency officers from time to time.

(4) (a) The aforesaid operations shall be subject to further check by the agency officers as often as found necessary.

(b) The material at any stage of processing or packing, not approved by the agency officers, shall be removed from the processing premises or defects rectified, as the case may be.

(c) The rejected material shall be disposed of in a way satisfactory to the agency.

(5) In case of dispute, the concerned raw materials shall be either kept adequately iced, or processed with a separate identity tag or mark, and kept separately for final disposal, which shall be decided by a panel of officers of the agency.

D. Procedure of Inspection

(1) (a) For the purpose of inspection under these rules, a day's production shall constitute a control unit. (b) A control unit may have more sub-units depending upon the sources of supply. (c) Samples shall be drawn from raw materials, different processing stages and the final product in accordance with the instructions laid down by the Council. (d) Those of the lots which meet the laid down standards shall be treated as approved lots.

(2) An exporter intending to export a consignment of fish and fishery products shall give intimation to the agency in writing, in the proforma prescribed by the Council, and submit along with such intimation a declaration to the effect that the consignment of fish and fishery products has been processed exercising the in-process quality control measures as prescribed in this regard and is from approved lot.

(3) Such intimation shall reach the agency office not less than 3 working days prior to the date of despatch of the consignment from the processing premises for shipment.

(4) On receipt of such intimation, the agency shall normally draw samples for organoleptic tests only, and if the

agency is satisfied that the consignment to be exported complies with the notified standards, and if the results of recorded regular checks conducted as per sub-clause (4) of Clause (c) are satisfactory, it shall, within 3 working days of receipt of such intimation, issue a certificate to the exporter declaring the consignment exportworthy.

(5) (a) In case the results of the recorded checks so warrant, or if the agency feels that further detailed checks are necessary, additional samples shall be drawn from the consignment for detailed testing including bacteriology.

(b) In such cases, the certificate of exportworthiness shall be issued only after satisfactory completion of the tests.

(6) Where the agency is not so satisfied, it shall refuse to issue such certificate and communicate such refusal in writing to the exporter, alongwith the reasons therefore soon after the completion of the tests.

(7) A separate record shall be maintained giving information relating to the rejection and mode of disposal of the control units or sub-units which do not conform to the specifications.

(8) (a) For the purpose of inspection, the agency officer shall have access to the relevant records and premises where processing, packing and storage of fish and fishery products are carried out.

(b) The processor shall provide a separate inspection room with necessary facilities, adjacent to the processing area.

4. Inspection fee :

Subject to a minimum of Rs. 30/- for each consignment a fee at the following rates shall be paid by the exporters to the agency as inspection fee namely :—

(1) Frozen Prawns — all type :— 12 Paise Per Kg or Part thereof.

(2) Frozen Lobsters :— 40 —do —

(3) Frozen Pomfrets :— 15 —do —

(4) Frozen Cuttle fish and squids :— 15 —do —

5. Appeal

(1) Any person aggrieved by :

(i) the refusal of the agency to accord approval for his unit under sub-clause (1) of Clause B of Rule 3 or to issue a certificate of exportworthiness under sub-clause (6) of Clause D of rule 3,

(ii) the decision of the agency to withdraw the approval accorded to a unit under sub-clause (2) of clause B of rule 3,

may, within 10 days of the receipt of the communication of such refusal by it, prefer an appeal to a Panel of Experts consisting of not less than three, but not more than seven persons, appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two-thirds of the total membership of the panel of Experts shall consist of non-officials.

(3) The quorum of the Panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

[No. 6(21)/76-EI & EP]

C. B. KUKRETI, Deputy Director

व्यापार मंत्रालय

(मुख्य निर्यातक, आयात निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर 1977

का० प्रा० 4009.—सर्वश्री सालगोयकार इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड फ्रान्सिसको लुइस गोमस रोड, बाम्को-डी-गामा गोआ को, अनुज्ञेय किस्म के और मूल्य सूची के अनुसार मिट्टी निकालने और निर्माण कार्य करने वाली मशीनों के लिए फालतू पुर्जों का आयात करने के लिए 6,50,000 रुपए का लाइसेंस सं० पी० (एफ) 2027133 दिनांक 15-5-76 प्रदान किया गया था।

2 उन्होंने ऊपर उल्लिखित लाइसेंस की सीमा शुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि के लिए इस आधार पर निवेदन किया है कि, मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति उनसे खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंसधारी ने आगे सूचना दी है कि लाइसेंस सीमा शुल्क मघन, बम्बई में पंजीकृत करवाया गया था और उसमें 1,89,462 रुपए की अप्रयुक्त धनराशि शेष थी।

3 अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। से इस बात से संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस सं० पी०/2027133 दिनांक 15-5-76 की मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति खो गई या अस्थानस्थ हो गई है और इसलिए एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क निकासी प्रति रद्द करने का आदेश देता हूं।

उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि भ्रमण से जारी की जा रही है।

[संख्या 3/79/75-76/एम०एल० II/178]

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

New Delhi

ORDER

New Delhi, the 13th December, 1977

S.O. 4009.—M/s. Salgaocar Engineers Pvt. Ltd. Francisco Luis Gomes Road Vasco-Da-Cama were granted import licence No. P/F/2027133 dated 15-5-1976 for Rs. 6,50,000 for the import of permissible types of spares parts of earthmoving and construction machinery and also as per list attached.

2. They have requested for the issue of duplicate Customs Purposes Copy of the above said licence on the grounds that the original Customs Purposes copy has been lost or misplaced by them. It has been further reported by the licensee that the licence was registered at Custom House Bombay and has an unutilised balance of Rs. 1,89,462 only.

3. In support of their contention, the applicants have filed an affidavit. I am satisfied that the original Customs Purposes Copy of import licence No. P/F/2027133 dated 15-5-76 has been lost or misplaced and therefore hereby order cancellation of original Custom Purposes copy of above licence.

The Duplicate Customs Purposes Copy of the above licence is being issued separately.

[File No. 3/79/75-76/MI.II/178]

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1977

रद्द करने का आदेश

का० प्रा० 4010.—सर्वश्री पी० बलाल एंड कंपनी, 132 डा० ऐसी बेसेंट रोड, बम्बई को मशीन के औजारों का आयात करने के लिए

लागत-बिमा-भाडा मूल्य 25,00,000 रुपए (पच्चीस लाख रुपए मात्र) के लिए एक आयात सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं० पी०/जे०/3053253/एन/एम एन/57/एच/41-42, दिनांक 24-10-75 जारी होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए वैध प्रदान किया गया था। पार्टी ने अब पूर्वोक्त आयात सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति इनसे खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। पार्टी ने आयात व्यापार नियंत्रण नियमों के अनुसार अपेक्षित शपथ-पत्र दाखिल किया है जिसके अनुसार पूर्वोक्त सीमा-शुल्क निकासी परमिट सीमा शुल्क कार्यालय बम्बई में पंजीकृत कराया गया था और आंशिक रूप से उपयोग में लाया गया था और उस पर 4,26,075 रुपए की धनराशि का उपयोग करना शेष है। शपथ-पत्र के अंतर्गत इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि यदि बाद में सीमा शुल्क निकासी परमिट मिल जाएगा अथवा वा जायगा तो वह लाइसेंस प्राधिकारी को वापस लौटा दिया जाएगा।

मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट खो गया/अस्थानस्थ हो गया है तथा निवेश देता हूं कि आवेदक को इस की अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए। मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट एमद् द्वारा रद्द किया जाता है।

[संख्या 1/7/75-76-एम० एल० I/863]

एम० जी० गोम्बर, उप-मुख्य नियंत्रक,
कुते मुख्य नियंत्रक

New Delhi, the 14th December, 1977

CANCELLATION ORDER

S.O. 4010.—M/s. P. Dalal and Company, 132 Dr. Annre Besant Road, Bombay were granted an import CCP No. P/I/3053253/N/MN/57/H 41-42 dated 24-10-75 for a C.I.F. value of Rs. 25,00,000/- (Rupees Twenty five lakh only) for import of Machine Tools valid for six months from the date of issue. Now the party have applied for grant of a Duplicate Copy for the aforesaid import CCP on the ground that the original one has been lost/misplaced by them. The party have furnished necessary affidavit as per I.T.C. Rules according to which the aforesaid C.C.P. was registered with Bombay Customs House and was utilised partly and the balance against the C.C.P. is Rs. 4,26,075. It has also been incorporated in the affidavit that if the said C.C.P. is traced or found later on, it will be returned to the issuing authority.

I am satisfied that the original C.C.P. has been lost/misplaced and direct that a Duplicate copy of the CCP should be issued to the applicant. The original C.C.P. is hereby cancelled.

[File No. 1/7/75-76/ML-I/863]

M. G. GOMBER, Dy. Chief Controller
for Chief Controller

जागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1977

का० प्रा० 4001—केन्द्रीय सरकार, अधिम संविदा (नियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन सुरेन्द्रनगरकाटन आयल एंड आयलसीड्स एसोसियेशन लिमिटेड, सुरेन्द्रनगर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये आवेदन पर शायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त एसोसियेशन को कपास की अधिम संविदाओं के बारे में 11 दिसम्बर, 1977 से 10 दिसम्बर, 1978 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अनिश्चित कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है।

2. एनडू द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त एसोसियेशन ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जायें।

[मिशन सं० 12(22)/आई टी/77]

बी० श्रीनिवासन, उप-सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

New Delhi, the 8th December, 1977

S.O. 4011.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under section 5 of

the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Surendranagar Cotton Oil and Oilseeds Association Limited, Surendranagar, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of one year from the 11th December, 1977 to the 10th December, 1978 (both days inclusive), in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions, as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[File No. 12(22)/IT/77]

V. SRINIVASAN, Dy. Secy.

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर, 1977

क्र०आ० 4012.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के श्वोरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे वापस लिए गए हैं और अब उन्हें रद्द माना जाए

अनुसूची

क्रम सं०	रद्द किए गए भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	राजपत्र अधिसूचना की एसओ संख्या और तिथि जिसमें भारतीय मानक के निर्धारण की सूचना छपी थी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 7612-1974 ज्वाला प्रतिरोधी और ताप प्रतिरोधी सूटों की कार्यपरक अपेक्षाएं	भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1977-10-08 में प्रकाशित एसओ 3081 दिनांक 1977-09-20	वास्तविक कार्य में यह भारतीय मानक व्यावहारिक नहीं पाया गया इसलिए वापस ले लिया गया।

[सं० सी एम डी/13 : 7]

आई० एम० बेंकटेश्वरन, अपर महानिदेशक

(Indian Standards Institution)

New Delhi, the 14th December, 1977

S.O. 4012.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, it is, hereby, notified that the Indian Standard(s) particulars of which is mentioned in the Schedule given hereafter, has been cancelled and stands withdrawn :

SCHEDULE

Sl. No. & Title of the Indian Standard Cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was Notified	Remarks
(1)	(2)	(3)
1. IS : 7612-1974 Functional requirements for flame resistant and heat resistant suits.	S.O. 3081 dated 1977-09-20 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1977-10-08.	In practice, this Indian Standard has not been found to be workable. Hence withdrawn.

[No. CMD/13 : 7]

Y. S. VENKATESWARAN, Addl. Director General

पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1977

क्रा०मा० 4013—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की क्रमण अधिसूचना तथा सुद्धि पत्र क्रा०मा०सं० 4816 तारीख 8-1-77 क्रा०मा०सं० 2470 तारीख 6-8-77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देनी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में बहिष्ठ होने के बजाय इंडियन अयल कारपोरेशन लिमि० में सभी धारों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

तालिका : मेहसाना	जिला : मेहसाना	राज्य : गुजरात		
गांव	सर्वेक्षण सं०	क्षेत्रफल		
		हे०	ए०	वर्ग मीटर
1	2	3		
रामपुरा	493/1	0	13	95
	494/1	0	12	00
	498	0	01	00
	497	0	01	80
	496	0	04	40
	495	0	08	55
	518	0	21	25
	519	0	14	96
	520	0	16	49
	521	0	20	68
	522	0	22	89
	523	0	03	030
	524	0	11	74
	527	0	10	89
	528	0	15	67
नडासा	1169	0	23	27
	1168	0	22	26
पलाज (जीवापुरा)	194	0	00	02
	(1175)			
	193	0	11	13
	(1174)			

1	2	3	
पलाज जीवापुरा-समाप्त	192	9	14
(1173)			16
191	0	04	05
(1172)			
207	0	28	33
(1188)	0	12	64
208			
(1189)			
210 ए	0	30	35
(1191 पी)			
210 बी	0	05	08
(1191 पी)			
211	0	40	47
(1192)			
166	0	20	23
(1147)			
167	0	26	30
(1148)			
168	0	68	80
(1149)			
169	0	04	05
(1150)			
150	0	40	47
(1131)			
149	0	38	45
(1130)			
127	0	43	50
(1108)			
126	0	20	23
(1107)			
125	0	50	59
(1106)			
123	0	01	55
(1104)			

[सं० 12020/9/76-प्रोडक्शन]

टी० पी० सुबह्नमनियन, प्रवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 9th December, 1977

S.O. 4013.—Whereas by a notification and corrigendum of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum S.O. No. 4816 dated 8-1-77 and S.O. No. 2470 dt. 6-8-77 respectively under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines :

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act. submitted report to the Government :

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification :

Now therefore in exercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines :

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on the date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Taluka : Mehsana District : Mehsana State : Gujarat

Village	Survey No.	Extent		
		H	A	Sq. M.
1	2	3		
Rampura	493/1	0	13	95
	494/1	0	12	00
	498	0	01	00
	497	0	01	80
	496	0	04	40
	495	0	08	55
	518	0	21	25
	519	0	14	96
	520	0	16	49
	521	0	20	68
	522	0	22	89
	523	0	03	30
	524	0	11	74
	527	0	10	89
	528	0	15	67
Nadasa	1169	0	23	27
	1168	0	22	26
Palaj (Jivapura)	194	0	00	02
	(1175)			
	193	0	11	13
	(1174)			
	192			
	(1173)	0	14	16
	191			
	(1172)	0	04	05
	207			
	(1188)	0	28	33
	208			
	(1189)	0	12	64
	210 A			
	(1191 P)	0	30	35
	210 B			
	(1191 P)	0	05	06
	211			
	(1192)	0	40	47
	166			
	(1147)	0	20	23
	167			
	(1148)	0	26	30
	168			
	(1149)	0	68	80
	169			
	(1150)	0	04	05
	150			
	(1131)	0	40	47

1	2	3
Palaj (Jivapura) (Contd)	149	
	(1130)	0 38 45
	127	
	(1108)	0 43 50
	126	
	(1107)	0 20 23
	125	
	(1106)	0 50 59
	123	
	(1104)	0 01 55

[No. 12020/9/76-Prod].

T. P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1977

का०घ्रा० 4014.—यतः भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का 48) की धारा 10 की उपधारा (2) के अनुसरण में भारतीय नर्सिंग परिषद् ने 7 सितम्बर, 1976 को हुई एक बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा यह घोषित किया है कि उसमें विनिर्दिष्ट ग्रहता की उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक मान्यता प्राप्त ग्रहता समझा जाएगा।

और यतः उक्त प्रस्ताव की उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में यथाविहित भारतीय नर्सिंग परिषद् की 6 जनवरी, 1977 की अधिसूचना संख्या 11-1/76-प्रा० एन० सी० के साथ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की अनुमूची में एतद्वारा प्राये और संशोधन करती है ताकि उसे उक्त घोषणा के अनुरूप रखा जाए; अर्थात्

उक्त अधिनियम की अनुमूची के भाग 1 में "ए-जनरल नर्सिंग" शीर्ष के अन्तर्गत

(क) प्रविष्टि 50 और 52 को हटा दिया जाए;

(ख) प्रविष्टि 51 को 50 कर लिया जाए।

[संख्या बी 14015/2/77-पी०एम०एस०]

वि० कु० अभिहोत्री, प्रवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 5th December, 1977

S.O. 4014.—Whereas the Indian Nursing Council has, by a resolution passed at a meeting held on the 7th September, 1976, in pursuance of sub-section (2) of section 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947), declared that the qualification specified therein shall be a recognised qualification for the purpose of the said Act;

And whereas the said resolution has been published in the Official Gazette with the notification of the Indian Nursing Council No. 11-1/76-INC, dated the 6th January, 1977, as required by sub-section (1) of section 15 of the said Act;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 15 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Schedule to the said

Act so as to bring it into accord with the said declaration, namely :—

In the Schedule to the said Act, in part I, under the heading "A-General Nursing",

(a) entry 50 and 52 shall be omitted; and

(b) entry 51 shall be re-numbered as 50.

[No. V 14015/2/77-PMS]

V. K. AGNIHOTRY, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1977

का०घा० 4015—विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का 21 नवम्बर, 1977 से प्रगले आदेश होने तक गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. श्री एम० एन० राय,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
2. श्री एच० धार० कुलकर्णी,
सदस्य (माप),
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
3. श्री एस०एस० मूर्ति,
सदस्य (विद्युत प्रणाली),
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
4. श्री के० पी० मैमनी,
सदस्य (प्राधिक और वाणिज्यिक)
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
5. श्री ए० एन० सिंह,
सदस्य (जल विद्युत)
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
6. श्री एन० सी० बसु,
सदस्य (प्रचालन),
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
7. श्री सी०एन० रामकृष्ण राव,
संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार,
विधि कार्य विभाग

[सं० बिजली-वो-28(8)/72]

जि० रे० मेहतानी, प्रवर सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

New Delhi, the 23rd November, 1977

5.O. 4015.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948), the Central Government hereby constitutes the Central Electricity Authority consisting of the following Members with effect from the 21st November, 1977, until further orders :—

- (1) Shri S. N. Roy, Chairman, Central Electricity Authority
- (2) Shri H. R. Kulkarni, Member (Thermal), Central Electricity Authority.

(3) Shri S. S. Murthy, Member (Power Systems), Central Electricity Authority.

(4) Shri K. P. Taimlai, Member (Economic and Commercial), Central Electricity Authority.

(5) Shri A. N. Singh, Member (Hydro-electric), Central Electricity Authority.

(6) Shri N. C. Basu, Member (Operations), Central Electricity Authority.

(7) Shri C. H. Ramakrishna Rao, Joint Secretary and Legal Adviser, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs.

[No. EL. II-28/8/72]

J. D. MEHTANI, Under Secy.

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1977

का०घा० 4016—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिमोर्गियों की बेवखली) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की तारीख 31 दिसम्बर, 1976 की अधिसूचना संख्या का० घा० 254 के अतिरिक्त में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्यथा अधिकारी नियुक्त करती है जो अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित सरकारी स्थानों की बाबत, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्यथा अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थान की कोटियाँ और अधिकारिता की स्वतन्त्र सीमाएँ
1	2
1. (i) महाप्रबंधक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का पाण्डवेश्वर क्षेत्र, डाकघर पाण्डवेश्वर, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल (2) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का पाण्डवेश्वर क्षेत्र, डाकघर पाण्डवेश्वर, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल।	कोयला क्षेत्र एरिया और सभी अन्य स्थान जो जिला बर्दवान बर्दवान, पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के पाण्डवेश्वर क्षेत्र के भाग हैं।
2. (i) महाप्रबंधक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का बंकोला क्षेत्र, डाकघर उखरा, जिला बर्दवान, पश्चिम-बंगाल (ii) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का बंकोला क्षेत्र, डाकघर उखरा, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल	कोयला क्षेत्र एरिया और सभी अन्य स्थान जो जिला बर्दवान पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के बंकोला क्षेत्र के भाग हैं।
3. (i) महाप्रबंधक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का कंडा क्षेत्र, डाकघर बहुला, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल (ii) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का कंडा क्षेत्र, डाकघर बहुला, जिला बर्दवान, पश्चिम-बंगाल	कोयला क्षेत्र एरिया और सभी अन्य स्थान जो जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के कंडा क्षेत्र के भाग हैं।

- | 1 | 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. (i) महाप्रबंधक, ईस्टर्न कोल-फील्ड्स लि० का कजोरा ग्राम क्षेत्र, डाकघर कजोरा ग्राम, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल
(ii) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का कजोरा ग्राम क्षेत्र, डाकघर कजोरा ग्राम, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल | कोयला क्षेत्र एरिया और सभी अन्य स्थान जो जिला बर्दवान, कोल-फील्ड्स लि० के कजोरा ग्राम क्षेत्र के भाग हैं। |
| 5. (i) महाप्रबंधक, ईस्टर्न कोल-फील्ड्स लि० का कुमुस्तोरिया क्षेत्र, डाकघर टोपोई, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल
(ii) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का कुमुस्तोरिया क्षेत्र, डाकघर टोपोई, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल | कोयला क्षेत्र एरिया और सभी अन्य स्थान जो जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के कुमुस्तोरिया क्षेत्र के भाग हैं। |
| 6. (i) महाप्रबंधक, ईस्टर्न कोल-फील्ड्स लि० का सतग्राम क्षेत्र, डाकघर देवचन्मनगर, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल
(ii) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का सतग्राम क्षेत्र, डाकघर देवचन्मनगर, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल | कोयला क्षेत्र एरिया और सभी अन्य स्थान जो पश्चिम बंगाल के जिला बर्दवान व बांकुरा में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के सतग्राम क्षेत्र के भाग हैं। |
| 7. (i) महाप्रबंधक, ईस्टर्न कोल-फील्ड्स लि० का भीमुर क्षेत्र, डाकघर कार्सीपहाड़ी, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल
(ii) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का भीमुर क्षेत्र, डाकघर कार्सीपहाड़ी, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल | कोयला क्षेत्र एरिया और सभी अन्य स्थान जो जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के भीमुर क्षेत्र के भाग हैं। |
| 8. (i) महाप्रबंधक, ईस्टर्न कोल-फील्ड्स लि० का दिजेरगढ़ क्षेत्र, डाकघर छीतारामपुर, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल
(ii) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का दिजेरगढ़ क्षेत्र, डाकघर छीतारामपुर, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल | कोयला क्षेत्र एरिया और सभी अन्य स्थान जो जिला बर्दवान और पुरुसिया, पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के दिजेरगढ़ क्षेत्र के भाग हैं। |
| 9. (i) महाप्रबंधक, ईस्टर्न कोल-फील्ड्स लि० का सासमपुर क्षेत्र, डाकघर समरी, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल
(ii) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का सासमपुर क्षेत्र, डाकघर समरी, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल | कोयला क्षेत्र एरिया और सभी अन्य स्थान जो जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल रभी सवास परगना, बिहार में ईस्टर्न कोलफील्ड्स के सासमपुर क्षेत्र के भाग हैं। |

- | 1 | 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. (i) महाप्रबंधक, ईस्टर्न कोल-फील्ड्स लि० का मुगमा क्षेत्र, डाकघर मुगमा, जिला धनबाद, बिहार
(ii) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का मुगमा क्षेत्र, डाकघर मुगमा, जिला धनबाद, बिहार | कोयला क्षेत्र एरिया और सभी अन्य स्थान जो जिला धनबाद, बिहार में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के मुगमा क्षेत्र के भाग हैं। |

[संख्या 11025/1/75-सी०ए०एफ०/सी०आई०आर० भाग II]

चन्द्र धर त्रिपाठी, निदेशक

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 30th November, 1977.

S.O. 4015.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Energy Number S.O. 254, dated the 31st December, 1976, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being officers equivalent to the rank of gazetted officers of Government, to be estate officers for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act, within the limits of their respective jurisdictions in respect of the categories of public premises specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
1. (i) General Manager Panvadeswar Area of Eastern Coalfields Limited, P.O. Pandaveswar, District Burdwan, West Bengal.	Coalfield area and all other premises forming part of Pandaveswar Area of the Eastern Coalfields Limited in the Districts of Burdwan and Birbhum, West Bengal.
(ii) Senior Administrative Officer, Panvadeswar Area of Eastern Coalfields Limited, P.O. Pandaveswar, District Burdwan, West Bengal.	
2. (i) General Manager, Bankola Area of Eastern Coalfields Limited, P.O. Ukhra, District Burdwan, West Bengal.	Coalfield area and all other premises forming part of Bankola Area of the Eastern Coalfields Limited in the District of Burdwan, West Bengal.
(ii) Senior Administrative Officer, Bankola Area of Eastern Coalfields Limited, P.O. Ukhra, District Burdwan, West Bengal.	

(1)	(2)
3. (i) General Manager, Kenda Area of Eastern Coalfields Limited P.O. Bahula, District Burdwan, West Bengal.	Coalfield area and all other premises forming part of Kenda Area of the Eastern Coalfields Limited in the District Burdwan, West Bengal.
(ii) Senior Administrative Officer, Kenda Area of Eastern Coalfields Limited, P.O. Bahula, District Burdwan, West Bengal.	
4. (i) General Manager, Kajora Area of Eastern Coalfields Limited, P.O. Kajoragram, District Burdwan, West Bengal.	Coalfield area and all other premises forming part of Kajora Area of the Eastern Coalfields Limited in the District of Burdwan, West Bengal.
(ii) Senior Administrative Officer, Kajora Area of Eastern Coalfields Limited P.O. Kajoragram, District Burdwan, West Bengal.	
5. (i) General Manager, Kunustoria Area of Eastern Coalfields Limited P.O. Topoai, District Burdwan, West Bengal.	Coalfield area and all other premises forming part of Kunustoria Area of the Eastern Coalfields Limited in the District of Burdwan, West Bengal.
(ii) Senior Administrative Officer, Kunustoria Area of Eastern Coalfields Limited, P.O. Topoai, District Burdwan, West Bengal.	
6. (i) General Manager, Satgram Area of Eastern Coalfields Limited P.O. Devchandnagar, District Burdwan, West Bengal.	Coalfield area and all other premises forming part of Satgram Area of the Eastern Coalfields Limited in the District of Burdwan and Bankura, West Bengal.
(ii) Senior Administrative Officer, Satgram Area of Eastern Coalfields Limited, P.O. Devchandnagar, District Burdwan, West Bengal.	
7. (i) General Manager, Sripur Area of Eastern Coalfields Limited, P.O. Kalipahari, District Burdwan, West Bengal.	Coal field area and all other premises forming part of Sripur Area of the Eastern Coalfields Limited in the District of Burdwan, West Bengal.
(ii) Senior Administrative Officer, Sripur Area of Eastern Coalfields Limited P.O. Kalipahari, District Burdwan, West Bengal.	
8. (i) General Manager, Dishergarh Area of Eastern Coalfields Limited P.O. Sitarampur, District Burdwan, West Bengal.	Coalfield area and all other premises forming part of Dishergarh Area of the Eastern Coalfields Limited in the Districts of Burdwan and Purulia West Bengal.
(ii) Senior Administrative Officer, Dishergarh Area of Eastern Coalfields Limited, P.O. Sitarampur, District Burdwan, West Bengal.	

(1)	(2)
9. (i) General Manager, Salanpur Area of Eastern Coalfields Limited, P.O. Samdi, District Burdwan, West Bengal.	Coalfield area and all other premises forming part of Salanpur Area of the Eastern Coalfields Limited in the District of Burdwan, West Bengal and Santhal Pargana, Bihar.
(ii) Senior Administrative Officer, Salanpur Area of Eastern Coalfields Limited, P.O. Samdi, District Burdwan, West Bengal.	
10. (i) General Manager, Mugma Area of Eastern Coalfields Limited, P.O. Mugma, District Dhanbad, Bihar.	Coalfield area and all other premises forming part of Mugma Area of the Eastern Coalfields Limited in the District of Dhanbad, Bihar.
(ii) Senior Administrative Officer, Mugma Area of Eastern Coalfields Limited, P.O. Mugma, District Dhanbad, Bihar.	

[No. 11025/1/75-CAF/PIR.PT.II]

C. D. TRIPATHI, Director

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1977

कां.प्र. 4017.—भोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 20 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कार्यकारी अधिनियम, मद्रास सेंट्रल डिवाइज नं. 2, के.लो.नि.वि.०, मद्रास को, सरकार के राजपत्रित अधिकारी होने के नाते, कथित अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा संपदा अधिकारी नियुक्त करता है और भारत सरकार के तत्कालीन निर्माण और आवास प्रति मन्त्रालय की अधिसूचना सं० कां.प्र. 3018 तारीख 12 दिसम्बर, 1960 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की धारणा के स्वच्छ 1 में कम संख्या 3 के सामने वर्तमान प्रविष्टि की अगस्त निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“कार्यकारी अधिनियम, मद्रास सेंट्रल डिवाइज नं. 2, केन्द्रीय भोक निर्माण विभाग, मद्रास”

[जाइल सं. 21012(1)/77-सी०.III]

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 12th December, 1977

5.O. 4017.—In exercise of the powers conferred by section 3, read with section 20, of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Executive Engineer, Madras Central Division No. II, Central Public Works Department, Madras, being Gazetted Officer of Government, to be Estate Officer for the purposes of the said Act and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Supply No. S.O. 3016 dated the 12th December, 1960, namely:—

In the said notification, against serial number 3 for the existing entry in column 1 in the Table, the following entry shall be substituted, namely:—

“Executive Engineer, Madras Central Division No. II, Central Public Works Department, Madras.”

[File No. 21012(1)/77-Pol. III]

का. आ. 4018.—लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेवखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 20 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उपमुख्य प्रशासक चण्डीगढ़ को सरकार के राजपरिसर अधिकारी होने के नाते कथित अधिनिगम के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा संपत्ति अधिकारी नियुक्त करती है और भारत सरकार के तत्कालीन निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय (निर्माण और आवास विभाग) की अधिराज्यता में का. आ. 3921 तारीख 23-10-1967 में निम्न-निम्नीलिखित मद अन्वयत स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तम्भ 1 में मद 4 के पश्चात् निम्नीलिखित मद अन्वय . स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"5 उपप्रमुख प्रशासक, चण्डीगढ़

[स. 21012(2)/77-जी-3]

आर्चू चाँधुरी, संपदा निवेशक

S.O. 4018.—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 20, of the Public Premies (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints, the Deputy Chief Administrator, Chandigarh, being a gazetted officer of Government to be "estate officer" for the purposes of the said Act and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Supply (Department of Works and Housing) No S O 3921 dated the 23rd October, 1967, namely :—

In the said notification, in the Table, in column 1, after item 4, the following item shall be *inserted* namely :—

5 "The Deputy Chief Administrator, Chandigarh "

[F No. 21012(2)/77-Pol III]

I CHAUDHURI, Director of Estates

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1977

का.आ. 4019.—वायुमान नियम, 1937 के नियम 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस समय की शक्ति को और आगे बढ़ाकर 31 मार्च, 1978 करती है जिस बीच भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपनी अधिसूचना सं. ए. सी. 15013/15/76-ए. सी. दिनांक 12 अक्टूबर, 1976 द्वारा नियुक्त किए गए जांच म्यालाय से आशा की जाती है कि वह उपर्युक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मामलों पर अपनी जांच का कार्य समाप्त कर वेग और उसका निर्णय केन्द्रीय सरकार को दे देगा।

[का. सं. ए. सी. 15013/15/76-ए. सी.]

एस. ए. एम्बरम्, जप सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 12th December, 1977

S.O. 4019.—In exercise of the powers conferred by rule 75 of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby further extends upto the 31st March 1978, the period of time

within which the Court of Inquiry appointed by the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation vide Notification No AV 15013/15/76-A dated 12th October, 1976, will be expected to complete its inquiry into the matters specified in the notification mentioned above, and report to the Central Government

[F No AV 15013/15/76-A]

S EKAMBARAM, Dy Secy

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1977

का.आ. 4020.—अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1971 (1971 का 43) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर, श्री पी. एस. संधवालिया को 13 दिसम्बर, 1977 से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[ए. सी. 24012/3/77-ए. सी.]

चिरजीत बोगरा, जप सचिव

New Delhi, the 13th December, 1977

S.O. 4020.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri P S Sandhawalia, Chief Engineer, International Airports Authority of India, as a part-time Member of the International Airports Authority of India with effect from the 13th December, 1977 for a period of three years

[AV 24012/3/77-AA]

C L DHINGRA, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1977

का.आ. 4021.—का.आ. संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक तार महानिदेशक ने जूनजुनु टेलीफोन एक्सचेंज में दिनांक 1-1-78 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-9/77 पी एच बी]

जसवंत राम वशिष्ठ, सहायक महानिदेशक (पी. एच. बी.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 15th December, 1977

S.O. 4021.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-1-1978 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Jhunjhunu Telephone Exchange, Rajasthan Circle.

[No 5-9/77-PHB]

JASWANT RAI VASHIST, Asstt Director General (PHB)

नई दिल्ली 16 दिसम्बर, 1977

का.आ. 4022.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम

434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिवेशक में पेरिंटलमन्ना टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-1-78 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-12/77 पी० एच० बी०]

New Delhi, the 16th December, 1977

S.O. 4022.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-1-1978 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Perintalamanna Telephone Exchange, Kerala Circle.

[No. 5-12/77-PHB]

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर 1977

का० घा० 4023.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिवेशक में फ़जिल्का टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-1-78 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-10-77/पी०एच०बी०]

के० बी० मुदगल, सहायक महानिवेशक (पी०एच०बी०)

New Delhi, the 20th December, 1977

S.O. 4023.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-1-1978 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Fazilka Telephone Exchange, N.W. Circle.

Assistant Director (PHB)

[No. 5-10/77-PHB]

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1977

का० घा० 4024.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० घा० 2135 तारीख 7 जून, 1977 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित बैंकिंग कम्पनी द्वारा चलाये जा रहे बैंकिंग उद्योग को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 29 जून, 1977 से छः मास की कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिये बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 29 दिसम्बर, 1977 से छः मास की और कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[नं० एस०-11017/77-डी०-1 (ए०)]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 13th December, 1977

S.O. 4024.—Whereas, the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 2135 dated the 7th June, 1977 the Banking Industry carried on by a banking company as defined in clause (bb) of section 2 of the said Act, to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 29th June, 1977;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 29th December, 1977.

[No. S. 11017/77/DI(A)]

का० घा० 1025.—केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखंड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० घा० 2259, तारीख 20 जून, 1977 द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना के अधीन दुग्ध प्रदाय उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 22 जून, 1977 से छः मास की कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिये बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 22 दिसम्बर, 1977 से छः मास की और कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस०-11017/11/77-डी०-1(ए०)]

एल० के० नारायणम, हेडक अधिकारी

S.O. 4025.—Whereas, the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 2259 dated the 20th June, 1977, the Industry for the supply of milk under the Delhi Milk Scheme to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 22nd June, 1977;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of

the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 22nd December, 1977.

[No. S. 11017/11/77/DI(A)]

L. K. NARAYANAN, Desk Officer

8.O. 4026.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur in the industrial dispute between the employers in relations to the management of the Heavy Water Project, Post Office Anushakti, Via Kota and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th December, 1977.

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN,
JAIPUR

Case No. C.I.T. 9 of 1975

REFERENCE :

Government of India, Ministry of Labour Notification No. L-42012(36)/74-LR. III/D. IIB dated 26th July, 1975.

In the matter of an Industrial Dispute

BETWEEN

Rajasthan Anushakti Karamchari Union, Rawatbhata, Kota.

AND

Heavy Water Project, Anushakti, Kota.

APPEARANCE :

For the Union.—Shri P. K. Sharma.

For the Management.—Shri Panachand Jain.

Date of Award.—28-11-77.

AWARD

By its Notification quoted above the Central Government has referred the following Industrial Dispute between the Management of the Heavy Water Project Anushakti, Kota and its some ex-workmen to this Tribunal for adjudication :—

Whether the action of the construction Manager, Heavy Water Project, Post Office Anushakti, via Kota, in retrenching the undermentioned workmen with effect from the 27th July, 1974 (afternoon) was justified? If not to what relief are these workmen entitled :—

1. Shri Bajaram Singh.
2. Shri Jhamak Lal.
3. Shri Bhanwar Lal.
4. Shri Bajrang Lal.
5. Shri Tulsi Ram.
6. Shri Sharif Ali.
7. Shri Shamsheer Ali.

As the terms of reference reveal, the dispute relates to the retrenchment of the above named seven workmen. The workmen's cause was espoused and sponsored by the Rajasthan Anushakti Karamchari Union, Rawatbhata, Kota, hereinafter to be referred as the Union. The Heavy Water Project, Anushakti, Kota, will be hereinafter referred to as the Project.

Succinctly stated, the case set out by the Union in its statements of claims is that the seven workmen involved in the dispute were working in the Project nearly for 2 years before their retrenchment in July, 1974. They were casual and daily rated employees. The union had raised some demands, one of which was that the daily rated employees who had completed 240 days of service should be absorbed forthwith, with retrospective effect as Industrial Temporary Employees. Some conciliation talks took place between the management

of the Project and the Union. The management of the Project had agreed that regularisation of the daily rated employees as Industrial Temporary Employees would be done in phased manner depending upon the requirements in the cadre and number of posts. Due to this assurance and understanding held by the Management the demand relating to the daily rated workmen who had completed 240 days of service was not pressed at that time. But this assurance and understanding proved only myths and the seven workmen were retrenched only after two days of the conciliatory talks. The retrenchment was assailed on the grounds that (1) provisions of sec. 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter to be referred as the Act were not complied with, (2) the principle of 'last come first go' engrafted in sec. 25-G of the Act was not followed, (3) it was made during the pendency of the conciliation proceeding and as such violated the provisions of sec. 33(1)(B) of the Act, (4) fresh hands were recruited in place of these seven retrenched workmen, and (5) it was a mala fide act. The relief claimed is that the seven workmen named in the reference be reinstated with full back wages.

The claim of the Union was resisted by the Project. It was admitted that the seven workmen concerned in the dispute had completed more than one year's continuous service before their services were put to an end. It was denied that their retrenchment was mala fide or was in contravention of the provisions of section 25-F or section 25-G of the Act. It was stated that the retrenchment compensation was offered to the workmen at the time of retrenchment, but they themselves refused to accept it. Later on, they accepted the compensation. It was pleaded that in the negotiations between the union and the project, it was agreed that all casual labourers who were appointed upto 1972 were to be brought on Industrial Establishment and retrenched next day, if necessary. It was in pursuance to this assurance or understanding that as many as 34 casual labourers were absorbed on Industrial Establishment. The seven workmen concerned in the dispute had to be retrenched because there was no room for their absorption in the Industrial Temporary Establishment. They were, therefore, surplus and had to be retrenched. Regarding the applicability of sec. 33(1)(D) of the Act, it was submitted that it has no applicability. The authority of the union to represent the workmen or espouse their cause was challenged. It was averred that the original union by name Bhari Pani Pariyojna Karamchari Sangh, which had raised the dispute, was dissolved on 8-10-74. The Union viz. Rajasthan Anushakti Karamchari Union has no locus standi and cannot represent or sponsor the workman's cause. It was also alleged that the Project is under construction stage, and therefore, was not covered by 'industry' as defined in the Act. It was also pleaded that the seven concerned employees were engaged for a work of temporary nature, in the various works of the construction of the Heavy Water Colony. After this work was completed they were disbanded on account of the closure of the work. In the end, it was submitted that the workmen were not entitled to the relief of reinstatement.

In view of the rival contention of the parties the following questions arise for decision :—

- (1) Whether the construction work in which the seven concerned workmen were employed is not an 'industry'?
- (2) Whether it is a case of closure and as such the provisions of retrenchment are not applicable?
- (3) Whether the Union has no authority to represent, espouse and sponsor the present cause of the seven workmen?
- (4) Whether the retrenchment is illegal?
- (5) Relief to follow?

My findings are recorded ad seriatim :—

Re-1—Whether the project is an 'industry'?

It was contended on behalf of the project that the seven retrenched workmen were employed in the constructional work. This work is neither of manufacture of Heavy Water nor incidental or ancillary to the manufacture of Heavy Water. It was argued that as such the constructional work in which the seven retrenched workmen were employed, should not be taken to be an 'industry'. Reliance in support of the contention was placed on Jamul Cement Works Vs. State Industrial Court (1968) 1 L.L.J. 131. It is a case from M. P. High

Court. I have given my anxious considerations to the contention and find no merit in it. Authority relied upon by the employer relates to the dispute under the Madhya Pradesh Industrial Relations Act. That Act does not apply to all 'industries' or undertakings in any industry, but applies only to those industries and undertakings in any industry as may be notified under section 1(3) of that Act. The constructional activity was not notified under section 1(3) of the Act. It was due to these reasons that the constructional work of a Cement Factory was not taken to be an 'industry' under the said Act. In the instant case the things are quite different. Here the constructional work forms an integral part of the Project. The constructional work is to install the Project to manufacture the Heavy Water.

A similar contention was raised in *Ananda Chandra Swain Vs. State of Orissa* and another (1973) 1 L.L.J. 508, a decision from Orissa High Court. There also the question arose whether the constructional work of Bali Melu Dam Project should or should not be taken to be an 'industry'. The contention raised by the employer was that the Project should not be taken to be an 'industry', because it had not been completed and was still under construction. The contention was disallowed. It was observed in para 15 of the judgment :

"Suffice it to say the point is not more at large. It is now too late in the day to say that Balimela Dam Project, which has the ultimate object of generating electrical power to run different business and industry on pay, is not an industry as defined under the Act. Further, in the process of construction, the industry contemplated does not cease to be so or becomes otherwise. No matter whether the project is complete or in the process of construction, the relationship of employer and employee starts from the date the project is taken into hand and persons are appointed under whose co-operation the aim is to be achieved. Therefore, the contentions raised on behalf of the State are baseless and hence rejected."

The definition of 'industry' given in the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter to be referred as the Act is wide enough to include the constructional work in its ambit. I, therefore, hold that the activity in which the seven retrenched workmen were employed was 'industry'.

Re-2—Whether it is a case of closure ?

In para 4 of the Additional Pleas of the statement of defence, it was submitted by the Project that the seven retrenched workmen were engaged for a work of temporary nature in the various constructional work of the Heavy Water Colony e.g. quarters, road work, painting work, plantation of trees etc. After the completion of these works, the seven workmen became surplus. It was thus a closure of the activity. I again find no force in the contention. The Project's document Ex. M2 and Ex. M3 completely explodes the myth of closure. Ex. M2 is the notice of retrenchment. Ex. M3 is a notice under sec 25F(c) of the Act by the employer to the appropriate Government (Government of India). Ex. M2 does not speak about closure. No reasons for retrenchment have been mentioned in Ex. M2. If it had been a case of closure, it is expected that the same must have been disclosed in Ex. M2. Likewise in notice Ex. M3, no case of closure was disclosed. Ex. M3 speaks of retrenchment due to tapering of works. Again there is a letter dated July 25, 1974 by the Constructional Manager. It also speaks that the retrenchment was introduced as the concerned workmen became surplus to the requirements. It does not speak of closure.

The project's witnesses have also betrayed the plea of closure. Shri Ramlal in his cross examination admitted that the constructional work in the project has not finished as yet and that it is still continuing. Shri G. N. Ranade, Engineer incharge of constructional work in the project also admitted in his cross-examination that the constructional work is still going on in the project. The evidence of these two witnesses is sufficient to reject employer's plea of closure.

Re-3—Union's authority ?

In para 2 of the additional pleas in the statement of defence, it was pleaded by the Project that the union which raised the dispute was Bhari Paki Pariyojna Karamchari Sangh (hereinafter briefly referred to as B. P. P. K. S.). This sangh was dissolved on 8-10-74. The union now raising the

dispute viz. Rajasthan Anushakti Karamchari Sangh has no locus standi or authority to proceed with this reference. I have examined the contention with thorough care and find it untenable.

It is true that the B. P. P. K. S. had raised the dispute. It was this Sangh which submitted the charter of demand and took the matter to the Conciliation Officer vide Ex. W2, Ex. W3, Ex. W4 and Ex. W7. Admittedly this Sangh was dissolved on 8-10-74. The workmen of the Project on the dissolution of B. P. P. K. S. became members of the union. Ex. W8 are the minutes of the meeting of the union held on 8-10-74. Ex. W9 is a letter addressed by the President of the Union to the Registrar of Trade Union, Kota. It is dated 28-10-74. By this letter the B. P. P. K. S. informed the Registrar that it stood dissolved since 8-10-74 and that the workmen have joined the Rajasthan Anushakti Karamchari Union. Ex. W10 is a letter by the President of the Union, to the Government of India. By it the Union informed the Government of India that as the B. P. P. K. S. stood dissolved on 8-10-74, and the workmen of the project had joined the Rajasthan Anushakti Karamchari Union, this union be made a party to the dispute raised by the B. P. P. K. S. The union's witness Shri R. K. Shukla has testified all these facts on oath and has proved documents Ex. W8, Ex. W9 and Ex. W10. Shri Shukla is the General Secretary of the Union. No reason appear to discount his testimony. There is no evidence in rebuttal from the employer's side.

On the material referred to above, it can be safely held that on the dissolution of B. P. P. K. S., the workmen of the Project became members of Rajasthan Anushakti Karamchari Union. As such the union is entitled to sponsor and espouse the cause of the seven retrenched workmen. The dissolution of B. P. P. K. S. does not make the reference invalid. The reference can be prosecuted by the Union without any legal bar.

It is not at all necessary that the Union which raised the dispute should remain in charge of the dispute till adjudication. I am fortified in my submission by the observations made in *Ramlal Guramal Textile Mills Vs. State of Punjab* and others. It was observed therein—

"As long as a trade union which for the time being represents a workman of an industry takes up an individual workman's dispute, it continues to remain an industrial dispute till it is finally decided and it is not necessary that the same union may remain in charge of that dispute till adjudication. A new trade union by amalgamation or otherwise may come into existence which from that date may represent the workmen of that industry and in such a case if the new union takes over the dispute, then the dispute does not cease to be an industrial dispute."

In the instant case the dispute can, therefore, be prosecuted and continued by the Rajasthan Anushakti Karamchari Union.

Re-4—Whether the retrenchment is legal ?

A few words about the concept of retrenchment may be added before proceeding further. Retrenchment has been defined in the Act. It means the termination of the service of a workman by the employer for any reason whatsoever except on the ground of misconduct. It also excludes, voluntary retirement, superannuation, termination on account of ill health. The words "for any reason whatsoever" used in the definition, give a wide discretion to the employer to introduce retrenchment. The retrenchment is generally introduced for reasons of economy, rationalisation in industries, installation of new labour saving machinery and like others. The employer has a right to take a decision to retrench the dead weight of any economy surplus. So long the retrenchment is bona fide, its propriety cannot be questioned before a Tribunal. In *Parry & Co. Ltd. Vs. Second Industrial Tribunal*, AIR 1970 SC 1334 it was observed :

"It is well-settled that it is within the managerial discretion of an employer to organise and arrange his business in the manner he considers best. So long as that is done bona fide, it is not competent for a tribunal to question its propriety. If a scheme for such reorganisation results in surplusage of employees no employer is expected to carry the burden of such economic dead-weight and retrenchment has to be accepted as inevitable, however unfortunate it is. The

legislature realised this position and therefore, provided by Section 25-F compensation to soften the blow of hardship resulting from an employee being thrown out of employment through no fault of his. It is not the function of the Tribunal, therefore, to go into the question whether such a scheme is profitable or not and whether it should have been adopted by the employer."

I shall now proceed to examine the Union's contentions pleaded to make the retrenchment i.e. illegal and invalid.

The first contention is that the retrenchment compensation was not given to the workmen at the time of retrenchment. This non-payment of compensation makes the retrenchment illegal and invalid. It was argued that the provisions of section 25-F (A&B) are mandatory in command and admit no exception.

It is true that the payment of compensation as required by sub-sections A & B of sec. 25-F of the Act is a condition precedent to retrenchment. If no retrenchment compensation is paid to the workmen before they are asked to go, the retrenchment order is bad, invalid and inoperative in law. Vide Mahesh Chandra Sharma Vs. State of Rajasthan and other 1974 W. L. N. (Raj.) 564, the State Bank of India Vs. Shri N. Sundara Money AIR 1976 SC 1111 and M/s. Hindustan Steel Ltd. Vs. Presiding Officer, Labour Court Orissa and others A.I.R. 1977 SC 31. It was observed in the case of Hindustan Steel Ltd. that non-compliance of sec. 25-F(B) renders the retrenchment illegal.

If the retrenchment is invalid in law for non-compliance of the provisions of sub-sections A & B of sec. 25-F of the Act, subsequent payment of compensation cannot validate it. Even if the workmen accept compensation subsequent to the retrenchment, they will not be estopped from challenging the legality and validity of retrenchment because there can be no estoppel against the statute.

In order to prove the contravention of the provisions of sec. 25-F (A&B) of the Act, the Union examined two witnesses viz. Shri R. K. Shukla and Shri Bajrang Singh. The testimony of Shri R. K. Shukla is neither relevant nor helpful to prove the non-payment of the retrenchment compensation. He is not one of the retrenched workmen nor he was present when the retrenchment was effected. His testimony, therefore, affords no help to the Union.

Shri Bajrang Singh is one of the retrenched workmen. He deposed that no compensation was paid to him at the time of his retrenchment. He, however, did not state that no compensation was offered to him at the time of retrenchment.

In rebuttal the Project examined two witnesses to prove the fact that compensation was offered in cash to the workmen. But they themselves refused to accept it. These witnesses are Shri Ratanlal, a U.D.C. in accounts section of the Project and Shri G. N. Ranade, Engineer Incharge of the construction work in Project Colony and Plant site. One document Ex. M11 was also filed. Both these witnesses stated that compensation as admissible under sub-sections A&B of sec. 25-F was offered to each of the seven retrenchment workmen at the time of their retrenchment on 27-7-74. A memo (Ex. M11) of this refusal was prepared then and there on the spot on which both of them appended their signatures. Both these witnesses were cross-examined by the Union, but their testimony on the whole remained unshaken and unshattered. There is nothing in their statements to make their evidence unworthy of belief. In short there is no material to put their testimony at a discount.

From what they have stated, it stands established that compensation as payable under sub-sections (A&B) of sec. 25-F of the Act was offered in cash to each of the seven workmen at the time of their retrenchment and that the workmen refused to accept it.

There is one more factor which speaks heavily against the union. The union has examined only one workman out of the seven retrenched employees. In the circumstances of the case, it was incumbent on the Union to examine each and every retrenched employee to swear on oath that no compensation was offered to him at the time of his retrenchment.

There is no truth in the Union's allegations that no compensation was offered to the retrenched employees. My finding is that the compensation was offered in cash but the same was refused by the seven workmen. In Rajasthan Canal Project Vijaynagar Vs. Rashtriya Mazdur Union, 1975 W.L.N. (Raj) 679, it was laid down that the employer must have actually tendered the amount of wages to the employee and if the employee refused to accept the cash, then it shall be deemed that the provisions of sec. 25-F of the Act have been sufficiently complied with. There was complete and full compliance of the provisions of sec. 25-F (A&B) of the Act in the instant case.

The next ground pleaded to invalidate the retrenchment is that the provisions of sec. 25-G of the Act were not followed inasmuch as the principle of "last come first go" was said good bye. Here again there is no truth in the allegation. The project has filed the seniority list Ex. M1/A. It shows that the seven retrenched workmen were junior most in their cadres. There is no evidence in the union's side to show that persons junior to the seven retrenched workmen were retained in service. I have no good and cogent grounds to discredit the seniority list Ex. M1/A. I, therefore, hold that the provisions of sec. 25-G of the Act were not contravened by the employer in making the retrenchment.

The next ground on which the retrenchment is assailed is that it was made during the pendency of the conciliation proceeding. It was, therefore, invalid. There is no merit in the contention. No conciliation proceedings were pending before any Court, Tribunal or Conciliation Officer when the retrenchment was introduced. Of course some negotiations were going on between the Union and the Management. But these talks cannot be taken to be conciliation proceeding. It cannot be said, in these circumstances that the provisions of sec. 33(1)(B) of the Act were contravened.

Yet another ground urged to render the retrenchment invalid is that fresh hands were recruited in place of these seven retrenched workmen. I again see no substance in the contention. There is no material to show that fresh hands were recruited in place of the seven retrenched workmen. Rather on the other hand the Project evidence shows that the retrenched employees were offered re-employment for forty days, but none of the workmen turned up to join it. Ex. M 14 read with the testimony of the Project's witness Shri H. V. Awtharmony, Administrative Officer, shows that the offer for re-employment of retrenched workmen was made to them by Registered letters. There was thus full compliance of the provisions of sec. 25-H of the Act.

The last ground taken by the Union against retrenchment is that it was not a bona fide act of the employer. It was argued that the construction work was still going on when the retrenchment took place. The contention is untenable. As discussed earlier, some of the construction work was going on. The seven retrenched workmen were daily rated casual labourers. They were retrenched because they became surplus due to tapering off the works. No case of want of bona fides has been successfully made out by the Union.

The grounds pleaded by the Union to render the retrenchment illegal do not stand proved. The retrenchment, therefore, cannot be held invalid or void. According to me the retrenchment is fully justified.

As a result of my above findings, I hold that the retrenchment of the seven workmen—Sarvashri (1) Bajram Singh, Jhamak Lal, Bhanwarlal, Bajranglal, Tulsiram, Sharif Ali and Shamsheer Ali was invalid or illegal. Their retrenchment was justified. They are, therefore, not entitled to the relief of reinstatement or any other relief. I make my award accordingly. No order as to costs of this proceeding.

The award be submitted to the Central Government for publication as required by law.

S. S. BYAS, Judge, Presiding Officer.

[No. L-42012(36)/74-LR-III/D.II(B)]

HARBANS BAHADUR, Desk Officer.

आदेश

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1977

का० आ० 4027.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाखण्ड अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

प्रतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधि-करण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री के० पी० नारायणराव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धतन्त्र की श्री के० स्वामीदास, आग्नित्वरी टरबाइन भट्टेण्ट 'बी' पावर हाउस, कोठा-गुडियम को 16-4-1976 से बरखास्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुसूची का हकदार है?

[संख्या एन०-21012(1)/77-डी०-4(बी०)]

ORDER

New Delhi, the 14th November, 1977

S.O. 4027.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri K. P. Narayana Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Singareni Collieries Company Limited in dismissing Shri K. Swami-das, Auxilliary Turbine Attendant 'B', Power House, Kotha-gudiyam with effect from 16-4-1976 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?

[No. L-21012(1)/77-D-IV(B)]

New Delhi, the 14th December, 1977

S.O. 4028.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management Patharkhera Colliery of Western Coalfields Limited, Patharkhera and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th December, 1977.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL—
CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(B(7)/7AEE

PARTIES:

Employers in relation to the management of Patharkhera Colliery of Western Coalfields Limited, Patharkhera and their workmen represented through the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh (AITUC), P.O. Patharkhera Colliery, District Betul (M.P.).

APPEARANCES:

For Employers—Shri P. S. Nair, Advocate.

For Workmen—Shri P. K. Thakur, Advocate.

INDUSTRY: Coal Mines DISTRICT: Betul (M.P.)

Dated: November 24, 1977

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its Order No. L-22011(1)/76-DIII(B)/D-IV(B) dated 22nd April, 1977, forwarding the following industrial dispute for adjudication:

"Whether the management of Patharkhera Colliery of Western Coalfields Ltd., Patharkhera are justified in denying wages to the following workmen as recommended by the Central Wage Board for Coal Mining Industry? If not, to what relief are the said workmen entitled to and from what date?"

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Shri Chunnail, | Water Carrier |
| 2. Shri Sukhlal, | —do— |
| 3. Shri Panduram S/o Laxman, | Mechanical Helper |
| 4. Shri Yasavantrao S/o Parnya | —do— |
| 5. Shri Sukaman S/o Bhimari | —do— |
| 6. Shri Fagulal S/o Bhangri | —do— |
| 7. Shri Babulal S/o Bhangi | —do— |
| 8. Shrimati Kashibai D/o Bhagchand | —do— |
| 9. Smt. Girabai W/o Ramprasad | —do— |
| 10. Kumari Shyamabai D/o Ghukalu | —do— |
| 11. Shri Kishore S/o Pannalal | —do— |

2. It is not disputed that at least eight of these persons were employed in the Civil Engineering Department of the Colliery. They were paid wages according to Minimum Wages Act but not according to Wage Board recommendations. The sponsoring union Samyukta Khadan Mazdoor Sangh, hereinafter called as S.K.M.S. raised a dispute that workers employed in Civil Engineering Section should be paid wages as per Wage Board recommendations and the matter was taken to the Conciliation Officer. When after the failure report the matter was pending before the Central Govt. for making the reference. Betul Zila Rashtriya Khadan Karmchhari Sangh (hereinafter called the B.Z.R.K.K. Sangh) served a notice of direct action and presented a charter of 20 demands one of which was the same as had been raised by S.K.M.S. and the dispute relating to which was pending before the Central Government.

3. The matter was immediately seized by the Conciliation Officer and a Conciliation settlement was arrived at between B.Z.R.K.K. Sangh and the management on 13-12-1976. In that settlement it was decided as follows with respect to that demand:

"Item No. 6: Demand No. 7: It is agreed by the parties that the Union will furnish a list to the Sub-area Manager, Patharkhera before 15-12-1970 of such of the workmen as are actually working in maintenance job (not covered by the schedule of employment attached to Minimum Wages Act) and the management will consider such cases in the light of Wage Board recommendations against their sanctioned vacancy by 31-12-1976".

S.K.M.S., which is a minority union, was not a party to this settlement. B.Z.R.K.K. Sangh is a majority union.

4. It is again not denied specifically that the matter was again raised by all the three unions including S.K.M.S. and was discussed at Nagpur on 16th and 17th May, 1977. The minutes were drawn as follows:—

"List of 8 workmen covered under item No. 6 of the settlement dated 13-12-1976 will be released within 24 hours of reaching Patharkheda".

Two of the office bearers of S.K.M.S. also signed these comments.

5. The concerned workmen are admittedly casuals working under Civil Engineer for maintenance of more than 1254 quarters constructed by the employers.

6. The case of the Union is that these workmen are covered by the Wage Board recommendations and should be paid accordingly. The said settlement was a fraud played upon S.K.M.S. and the workmen. Management resorted to unfair labour practice. B.Z.R.K.K. Sangh was encouraged by the management to raise the dispute and with post haste entered into the said settlement with a view to kill the probable reference in the womb. The settlement itself did not resolve the dispute and therefore the present reference is valid as it relates to an existing industrial dispute.

7. Employer's case is that the reference is bad and untenable because:

- (i) the concerned workmen were not the members of the sponsoring union;
- (ii) there was no resolution passed by the majority of the union in favour of the sponsoring of such a dispute;
- (iii) the union has no representative capacity;
- (iv) in any case the minority union could not raise the industrial dispute;
- (v) the dispute raised was different from the dispute conceived in the reference, no names were given by the union even when demanded by the management;
- (vi) No dispute was directly raised with the employer. Raising the dispute before A.L.C. for the first time is not sufficient to bring an industrial dispute into existence before the reference;
- (vii) the industrial dispute even if it came into existence stood killed by the conciliation settlement with the majority union;
- (viii) the S.K.M.S. is estopped from denying the settlement because its office bearers were signatory to minutes of discussions held in response to and for the purpose of effectuating that settlement in respect of this demand.

Of these 11 workmen, names of which were never before disclosed by the sponsoring union, Nos. 4 & 10 are not in the rolls of the employer, No. 11 has left the service and it was asserted at the time of arguments that some of the remaining have already been absorbed on the regular wage board scale. The Wage Board never recommended a scale for such casual employees of Civil Engineering Department.

8. Parties agreed to at first seek decision on legal points which were treated as preliminary issues. Management examined Shri S. S. Misra and closed the case so far as preliminary issues were concerned while the union relied only on documents. It did not examine any witness when Shri Nair, Counsel for the management, conceded that the Union, S.K.M.S., had representative character in the mine. Whereas validity of reference was challenged in the pleadings on several counts stated above, only the following points were pressed by the learned Counsel at the time of arguments. I shall not therefore deal with the other points raised in the written statement by way of embellishment only.

9. Admittedly dispute was raised before the Asstt. Labour Commissioner and the management participated in those conciliation proceedings without raising the objection that the dispute was not raised before it. There the management disputed the demand and as such an industrial dispute came into existence much before the reference was made by the Government of India. The validity of the reference cannot therefore be challenged on this count. By participation in conciliation proceedings and without raising any such objection the management has missed the train and it does not now lie in its mouth to raise such a plea before this Tribunal. In fact before the Conciliation Officer first letter for adjournment was presented as a joint request.

10. Whereas sometimes the concerned workmen of Civil Section were called piece rated workmen as in the notices issued by the Asstt. Labour Commissioner, may be due to clerical error. (See Annexures 6, 7 & 8), they were called time-rated at other times as it appears from the initial application presented by the union on 28-2-75 before the A.L.C. Still it was quite clear that the dispute related to the workers of Civil Engineering Section and the dispute was about the non-payment of wages according to Wage Board recommendations. The dispute so raised was not different to the dispute conceived in the reference. Saying about the workers of Civil section generally and naming them subsequently, does not make such a difference as may give the dispute a grossly different colour, content or character. Hence I am of the view that the dispute raised before the A.L.C. was not different as compared to dispute conceived in the reference.

11. This brings us to the last point pressed before me in the arguments and that was about the validity and effect of the conciliation settlement dated 13-12-76 (Ex. M/4). Admittedly, B.Z.R.K.K. Sangh is the recognised union. It served a notice of strike and raised not only this demand as had previously been raised by S.K.M.S. which had resulted in submission of failure report by that time, but also other 19 demands and some of them were quite serious ones involving a number of workmen. Demand No. 10 concerned 109 workmen who were agreed to be taken back as time-rated workmen. The cases of those who were stopped from work, those who were not made permanent, and those who were not posted as time rated even after two years of service were taken up in the demands and the management almost conceded on many of these points. Many decisions about welfare activities were made. Thus an overall picture of the settlement presents a picture of genuine effort to settle comprehensively the disputes in their various aspects rather than a fraudulent conspiracy to devise a means to kill the comparatively insignificant dispute only one item, which had been raised by S.K.M.S. and was pending with the Govt. of India.

12. Management was a hard bargainer. On quite a few matters management kept the last word with it. Union has many times to concede some ego to the management. The settlement goes to show that the union at places conceded one or two points, for gaining the third one. It is after all a bargain in which neither party wins or loses completely. Hence if the management agreed to consider some names of casual workers of civil engineering department as and when the vacancy occurred after the union furnished the list of such workmen, it could not be said to be so vague a-term as to be not amounting to a settlement. Nor could it be an evidence of conspiracy or fraud between the majority union and the management.

13. The fact that the (B.Z.R.K.K. Sangh) Union had given a strike notice is sufficient to explain why conciliation settlement was hatched out without much loss of time. This timely action and effort to avert a strike cannot be interpreted to be giving rise to a suspicion against genuineness. On the other hand as said above the settlement appears to be fair and genuine. Such a settlement therefore binds not only the members of B.Z.R.K.K. Sangh but even the members of the rival union, S.K.M.S. It was so held in Ramnagar Cane and Sugar Co. Ltd. Vs. Jatin Chakravorty [1961-I-LJ 244(247)] by the Supreme Court in a similar situation Hon. Gajendragadkar J. (as he then was) observed that:

"there can be no doubt that the settlement arrived at between the appellant and the employer's union

during the course of conciliation proceeding on February 25, 1974 would bind not only the members of the said union but all workmen employed in the establishment of the appellant at that date. This inevitably means that the respondents would be bound by the said settlement even though they may belong to the rival union."

I am, therefore, inclined to hold that the conciliation settlement dated 13-12-1976 (Ex. M/4) settled the dispute which had been raised by S.K.M.S. union and was binding on its members as well. If principles of Contract Act are applied fraud may render a settlement voidable. Party to the settlement may in that case seek to set it aside on that ground but even in that case alleged fraud, will require proof beyond doubt. Mere suspicious circumstances, which may have their innocuous explanations, shall not be sufficient to set aside the settlement. However, in my opinion there is no need to induct the principles of Contract Act for that purpose. S. 19(2) lays down the procedure for setting aside a conciliation settlement. When the special law lays a specific procedure for achieving a particular end, the general law shall not apply and the prescribed procedure will have to be followed. As by the time the reference was made the union had no right or occasion to set it aside by a notice, the settlement had its binding force and it killed the dispute.

15. It has been held in *Sir Silk Ltd Vs. Govt. of A. P.* [4 SCLJ 2359 (2364)] that bona fides of a settlement can be challenged only by an independent industrial dispute. The bonafides cannot be obliquely considered in this matter as an incidental point. As no industrial dispute relating to bona fides has been incorporated in this reference for adjudication by this Tribunal, such an objection would be an extraneous matter which cannot be considered within the limitations of the present reference.

16. In *State of Bihar Vs. D. N. Ganguly* (1958-II-LLJ 634) at (64) the Supreme Court observed that 'it would be very unreasonable to assume that Industrial Tribunal would insist upon dealing with the dispute on merits even after it is informed that the dispute has been amicably settled between the parties.' Of course in the present case Central Govt. was not informed of this settlement otherwise after the settlement of 13-12-1976 it would not have made reference on 22nd April, 1977. The settlement has almost the force of an award and finality under Sec. 18(3) of I.D. Act. Moreover in the present case subsequently a meeting was held between the management and all the three operating unions including S.K.M.S. in which the question of implementation of the settlement on this dispute was discussed and the manner to deal with it was decided. Two representative office bearers of S.K.M.S. signed the minutes of that meeting. In other words S.K.M.S. Union gave its seal of approval to the said settlement and cannot now turn round to say something against it.

17. It is therefore held that the reference was not competent because the industrial dispute had so ceased to exist before the date on which the reference was made.

Award is given accordingly.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

24-11-1977.

[No. L-22011(i)/76-D. III(B)/D-IV (B)]

BHUPENDRA NATH, Desk Officer

New Delhi, the 14th December, 1977

S.O. 4029.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Gosalia Shipping Pvt. Ltd., Stevedores, Vasco-da-Gama, Goa and their workman which was received by the Central Government on the 13th December, 1977.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY CAMP: PANAJI

PRESENT :

Reference No. CGIT-2/1 of 1974

Employers in relation to the Management of
M/s. Gosalia Shipping Private Limited, Stevedores,
Vasco-da-Gama, Goa.

AND

Their Workman

Shri Luis Matiano Pereira, Assistant Foreman.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri G. R. Srinivasan, Personnel Manager.

For the Workman—No appearance.

INDUSTRY : Ports and Docks STATE : Goa, Daman & Diu
Bombay, dated the 28th November, 1977

AWARD

The Government of India, in the Ministry of Labour acting under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 have referred the following dispute to this Tribunal for adjudication as per its order No. L-36012/5/73-P & D dated 8-2-1974 :—

"Whether the action of the management of Messrs Gosalia Shipping Private Limited, Stevedores, Vasco-da-Gama (Goa), in not allowing Shri Luis Mariano Pereira, Assistant Foreman, to resume duty with effect from the 13th December, 1972, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The facts of the case as can be gathered from the statement of claim are that the workman herein joined the service of M/s. Shantilal Khushaldas & Irmaos, Vasco-da-Gama on 15-12-1959 as a Tally Clerk. In 1968 the company M/s. Gosalia Shipping Private Limited was formed. The workmen in the service of M/s. Shantilal Khushaldas & Irmaos were allowed to work with M/s. Gosalia Shipping Private Limited with continuity of service. In January 1972 the workmen fell sick. Dr. R. P. Kuvelkar, who examined him diagnosed the disease to be Chronic Pyelonephric and advised complete rest. Till 2-3-1972 the workman could not attend his duties in the company. He claims to have orally informed the company of his sickness. From March, 1972 to December, 1972 he was under the treatment of a Specialist by name Dr. Camilo Luis A. Paleiro Margac. He submits that he had orally informed his employers of his inability to attend the duty on account of his illness. By 10-12-1972 he was declared fit to attend his duties. On 13-12-1972 he reported himself before the Employers with medical certificate of fitness given by the Doctor but he was not allowed to resume duty. Thereafter he approached the Conciliation Machinery by raising an industrial dispute through the Mormugao Stevedores' Staff Association of which he is a member. The Employer did not care to attend the conciliation proceedings before the Assistant Labour Commissioner (C), Vasco-da-Gama. Consequently the Assistant Labour Commissioner (C) submitted failure of conciliation report to the Government, upon receipt of which the Government of India made the present reference to this Tribunal. The workman prays that (1) he may be reinstated in service with effect from 13-12-1972 and (2) that the period of absence from 1-1-1972 to 12-12-1972 may be treated as authorised leave and that the same may be adjusted towards his leave account.

3. The management filed written statement stating that in the month of January, 1972 the workman orally applied for leave of absence for two days through a friend of his. They further say that from January, 1972 to December, 1972 they had not heard from this employee. Therefore in accordance with the rules of the company which was following the Model Standing Orders the worker was treated as having lost his lien on his permanent post. Therefore the management submits that the workman is not entitled to reinstatement or any of the reliefs prayed for.

4. After the management filed the written statement 23-7-1976 the case was posted for hearing for the first time on 23-5-1977 at Mormugao on which date the Trade Union representative reported ready. At the instance of the management the matter was adjourned to 8-8-1977 for hearing at Bombay. On 8-8-1977 the Union representative appeared but the management sought adjournment by a wire. The case was posted at Panaji for hearing on 19-9-1977. On that date the workman and the Trade Union representative were absent. The case was called on 20-9-1977 and 23-9-1977 for the appearance of the workman and the Trade Union representative. As they did not appear during that sitting at Panaji the matter was adjourned to 15-11-1977 for being heard at Panaji. On 15-11-1977 and on 17-11-1977 the workman and his representative failed to appear. So a notice of pre-mptory hearing for 19-11-1977 was issued to the parties. The Trade Union having received the notice on 17-11-1977 did not choose to make its appearance. The matter was therefore heard ex-parte.

5. The point that arises for consideration is whether the workman in question is entitled to resume duty on 13-12-1972 after an absence of nearly 12 months. From the averments made in the statement of claim and the written statement it appears that in January, 1972 the workman orally applied for two days leave which the management granted. Admittedly the workman did not report himself to duty till 13-12-1972. According to him he was under the treatment of one Dr. R. P. Kuvelkar till March, 1972. Therefore, under treatment at the hands of a specialist by name Dr. C.I.A. Faleirao. He says that on 10-12-1972 Dr. Faleire pronounced him to be fit to resume duty. The workman claims that during the period from January, 1972 to December, 1972 he was periodically informing his employer of his inability to attend to his duties on account of his prolonged illness. The management denies that averment. In the absence of any oral or documentary evidence this plea of the workman cannot be accepted. On behalf of the management it is submitted that as the workman did not report himself for duty after the expiry of the 2 days casual leave applied for they treated his absence for the next 17½ days as leave with full pay. As the workman did not report himself for duty thereafter they suspended his lien on the post he was holding. They submit that in the circumstances the workman is not entitled to reinstatement. The statement made on behalf of the management has to be accepted in the absence of any evidence to the contra.

6. For the aforesaid reason I hold that the section of the management in not allowing the workman Shri Luis Mariano Pereira, Assistant Foremen, to resume duty with effect from the 13th December, 1972 is justified.

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer.

[No. L-36012(5)/73-P&D/D-IV(A)]

S.O. 4030.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Launch "Sai Prasad II", Vasco-da-Gama, Goa and their workmen which was received by the Central Government on the 13th December, 1977.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 BOMBAY CAMP . PANAJI

PRESENT :

Shri P. Ramakrishna, Presiding Officer.

Deference No. CGIT-2/14 of 1974

PARTIES

Employers in Relation to the Management of Launch "Sai Prasad II", Vasco-da-Gama, Goa

AND

Their Workmen

Sarvashri Narain Bhagwan Parab, Serang and Yeshwant K. Mapsekar, Driver.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri Vasant Sacolkar Launch Owner.

For the Workmen.—1. Shri Mohan Nair, General Secy. Goa, Dock Labour Union.

2. Shri Y. K. Mapsekar, One of the workmen.

INDUSTRY : Ports and Docks.

STATE : Goa, Daman and Diu.

Panaji, dated the 29th November, 1977

AWARD

The Government of India, in the Ministry of Labour acting under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, (14 of 1947) has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication by their order No. L-36012/8/74-P & D dated 25-4-1974 :—

"Whether the action of the management of Launch "Sai Prasad II", Vasco-da-Gama, Goa in terminating the services of Sarvashri Narain Bhagwan Parab, Sarang and Yeshwant K. Mapsekar, Driver, was justified? If not to what relief are the workmen entitled?"

2. The Goa Dock Labour Union filed a statement of claim on behalf of the workmen herein stating that the workmen Narain Bhagwan Parab, and Yeshwant K. Mapsekar were Sarang and Driver respectively on the Launch Sai Prasad II belonging to one Vasant B. Sancelker. N. B. Parab put in a service of more than 10 months and Mapsekar put in about one year of service before their services were unlawfully terminated in October, 1973. It is submitted that on account of the trade union activities of the workmen herein the owner resorted to terminate their service by way of victimisation. The workmen raised an industrial dispute with the Assistant Labour Commissioner (C) Vasco da Gama through their Union requesting him to take up the matter in conciliation. On the Assistant Labour Commissioner (C) submitting the failure of conciliation report the Government of India referred the present dispute to this Tribunal for adjudication. The workmen pray that they may be reinstated in service with full back wages and continuity of service

3. The Owner of the Launch has filed a written statement stating that on 1-1-1973 Parab joined the service of his launch Sai Prasad II. He says that he did not find his service to be satisfactory. He further stated that Parab quarrelled with two persons Narayan and Tato working on the Launch 'Nanda'. The Police registered a case against Parab which was ultimately compounded between the parties. It is also stated that on account of the absence of Parab the Launch could not ply on 9-9-73 with the result the Gang workers could not be taken to the ships s.s. Olympic and s. s. Linda. The Shipping agents M/s. Agencia Naritima Commercial, Vasco-da-Gama debited Rs. 2356.08 to the owner for his failure to transport their gang workers to their ship. On 10-9-1973 the management served notice on Parab calling upon him to explain his above conduct. The workman instead of giving a reply to the said show cause notice absconded from duty. So the owner submits it is not a case of termination of service. The amount due to Parab as per the Award of Machado was paid to him regarding the workman Yeshwant K. Mapsekar it is said that he also absconded himself from duty on 9-10-1973, and that he never reported for duty thereafter. It is stated that Mapsekar is now employed by M/s. Timblo Pvt. Ltd., on the launch 'Navegadora'. So the workman Mapsekar has no claim whatsoever for reinstatement. The owner prays that this reference may be answered against the workmen.

4. On 15-11-1977, Shri Mohan Nair appearing for the workmen and the Owner of the Launch Shri Vasant B. Sancelker appearing in person filed a memo, reporting settlement of the dispute between the parties. As per the terms of

the settlement the owner has agreed to pay Rs. 1050 to the workman Parab and Rs. 1200 to the workman Mapsekar in full and final settlement of their claim against the management. The amount mentioned in the settlement is also paid to the workmen concerned and copies of receipts passed by them are filed before the Tribunal. The workmen have also stated that they were not interested in pressing their claim for reinstatement. I consider that this settlement is in the interests of the workmen.

5. In the result this reference is answered in terms of the settlement arrived at between the parties. A copy of the Memo. of Settlement is appended hereto.

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

MEMORANDUM OF SETTLEMENT UNDER SECTION 2(p) OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947 READ WITH SECTION 18(1) OF THE SAID ACT, BETWEEN SHRI VASANT B. SANCALKAR, OWNER OF LAUNCH 'SAI PRASAD II' AND HIS WORKMEN, REPRESENTED BY GOA DOCK LABOUR UNION (INTUC) IN RESPECT OF TERMINATION OF SERVICES OF S/SHRI NARAYAN BHAGWAN PARAB, SERANG, AND YESHWANT K. MAPSEKAR, DRIVER.

PRESENT :

Representing the Employer.—(1) Shri Vasant B. Sancalkar, Owner,
Launch 'Sai Prasad II'

Representing the Employees.—(1) Shri Mohan Nair, General Secretary, Goa Dock Labour Union (INTUC),

(2) Shri Narayan Bhagwan Parab, Serang.

(3) Shri Yaswant K. Mapsekar, Driver.
(Both covered under reference).

SHORT RECITAL OF THE CASE

The Government of India, Ministry of Labour was pleased to refer the matter relating to the wrongful termination of services of S/Shri Narayan Bhagwan Parab, Serang and Yeshwant K. Mapsekar, Driver, to the Hon'ble Industrial Tribunal under clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication under reference No. CGIT-2/14 of 1974.

In the meantime the well-wishers and the friends of both the parties covered in this dispute had tried through their good office to come to an amicable settlement in the matter and lastly the dispute was amicably resolved to the satisfaction of all concerned and the workmen as follows:—

TERMS OF SETTLEMENT

(1) Shri Vasant B. Sancalkar, owner of Launch 'Sai Prasad II' hereby agrees to pay and Shri Narayan Bhagwan Parab, Serang, agrees to accept the sum of Rs. 1050 (One thousand and fifty only) as full and final settlement of all his claims whatsoever including and against reinstatement.

(2) Shri Vasant B. Sancalkar, owner of Launch 'Sai Prasad II', hereby agrees to pay and Shri Yeshwant K. Mapsekar, driver, agrees to accept the sum of Rs. 1,200 (One thousand and two hundred only) as full and final settlement of all his claims whatsoever including and against reinstatement.

(3) Both these workmen referred under clause (1) and (2) are not interested in reinstatement as both of them have joined other jobs for better prospects.

(4) Both these workmen have been issued with good service certificates by the employer.

(5) This memorandum of Settlement is signed here at Vasco-da-Gama, with the consent of both the parties covered in this dispute.

(6) Both these parties agree to file this memorandum of Settlement before this Hon'ble Tribunal for giving a consent award.

For the Employer

Sd/-

Shri Vasant B. Sancalkar

For the Employees

Sd/-

(1) Shri Mohan Nair

Sd/-

(2) Shri Narayan B. Parab

Sd/-

(3) Shri Yeshwant Mapsekar

Sd/-

Witness :

(1) Sd/-

(2) Sd/-

Vasco-da-Gama, Goa.

Dated : 14th November, 1977.

[No L-36012(8)/74-P&D/D-IV(A)]

NAND LAL, Desk Officer

New Delhi, the 20th December, 1977

S.O. 4031.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Redi Iron Ore Mine of M/s. Gogte Minerals, Tilakwadi, Belgaum and their workmen, which was received by the Central Government on the 3-12-1977.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/19 of 1975

PRESENT :

Shri P. Ramakrishna, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Redi Iron Ore Mine of Messrs Gogte Minerals, Tilakwadi, Belgaum.

AND

Their Workmen

1. Shri V. B. Kanyalkar

2. Shri B. J. Deeya

3. Shri A. N. Kambli

4. Shri N. V. Nagolkar

5. Shri R. J. Kambali

6. Shri V. A. Bhute

7. Shri S. R. Kambli

8. Shri P. L. Ajgaonkar

9. Shri S. N. Kambli

10. Shri K. S. Kambli

11. Shri N. S. Krishnaji

12. Shri M. S. Krishnaji

13. Shri H. B. Hukkeri

14. Shri A. B. Lodrie

15. Shri M. B. Kambli

16. Shri M. A. Palyekar

17. Shri K. S. Shirodkar

18. Shri A. N. Krishnaji

19. Shri P. D. Fernandes

20. Shri G. K. Rane
21. Shri E. M. Fernandes
22. Shri J. D. Kerkar
23. Shri A. G. Manjrekar
24. Shri K. A. Kambli
25. Shri N. M. Redkar
26. Shri G. V. Redkar
27. Shri U. S. Nair
28. Shri A. V. Korgaonkar
29. Shri K. L. Morajkar
30. Shri M. B. Awade
31. Shri V. K. Naik
32. Shri S. S. Vengurlekar
33. Shri T. T. Coelhe
34. Shri D. S. Pilankar
35. Shri G. P. Sakholkar
36. Shri M. S. Suryaji
37. Shri I. J. Deeya
38. Shri K. S. Kamat
39. Shri B. D. Mannekar
40. Shri R. D. Sutar
41. Shri M. A. Salgaonkar
42. Shri S. N. Redkar
43. Shri M. V. Pilankar
44. Shri U. S. Padval
45. Shri T. R. Lohar
46. Shri S. G. Gadekar
47. Shri S. A. Samant
48. Shri N. S. Ibrahimpurkar
49. Shri R. L. Redkar
50. Shri G. P. Reddy
51. Shri S. R. Warkhandkar
52. Shri P. N. Pereira
53. Shri G. L. Sutar
54. Shri D. A. Rodric
55. Shri M. G. Warkhandkar
56. Shri J. H. Kanyalkar
57. Shri H. T. Kadam
58. Shri S. D. Suryawamshi
59. Shri B. N. Arondekar
60. Shri D. N. Mayekar
61. Shri D. S. Kanyalkar
62. Shri U. V. Satoskar
63. Shri N. K. Tivarekar
64. Shri M. T. Kambli
65. Shri J. V. Gawade
66. Shri R. M. Parab
67. Shri M. E. Arolkar
68. Shri A. A. Shatgar
69. Shri S. B. Pednekar
70. Shri P. B. Padnekar
71. Shri Pandurang G. Patil
72. Shri M. J. Gaotalkar
73. Shri T. S. Parab
74. Shri D. H. Kambli
75. Shri B. T. Kerkar
76. Shri H. S. Vadar
77. Shri B. H. Kambli
78. Shri R. D. Redkar
79. Shri M. D. Pednekar
80. Shri N. G. Gosavi
81. Shri M. B. Gavandi
82. Shri T. M. Konadkar
83. Shri C. V. Kambli
84. Shri S. B. Redkar

85. Shri V. G. Nagolkar
86. Shri Ankush B. Redkar
87. Shri S. V. Kerkar
88. Shri L. R. Parulekar
89. Shri S. R. Gawade
90. Shri Kaitan M. Shivalkar
91. Shri M. M. Redkar
92. Shri R. S. Redkar
93. Shri K. P. Suryaji
94. Shri S. K. Upshekar
95. Shri P. B. Bhujang
96. Shri V. V. Sawant
97. Shri K. S. Pednekar
98. Shri B. E. Khan
99. Shri A. E. Khan
100. Shri J. M. Palyekar
101. Shri Vithal K. Gavandi
102. Shri Rajaram S. Satoskar
103. Shri Madhukar V. Savant
104. Shri R. M. Padval
105. Shri Sadanand Shirodkar
106. Shri G. V. Raut

APPEARANCES :

For the Employers—Shri P. K. Rele, Solicitor and Advocate.

For the Workmen—Shri S. M. Dharap, Advocate.

INDUSTRY : Iron Ore Mines STATE : Maharashtra
Bombay dated the 3rd November, 1977

AWARD

The Government of India, in the Ministry of Labour by virtue of the powers conferred under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication by its Order No. L-26012/11/75-D-IV(B) dated 1-9-1975 :—

“Whether the action of the management of Redi Iron Ore Mine of Messrs Gogte Minerals in retrenching the following 106 permanent workmen with effect from the 15th May, 1975 was justified? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?”

Names of the workmen :—

(Names of the retrenched workmen are not repeated as they have been given above).

The facts disclosed in the statement of claim filed by the workmen through the Rashtriya Mine Mazdoor Sangh, Redi are that they are employed in the Iron Ore Mines of Messrs. Gogte Minerals. By notice dated 15-5-1975 the management retrenched the 106 workmen who are parties to this dispute on the ground that during rainy season i.e. May to October they are not finding it economical to operate the mines. The workmen question the legality and the propriety of the order of retrenchment. They raised an industrial dispute before the Assistant Labour Commissioner (C), Vasco-da-Gama who took up the matter in conciliation. Thereafter the Assistant Labour Commissioner (C), Vasco-da-Gama submitted his failure of conciliation report dated 26-7-1975 to the Ministry, who on receiving the same referred the dispute to this Tribunal for adjudication.

The management filed a written statement stating that the order of retrenchment passed by them in respect of the workmen in question is legal and justified in the circumstances of the case. They say that the workmen raised a similar dispute with the management for retrenching the workmen during the off-season in 1974 i.e. May to October and the said dispute was referred to the Arbitration of Shri A. S. Gupta, Regional Labour Commissioner (C), Bombay. The Arbitrator held that the retrenchment was legal and justified. He also held that the management should give option to the employees either to accept retrenchment compensation or opt for continuity of service by regularising the intervening period by grant of leave due or treating the period of absence during the off-season as leave without pay. They submit that during the Monsoon season ships will not be calling at the port

for taking the cargo of Iron Ore. They say that by May, 1975 they were having stock of Iron Ore worth Rs. 30 to 40 lakhs and their funds having thus got locked up they did not consider it economical to carry on the work of further extraction of Iron Ore. For that reason they temporarily closed their mines and retrenched the workmen in question.

This case having undergone several adjournments stood posted to 12-10-1977 on which date Shri Rele the learned Advocate appearing for the management filed a memorandum dated 23-9-1977 signed by Shri M. S. Rane, General Secretary, Rashtriya Mine Mazdoor Sangh, Redi and Shri A. B. Gogte, Partner, M/s. Gogte Minerals praying the Court for permission to withdraw this dispute in view of the amicable settlement of the dispute arrived at between the parties out of Court. Shri Dharap, the learned Advocate appearing for the workmen prayed for time till 31-10-1977 to ascertain from the Union whether the facts mentioned in the joint Memo. were correct. On 31-10-1977 Shri Dharap appeared in person before the Court and endorsed on the statement of claim that he is not pressing the demand in question.

In view of the joint Memo. filed by the parties seeking the permission of the Tribunal to withdraw this dispute and the endorsement made by Shri Dharap for the workmen on the statement of claim that he is not pressing the demand this reference must be closed.

For the aforesaid reasons no order need be passed on this reference except to say that this reference is closed in view of the Joint Memo. filed by the parties, a copy of which is appended to this order.

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer,

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 2 AT BOMBAY

Reference No. CGIT-2/19 of 1975

Employer in Relation To

The Management of Redi Iron Ore Mine of Messrs.
Gogte Minerals

AND

Their workmen

Subject : Industrial dispute between the workers represented by the Rashtriya Mine Mazdoor Sangh, Redi and M/s. Gogte Minerals, pertaining to retrenchment of workers in the month of May 1975.

May it please the Hon'ble Tribunal,

We, M/s. Gogte Minerals and the Rashtriya Mine Mazdoor Sangh, Redi beg to submit that the dispute referred to this Hon'ble Tribunal has been amicably settled between us, as per the Memorandum of Settlement dated 12th September 1977, signed at Bombay, before Hon'ble Shri Hussain Dalwal, Minister of Law & Judiciary, Govt. of Maharashtra.

In view of the settlement of the dispute, as per the said Memorandum of Settlement, we jointly request this Hon'ble Tribunal to permit us to withdraw the dispute pending before the Hon'ble Tribunal.

We request the Hon'ble Tribunal to pass suitable orders to the effect.

A. B. GOGTE, Partner,
M/s. Gogte Minerals.

Signed on : 23rd September, 1977.

M. S. RANE, General Secretary,
Rashtriya Mine Mazdoor Sangh, Redi.

[No. L-26012/11/75-DIVB/DII] B]

New Delhi, the 20th December, 1977

S.O. 4032.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal Madras, in the industrial disputes between the management of Messrs. Associated Cement Companies Limited, Madukkarai and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th December, 1977.

BEFORE THIRU K. SELVARATNAM, B.A., B.L.,

Presiding Officer,

Industrial Tribunal, Madras

(Constituted by the Central Government)

Monday, the 28th day of November, 1977

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 30 of 1977

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of M/s. Associated Cement Companies Limited, Madukkarai).

BETWEEN

The workmen represented by

The General Secretary, Kovai Mavatta Cement Thozhilalar Sangam, No. 17/225, Palghat Road, Madukkarai-641105, Coimbatore District.

AND

The Manager,

M/s. Associated Cement Companies Limited,

Madukkarai, Coimbatore District.

Reference :

Order No. L-29011/34/76-D, III-B, dated 17th May, 1977 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Friday, the 18th day of November, 1977 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiruvalargal K. Venugopal and K. Ayyaswamy, Assistant Secretaries of the Union and of Thiruvalargal T. S. Gopalan and S. Ranganathan, Advocates appearing for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following

AWARD

This is a reference by the Government of India under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of an industrial dispute between the Management of Messrs. Associated Cement Companies Limited, Madukkarai and their workmen.

(2) The matter under the reference is as follows :

"1. Whether the management of Messrs. Associated Cement Companies Limited, Madukkarai, P.O. Coimbatore District in promoting Shri Kumaran, T. No. 51, Driller from 'C' grade to 'B' grade with effect from 13-9-1974 overlooking the claims of the following drillers in 'C' grade namely (i) Shri S. Ramalingam, R. No. 13; (ii) Shri S. Veluswamy, T. No. 153, (iii) Shri S. Arumugham, T. No. 26; (iv) Shri Chinnakaruppan, T. No. 154 and (v) Shri Sankaran, T. No. 158 is justified? If not, to what relief are they entitled to and from what date?

2. What should be the criteria for promotion of "Jack Hammer Drillers" to the category of "Halco Drillers" and also whether the existing grades 'D' and 'C' only for Jack Hammer Drillers and Grades 'D', 'C' and 'B' for Halco Drillers are justified?"

(3) The General Secretary, Kovai Mavatta Cement Thozhilal Sangam has filed a claim statement, to which the Management filed a Counter Statement.

(4) The facts that are raised in this dispute are briefly as follows : The Factory in question manufactures cement. Cement is produced out of the limestones quarried in the area in and around Madukkarai in Coimbatore District. The limestones are quarried by drilling operations. Drilling operations consist of two methods, one by hand drilling called Jack hammer drilling and the other method by mechanical drilling called Halco drilling. The operators working on Jack hammer drills are classified into 'D' and 'C' grades. The workers working on Halco drills are classified into 'D', 'C' and 'B' grades. The grades in respect of Halco drilling carries more wages than the grades in Jack hammer drilling. Thiruvallargal S. Ramalingam and S. Veluswamy were engaged in Jack hammer drilling like Thiru Kumaran. Ramalingam and Veluswamy have put in about 10 years of service as Halco Driller whereas Kumaran had put in only 3 years of service as Halco driller. In spite of that, the claim of Ramalingam and Veluswamy was overlooked and Kumaran was transferred to Halco Drilling and it is clearly unjust and this has been done with mala fide intention to favour I.N.T.U.C. Union to which Kumaran belonged as against C.I.T.U. Union. The workers protested the action of the Management raising a dispute before the Assistant Labour Commissioner and the conciliation proceedings failed. So the matter was referred to this Tribunal. The Union's further contention is that a separate criteria for drilling categories alone could not be evolved as it will have its repercussions on other categories and grades in the establishment as well as the industry and it suggests the following : Jack Hammer Drilling category should be fitted in Grade 'C' and Halco Drilling category should be fitted in Grade 'B'. The senior-most in the category should be promoted to the next higher category. Those who have attained the ceiling in a particular grade should also be promoted to the next higher grade and this criteria should be followed for the future incumbents alone.

(5) The contention of the Management in their counter is : The classification has been done into five grades, viz., 'F' (unskilled), 'D' (Semi-skilled), 'C' (Skilled-lower), 'B' (Skilled-upper) and 'A' (Skilled-highly) as suggested by the Central Wage Board which was constituted in 1958. The grades are existing in the factory according to the classification. In the limestone quarries at Madukkarai drilling operation is done by Jack hammer drilling and Halco drilling. The Jack hammer drillers are classified into 'D' and 'C' grades. The Halco drillers are classified into 'D', 'C' and 'B' grades. Among the Jack hammer drillers, if any Jack hammer driller reaches the maximum in the 'D' grade and his work is satisfactory, he will be eligible to be considered for promotion to 'C' grade. The work in the Jack hammer drilling category is not treated as skilled labour, whereas the work in the Halco drilling is considered as skilled labour and the grades are 'D', 'C' and 'B' and 'B' grade is considered as an upper grade. If a Jack hammer driller shows efficiency and reaches the maximum ceiling level he is considered for Halco drilling and he is given a grade 'D' or 'C' or 'B' which is the upper grade in Halco drilling. In the present case, Kumaran had reached the ceiling level as Jack hammer driller and as such he was transferred to the category of Halco drilling and he reached the 'B' grade. There was no mala-fide conduct on the part of the Management in transferring Kumaran to Halco drilling category and it was done fairly as he had reached the ceiling level in Jack hammer drilling category, whereas the two persons Ramalingam and Veluswamy had not reached the ceiling level and when they reached the ceiling level they would be considered for transfer to Halco drilling category. They promoted Kumaran to 'B' grade in Halco drilling on justifiable ground, viz., his work, attendance, job knowledge and conduct were satisfactory and also reached the maximum in his grade. The allegation that Kumaran was promoted as a measure of favouritism is quite unfair. The Halco drillers in 'C' grade are not entitled to the promotion to 'B' grade as a matter of right. Even in the Jack hammer drilling category they are not entitled for promotion to 'C' grade automatically and they must prove their efficiency in their work and also bear good conduct. In laying down the criteria, seniority alone should not be the criteria for promotion and it has to be considered along with other factors like the efficiency and his conduct. The Management had acted fairly and justly in

promoting Kumaran to 'B' grade in Halco drilling category. Hence the award may be passed rejecting the claim of the workmen.

(6) The points that arise for determination are : (1) whether the Management was justified in transferring Kumaran overlooking the claims of Ramalingam and Veluswamy and (2) what is the criteria to be adopted for promotion in the two categories under reference.

(7) Point No. 1 : The grievance of the Union is that Kumaran who was put in only three years of service has been transferred to the category of Halco drilling overlooking the claims of Ramalingam and Veluswamy who have put in 10 years of service in the Jack hammer drilling. The contention of the Management is that the transfer of Kumaran to Halco drilling category was not based upon the seniority in service, but was based upon his technical skill, efficiency, conduct and reaching of the maximum ceiling limit in respect of wages in the Jack hammer drilling category and the Management did not discriminate the two persons on any other ground with mala-fide intention to help labourers belonging to I.N.T.U.C. as against C.I.T.U. In considering the contention of the Management, the Tribunal has to consider whether the Management was actuated by any dishonest intention in transferring Kumaran to 'B' grade in Halco drilling having regard to the facts and circumstances of this case. It is an admitted fact that Halco drilling requires a high technical skill, whereas Jack hammer drilling is only a simple device which any lay man can operate. Evidence was also let in by the Management by examining Thiru K.M.R. Reddy who is a Manager (Mining). He says that he is a qualified Mines Manager under the Mines Act and the Madukkarai Cement Factory is one of the 17 factories owned by the Associated Cement Companies Limited. Necessary material is obtained by drilling in the limestone block with the help of Jack hammers, Halco and Wagon drills. Jack hammer is a small drilling machine weighing about 35 to 40 kgs. and capable of drilling 1-1/2" diameter holes to a depth of 5 feet and it is manually operated by handling only one valve holding by hand and the work does not entail much skill and strain. On the contrary, Halco drill is a self propelled drilling rig, consisting of various air motors meant for different operations such as rotation, lowering or pulling out the drill rods and moving the machine from place to place and it is capable of drilling 4" diameter holes upto a depth of 100 feet and it is being worked by manipulating various valves. For operating Halco drilling, basic knowledge of compressed air motors and drilling is necessary. Thus from his evidence, it is clear that for Halco is a sophisticated machine, for which high technical skill is required. Therefore it is needless to say that it is absolutely necessary for a man to have necessary skill to be considered for transfer to Halco drilling category. Even W.W.1 Thiru S. Veluswamy, a driller who is working in the quarry from 1947 admits that he worked as a Jack hammer driller for 18 years before he was transferred as a Halco Driller and Halco drilling was a tough job and it also warrants technical skill in the matter of rod adjustment. It is not the case of the Union that Kumaran lacked any of the qualities and skill for operating Halco drilling machine. If the Management says, that aspect was considered while transferring Kumaran to Halco Drilling category, the Tribunal cannot attribute mala-fide intention to the Management. The one other aspect was taken into account in the case of Kumaran was his reaching the ceiling level in the grade of Jack hammer drilling. M.W.1 says that Kumaran reached the ceiling quicker than Ramalingam and Veluswamy and he was given additional special increment in recognition of his highest output in 1967 and he was drawing a personal allowance of 90 paise whereas the others were drawing only 60 paise. It is also seen from Ex. M-6 that Kumaran reached the maximum ceiling limit in his category in 'C' grade. It is no doubt true that Kumaran entered like any other worker as Jack hammer driller but due to his efficiency he earned increments and reached the maximum in his grade. Naturally, the Management to avoid stagnation, transferred him to Halco drilling category, so that he can earn higher wages and one cannot find fault with the Management for giving him opportunity to earn higher wages as an impetus in that category. Having regard to the technical skill involved, seniority in service alone cannot be the only criterion. It is also to be noted that some of the Jack hammer drillers had not opted for Halco drilling category as the work is very tough and it requires high degree of skill. As regards three other persons, Chinnakaruppan examined as W.W.2 says that he was working as Jack hammer

driller in the 'C' grade for the past 10 years, but he was not given a chance in Halco drilling. That instance has been cited by the learned counsel appearing for the Management on the erroneous assumption that it is a promotion and not a transfer. Having regard to the evidence in this case, I find that it is only a transfer and not a promotion and it depends upon several factors. Therefore, there cannot be any grievance against the Management if the Management had not chosen to transfer a person if he is not possessed of necessary qualifications. The division of labour as Jack hammer drillers and Halco drillers is similar to the division of labour prevailing in other factories and the basic principle evolving grades is similar to the principles adopted by the other Companies as seen from Exs. M-17 to M-21. Therefore having regard to the circumstances and facts of this case the Management was justified in transferring Kumaran to Halco drilling category. This point is answered in the affirmative.

(b) Point No. 2: As I discussed earlier, for transferring a person from Jack hammer drilling he should possess necessary skill and technical knowledge for operating a sophisticated machine like Halco drill, one cannot claim the transfer to the other category solely on the basis of seniority in service. For transfer of a person from Jack hammer category it has also to be considered as to whether a person in Jack hammer category has reached the maximum ceiling level in his grade and has attained necessary skill, and if it is so, it is the duty of the Management to transfer him to Halco drilling category. Suitability of the candidate to a particular job is to be left to the discretion of the Management in the interest of the prosperity of the factory. Therefore, it is not for the Tribunal to lay down a hard and fast rule of selection of candidates for a particular job especially when the job entails high degree of technical skill and labour. This Tribunal can intervene only when other things being equal, the Management acts in disregard of all cannons of justice, with mala-fide intention. The legitimate right of the worker for promotion or transfer arises only if the worker is suitable for a job. This point is answered accordingly.

(9) There are only two categories for Jack hammer drillers, i.e., 'D' and 'C' and a person is first entertained in the 'D' grade and later promoted to 'C' grade, whereas in the Halco drilling there are three grades 'D', 'C' and 'B'. When a person is entertained in the 'D' grade, he will be promoted to 'C' grade and finally to 'B' grade. The contention of the Union is that distinction should go. I do not agree with the contention of the Union for the following reasons: In the Jack hammer drilling operation, one need not have special skill to operate the machine and it is sufficient if he holds on the machine. Therefore Jack hammer drilling category is only in the nature of unskilled or semi-skilled work, whereas in the other category only a skilled labourer can alone be employed and the degree of skill varies according to the capacity and experience of that person employed and naturally there are three grades in Halco drilling so that when one reaches 'B' grade he should be highly skilled person. Having regard to the nature of the work involved in the two categories it is futile to compare the grades in both the categories. It also appears that such a distinction is based upon from the recommendations of the Central Wage Board for the Cement industry constituted in 1958. Therefore, the grades existing in the respective categories are well justified.

(10) In the result, an Award is passed rejecting the claims of the Union.

Dated, this 28th day of November, 1977.

Sd/- eligible
Presiding Officer

WITNESSES EXAMINED

For workmen

W.W. 1—Thiru S. Veluswamy.

W.W. 2—Thiru N. Chinnakaruppan.

For Management

M.W. 1—Thiru K. M. R. Reddy, Manager (Mining).

DOCUMENTS MARKED

For workmen

Ex. W-1/12-3-75—Letter from the Union to the Management regarding change of grade given to Thiru Kumaran.

Ex. W-2/30-3-76—Letter from the Union to the Assistant Labour Commissioner (Central) II, Madras raising dispute.

For Management

Ex. M-1/12-10-75—Letter from the Union to the Labour Enforcement Officer, Coimbatore regarding change of grade given to Thiru Kumaran. (copy).

Ex. M-2/18-10-75—Letter from Labour Enforcement Officer(C), Coimbatore to the Management enclosing Ex. M-1 for remarks. (copy).

Ex. M-3/31-10-75—Letter from the Management to the Labour Enforcement Officer (Central), Coimbatore submitting remarks on Ex. M-1. (copy).

Ex. M-4/28-4-76—Minutes of discussions held at the office of the Labour Enforcement Officer (Central), Coimbatore. (copy).

Ex. M-5/7-5-76—Conciliation failure report. (copy).

Ex. M-6/12/14-7-76—Statement showing the list of drillers who reached ceiling of grades on 13-2-73 and the promotions granted. (copy).

Ex. M-7/16-7-76—Letter from the Union to the Assistant Labour Commissioner (Central)-I, Madras requesting to take action to change the grades of the affected workers. (copy).

Ex. M-8/16-8-76—Conciliation failure report. (copy).

Ex. M-9/14-9-76—Letter from the Government to the parties deciding not to refer this dispute to the Industrial Tribunal. (copy).

Ex. M-10—Extract of I Wage Board Report regarding fixation of differentials.

Ex. M-11—Extract of First Wage Board Report regarding Basic wage scale for daily rated operatives.

Ex. M-12—Extract of II Wage Board Report regarding basic wage scale for daily rated operatives.

Ex. M-13—Extract from the settlement dated 7-5-1975 revising wage scale for operatives from 1-5-75.

Ex. M-14—Statement showing promotions of Quarry drillers from 1969 to 1976.

Ex. M-15—Statement giving details of drillers employed and their wage increase from 1-1-1967.

Ex. M-16/6-6-77—Letter from the Management to Madras Cements, Thulukkappatti requesting particulars in respect of drillers. (copy).

Ex. M-17/-6-77—Reply letter from Tamil Nadu Cement Corporation Ltd., furnishing particulars in respect of Quarry drillers. (copy).

Ex. M-18/8-6-77—Letter from Chettinad Cement Corporation Ltd., Puliur to the Management furnishing particulars in respect of Quarry drillers. (copy).

Ex. M-19/4-7-77—Letter from the India Cements Ltd. to the Management furnishing details about Quarry Drillers. (copy).

Ex. M-20/8-7-77—Letter from the Dalmia Cement (Bharat) Ltd. to the Management furnishing details about Quarry drillers. (copy).

Ex. M-21/26-7-77—Letter from the India Cements Ltd., to the Management furnishing particulars in respect of quarry drillers. (copy).

Ex. M-22—List of Halco drillers as on 1-9-1977.

Ex. M-23—Extract from the Standard list of occupational nomenclatures prepared by the Director General of Resettlement and Employment.

Sd/- Illegible
Presiding Officer

Note : Parties are directed to take return of their document(s) within six months from the date of the Award.

[No. L-29011/34/34/76-D. IIIB]

MANJIT SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 23rd December, 1977

S.O. 4033.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of National and Grindlays Bank Ltd., Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 2-12-77

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

PRESENT

J. Narain Esqr., M.A., B.L.,

Presiding Officer.

Reference No. CGIT-24 of 1975

Parties :—Employers in relation to National Grindlays Bank Ltd., Bombay,

AND

Their workmen.

Appearances :

For the Employers : (1) Shri V. V. Pal, Advocate,

(2) Shri S. D. Vimadalal, Senior Counsel.

For the workmen : (1) Shri Madan Phadnis, Advocate.

(2) Shri P. N. Subramanyan,

General Secretary,

National & Grindlays Bank

Employees' Union, Bombay.

Industry :

Banking.

State :

Maharashtra.

Bombay, dated the 3rd November, 1977

AWARD

1. The Government of India by their Order dated the 16th May, 1975, in exercise of powers conferred by Sec-

tion 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

SCHEDULE

"Whether the management of the Messrs National and Grindlays Bank Limited, Bombay is justified in introducing 'mechanisation' at Bombay main office and Current Accounts Departments of its Branches at Bombay ? If so, to what extent and to what relief the workmen are entitled ?"

2. Simultaneously there was a Reference pending before this Tribunal, namely Ref. No. CGIT-1 of 1975. The dispute there was the same, the relief portion, however, was slightly different as will appear from the Schedule appended to the Government of India Order dated the 23rd December, 1974. The subject matter of dispute was the following :—

"Whether the management of M/s. National and Grindlays Bank Ltd., Bombay is justified in introducing mechanisation at its Bombay Main Office and the Current Accounts Departments of its Branches in Bombay ? If not, to what relief are the workmen entitled ?"

3. When this Reference was taken up for hearing the National & Grindlays Bank Employees' Union (hereinafter referred to as the 'Union') submitted that the matter referred for adjudication by the Government of India by their Order dated the 23rd December, 1974 was not the dispute in which the Union was interested and since the dispute in which the Union was interested has been referred by the Government of India by its Order dated 16th May, 1975, the Union was not interested in pursuing the Reference No. CGIT-1 of 1975. My predecessor-in-office was of the view that since the Union did not press for adjudication of the Reference and the Management had not filed any counter to the application, he, therefore, dismissed the Reference for non-prosecution by his Order dated the 12th June, 1975.

4. Shortly stated the history of the dispute is that the Bank in its five branches in Bombay introduced mechanisation rendering large number of senior employees as surplus and compelled them to do odd jobs and some of them were made to sit idle. When the Bank initiated certain steps towards mechanisation in reorganising its Current Accounts Departments, the Union wrote a letter to the Bank on the 26th December, 1972 requesting them to withdraw the notice of reorganisation until the matter was discussed with the Union. Another letter to the same effect was sent on 26th February, 1973. The matter went also to the Assistant Labour Commissioner, but it is said that due to the non-effective intervention of the Assistant Labour Commissioner the Bank took further advantage of the situation and intensified its scheme of mechanisation. Ultimately the dispute was taken in conciliation, but the Conciliation Officer submitted his failure report.

5. Permission to introduce mechanisation was granted to the Banks under the first Bipartite Settlement dated 19-10-1966. Chapter No. VI which was on mechanisation inter-alia provides as follows :—

".....

(iii) that there will be no retrenchment on the introduction of the machines as in (i) and (ii) above and the displacement of staff in a particular department

or office/branch where such machines are introduced will be kept at the minimum possible level.

6.2 The workmen or their representatives will not object to the introduction of machines, as mentioned above and to the consequent reorganisation.

6.3 The question whether the scope of utilisation of the machines referred to above can be extended or not, will be considered afresh as early as possible after 31-12-1968."

6. The contention of the Union is that true it is that the Bank did not resort to any retrenchment, but subsequent action of the Bank amply showed the sinister move to effect the drastic retrenchment in the Bombay Branches. As against the total number of 112 clerks in the Current Accounts Department, after mechanisation of these five branches 71 clerks have been displaced. Even though no job of Peons are mechanised the Bank has rendered 10 Peons as surplus and displaced them from the department out of the earlier strength of 30 Peons.

7. The National & Grindlays Bank Ltd. (hereinafter referred to as the 'Bank') has raised certain preliminary issues. They have contended that the subject matter of the Reference is covered by the First Bipartite Settlement and continued by the subsequent two Settlements and, therefore, the present Reference made during the currency of the Settlement is bad in law. The Reference is also premature in as much the procedure set out in para 31 of the Second Bipartite Settlement dated 12th October, 1970 has not been followed and/or exhausted. Attack has been made upon the wordings used in the Order of Reference. It is contended that even in the event the Bank's action be held to be not justified, no relief can be granted to the workmen because the terms of reference are that the question of relief is to be considered only if the action is justified. The workmen have already withdrawn or given up or disclaimed the right to claim relief in Reference No. CGIT-1 of 1975, as such the present Reference is barred by res-judicata or principles thereof. The Bank denied that any employee was found surplus and that the senior employees were compelled to do odd jobs or were made to sit idle. The Bank introduced mechanisation for the first time in 1942. Nearly all the workmen/staff of the Bank are persons who joined their service after 1942 and the fact that mechanisation was in existence before they joined must have made them aware that when there was great pressure of work and/or when speed and accuracy was required, machines were being used. This obvious knowledge of the state of affairs would show that the employees cannot take exception to mechanisation. Further the question of introduction of mechanisation is entirely a part of the management function and falls within the frame-work of Chapter VI of the First Bipartite Settlement. Mechanisation in the Bank has been introduced in terms of First Bipartite Settlement dated 19-10-1966. When machines were introduced, necessarily the work of posting ledger by hand was eliminated and, therefore, the ledger keepers who used to write were displaced; meaning thereby that some other type of work was given to them.

8. Since the matter was argued only on the preliminary points I propose not to refer to other points referred to in the two statements of claim.

9. It has been strenuously argued for the Bank that the present Reference is not maintainable inasmuch as it was made

during the pendency of Reference No. CGIT-1 of 1975 which would mean that the government cancelled that Reference and made the present reference. In support of this contention, reliance is placed upon State of Bihar & Ganguli (D.N.) and others (1958 II LLJ page 634). In this case dispute between the Management of Bata Shoe Company Ltd. & their 31 workmen was referred by Notification dated 8th October, 1954. The dispute was whether the dismissal of the workmen was justified; if not, whether they were entitled to reinstatement or any other relief. This was Ref. No. 10 of 1954. On 15th January, 1955, a similar industrial dispute between the same Bata Shoe Company Ltd. & its 29 other workmen was referred which was numbered as Reference No. 1 of 1955. These two references were consolidated by the Industrial Tribunal. When these two references had made some progress, the Government of Bihar issued a third Notification dated 17th September, 1955, by which it purported to supersede the two earlier notifications, to combine the said two disputes into one dispute, to implead the two sets of workmen involved in the two said disputes together and to refer the same to the adjudication of the Industrial Tribunal. The dispute thus referred to was "whether the dismissal of the 60 workmen mentioned in Annexure B was justified or unjustified; and to what relief, if any, those workmen are entitled?" It was held by the Supreme Court that after the dispute is referred to the Tribunal during the continuance of the reference proceeding, it is the Tribunal which is seized of the dispute and which can exercise jurisdiction in respect of it. Accordingly, the third notification was held invalid and ultra vires. Regard being had to the above decision, it must be held that in the instant case the Central Government had no jurisdiction to make the present reference and accordingly it must be held to be incompetent.

10. In the First Bipartite Settlement dated 19-10-1966 the employees were represented by All India Bank Employees' Association and All India Bank Employees' Federation. Chapter VI of the Settlement refers to the subject of mechanisation and relevant provision thereof has already been reproduced while stating the facts of the case. It was to be binding on the parties for three years from 1st January, 1966 to 31st December, 1968 and "shall continue to be binding even thereafter until either party gives to the other two months' notice in writing of intention to terminate this settlement". This was followed by two other Settlements; second one was dated 12th October, 1970 and the third one dated 8th November, 1973. Both the All India Bank Employees' Association & the All India Bank Employees' Federation were parties to the Second Settlement whereas only the All India Bank Employees' Association was a party to the Third Settlement. Provision regarding mechanisation as set out in the First Bipartite Settlement remained unaffected by the subsequent two Settlements. The Second Settlement came into force with retrospective effect from 1st January 1970 and "shall be binding on the parties for four years from 1st January 1970 to 31st December, 1973 and shall continue to be binding even thereafter until either party gives to the other two months' notice in writing of intention to terminate this Settlement". Regarding resolving disputes, para 31 reads as follows :—

"If any doubt or difficulty arises regarding interpretation of any provision of this Settlement, the matter will be taken up only at the level of Indian Bank's Asso-

ciation and the All India Bank Employees' Association for discussion and settlement."

The Third Settlement "shall be binding on the parties upto 31st December, 1973 and shall continue to remain binding thereafter until either party gives to the other two months' notice in writing of intention to terminate this Settlement." It also contained a provision similar to para 31 of the Second Settlement.

11. Relying on the Union's own case that there has been no retrenchment and what is stated in paragraph 6.2 of the Chapter VI on mechanisation of the First Bipartite Settlement regarding no right of objection to the introduction of machines and the provisions of Sections 18 & 19 of the Industrial Disputes Act, it has been argued for the Bank that the Union, which admittedly is affiliated to the All India Bank Employees' Association, cannot be allowed to raise the present industrial dispute. Section 18(1) says that the settlement arrived at by agreement between the employer and the workmen, otherwise than in the course of conciliation proceeding, shall be binding on the parties to the agreement. Speaking on the period of operation Section 19(2) says that the settlement "shall continue to be binding on the parties after the expiry of the period aforesaid, until the expiry of two months from the date on which a notice in writing of an intention to terminate the settlement is given by one of the parties to the other party or parties to the settlement." It is common round that no such notice to terminate the settlement has been given.

12. For the Union it was vehemently argued that the three Settlements cannot stand in the way of the present Reference inasmuch as it has not been signed by a registered Trade Union. In support of this contention, reference was made to Sections 2(p), 36 & Rule 58 of the Industrial Disputes (Central) Rules and section 2(h) of the Trade Union Act of 1926. Section 2(p) defines settlement and it contemplates signing of agreements by the parties thereof in such a manner as may be prescribed. Rule 58 lays down that the settlement shall be in Form 'H' and it shall be signed by....."(b) in the case of workmen, by any officer of a trade union of workmen or by five representatives of the workmen duly authorised in this behalf at a meeting of the workmen held for the purpose." Relying on Section 36, it was argued that for the purpose of representation the Industrial Disputes Act makes a distinction between a registered Trade Union and Federation of Trade Unions. Section 2(h) of the Trade Unions Act says that a trade union includes any federation of two or more trade unions. It has been stated at the Bar that the All India Bank Employees' Association was registered in 1975, that is, not when the settlements were made. For the Bank it was submitted that Rule 58 nowhere speaks that the settlement shall be signed by a registered trade union nor there is any such provision in the Industrial Disputes Act. It is not necessary for the present purpose to consider whether and if so, for what purpose Industrial Disputes Act makes a distinction between the registered Trade Union and an unregistered Trade Union. Suffice it to say that for the settlement to be binding the Act does not contemplate its signing by a registered Trade Union or an Association of Trade Unions.

13. Next it was argued for the Union that the demand is not for a change of conditions in service, but in furtherance of

settlement; what they want is that injustice that has been done to them while implementing the settlement should be undone. For this purpose reference was made to the word 'displacement' and it was urged that the kind of mechanisation that has been resorted to has resulted in retrenchment and this is in violation of the settlement. For the Bank it was submitted that the result of mechanisation was not retrenchment, but displacement of workmen. Regard being had to the contentions of the parties manifestly, there is dispute as to interpretation of the word 'displacement' occurring in the settlement. That being so, the forum of agitating this question should be as provided in para 31 of the Second Settlement and not in a Reference. For the above reasons, I agree with the Bank that so long as no notice of terminating the Settlement is served the present Reference is not maintainable.

14. It was next argued for the Bank that Ref. No. CGIT-1 of 1975 having been dismissed for non-prosecution, the present Reference is barred by res-judicata. This contention cannot be upheld since the aforesaid Reference did not finally and substantially decide the dispute in question.

15. Some argument was also advanced that the statement of claim, which has been filed by the Union, does not disclose any cause of action. As against this, the learned Counsel for the Union referred to paragraphs 3, 4, 10, 14, 23, 28, 29, 46, 62, 64, 69, 70, 71, 97 & 99 of their statement of claim. Alternatively, it was argued that all the provisions of the Code of Civil Procedure do not apply to a Reference under the Industrial Disputes Act. Regard being had to the view that I have taken of the above, it is not necessary to decide this question at the present stage.

16. Some argument was also advanced that the wordings of the present Reference are such that no effective order can be passed by this Tribunal. In the first place, it was urged that the Tribunal is not required to pronounce whether the Bank was unjustified in introducing mechanisation. Secondly, according to the second sentence of the Schedule of the Order of Reference if the introduction of the Scheme was justifiable, manifestly no relief can be afforded to the workmen. I do not agree with the submission made. The first sentence, in fact, contemplates adjudication whether the introduction of the Scheme was justified or unjustified. If it was justified the workmen will be entitled to no relief. In the circumstance, the Reference can be answered effectively.

17. In the result, I hold that the Reference is not maintainable and it is answered accordingly.

J. NARAIN, Presiding Officer,

[No. L-12011/17/74-LR. III]

JAGDISH PRASAD, Under Secy.

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th August, 1977

S.O. 4034.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1598, dated the 21st May, 1977, published in Part II Section-3, Sub-Section (ii) on the

Gazette of India, dated the 28th May, 1977 for sub-paragraphs (ii) and (iii) read the following namely :—

- “(ii) Government securities as defined in clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by any State Government. (iii) Any other negotiable securities or bonds, the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government.” } Not less than 25%”

[No. G. 27035(5)/76-PFI(i)]

CORRIGENDUM

S.O. 4035.—In the notification of the Government of India, Ministry of Labour No. S.O. 1599, dated the 21st May, 1977, published in Part II, Section-3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 28th May, 1977, for sub-paragraphs (ii) and (iii) read the following namely :—

- “(ii) Government securities as defined in clause (2) of Section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by any State Government. (iii) Any other negotiable securities or bonds, the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government.” } Not less than 25%”

[No. G. 27035(5)/76-PFI(ii)]

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1977

क्रा०श्रा० 4036.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शक्ति एक्सपोर्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, “पाको हाउस” 74-बी, कान्दिवली इन्डस्ट्रियल एस्टेट, कान्दिवली (पश्चिम), मुम्बई 67, नामक स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 जून, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018 (92)/77 पी० एफ० II]

New Delhi, the 12th December, 1977

S.O. 4036.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shakti Exports (Private) Limited, “Paco House” 74-B, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West), Bombay-67, have agreed that the provisions of the Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1975.

[No. S. 35018(92)/77-PF. II]

क्रा०श्रा० 4037—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बागमल निटिंग इन्डस्ट्रिज 28ए-डी गवर्नमेंट इन्डस्ट्रियल एस्टेट कान्दिवली (पश्चिम), मुम्बई 67 जिसमें 30, जम्बूल वादी, कालबादेवी, मुम्बई 2 स्थित उसकी शाखा भी सम्मिलित है, नामक स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018(93)/77-पी० एफ० II]

S.O. 4037.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bagamal Knitting Industries 28, A-D-Government Industrial Estate, Kandivli (West), Bombay 67 including its branch at 30, Jambool Wadi, Kalbadevi, Bombay-2, have agreed that the provisions of the Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1976.

[No. S. 35018(93)/77-PF. II]

क्रा०श्रा० 4038—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रंगाम्बायी एण्ड कम्पनी (कोयम्बटूर) सं० 52, 11 बी मेन रोड मालेश्वरम, बंगलोर 55, जिसमें उसका तीसरी मंजिल सं० 75 काला-सीपालायम, न्यू ऐक्सपेंशन, पोस्ट बाक्स सं० 6872 बंगलोर-2 स्थित बिक्रय और शी रूम भी सम्मिलित हैं, नामक स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मई, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम० 35019(352)/77 पी०एफ० II]

S.O. 4038.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rangu-swamy and Company (Coimbatore), No. 52, 11th Main Road, Malleswaram, Bangalore-55, including its Sales and Show Room, 2nd Floor No. 75, Kalasipalyam, New Extension, Post Box No. 6872, Bangalore-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1977.

[No. S. 35019(352)/77-PF. II]

का० प्रा० 4039.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रीमियर मंगनीज और कार्पोरेशन, चिपुरपल्ली, श्रीकाकुलम जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम० 35019(416)/77 पी०एफ० II]

S.O. 4039.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Premier Manganese Ore Corporation, Chipurupalli, Srikakulam District, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1976.

[No. S. 35019(416)/77-PF. II]

का० प्रा० 4040.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बोस गार्डन स्टेट, कुत्ता, दक्षिण कुर्ग, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मिनम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम० 35019(420)/77 पी०एफ० II]

S.O. 4040.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bose Garden Estate, Kutta, South Coorg, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Mis-

cellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made application to said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1977.

[No. S. 35019(420)/77 P.F. II]

का० प्रा० 4041.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 जुलाई, 1977 से मैसर्स बिन्द वेल, मुकुन्द निवास, उदुपी नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस 35019(421)/77 पी०एफ० II(ii)]

S.O. 4041.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty first day of July, 1977, the establishment known as Messrs Bind Well, Mukund Nivas, Udupi, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(421)/77-PF. II(ii)]

का० प्रा० 4042.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम० डी० फ्रांसिस एण्ड सन्स, फर्नीचर मरचेंट्स एम० जे० पी० रोड पोस्ट बाक्स नं० 6596, बंगलोर-2, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 जून, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(422)/77-पी०एफ०-II]

S.O. 4042.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs M. D. Francis and Sons, Furniture Merchants, S.J.P. Road, Post Box No. 6596 Bangalore-2, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1977.

[No. S. 35019(422)/77-PF. II]

का० प्रा० 4043.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री वेंकट राजू इंजीनियरिंग वर्क्स, अरिकापोटा, सन्नूर (टी० क्यू), श्रीकाकुलम जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जून, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019(423)/77-पी० एफ० II]

S.O. 4043.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Venkat Raju Engineering Works, Arikathota, Salur (TQ), Srikakulam District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1977.

[No. S. 35019(423)/77-PF. II]

क्रा० प्रा० 4044.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पी० एस० एंड कम्पनी, पोस्ट बॉक्स नं० 31, विशाखापत्तनम, नामक स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019(424)/77-पी० एफ० II]

S.O. 4044.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs P. S. and Company, Post Box No. 31, Visakhapatnam, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1977.

[No. S. 35019(424)/77-PF. II]

क्रा० प्रा० 4045.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दि नरसम्पत कोआपरेटिव एग्रिकल्चरल डेवेलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, नरसम्पत, वरांगल जिला, नामक स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 मार्च, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019(425)/77-पी० एफ० II]

S.O. 4045.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Narsampet Co-operative Agricultural Development Bank Limited, Narsampet, Warangal District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1977.

[No. S. 35019(425)/77-PF. II]

क्रा० प्रा० 4046.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जेपीका केमिकल इंडस्ट्रीज (इन्डिया), ए०-1/7, जेपीका हाउस, कृष्णा नगर, दिल्ली-51, नामक स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 नितम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019(427)/77-पी० एफ० II]

S.O. 4046.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jepika Chemical Industries (India), A-1/7, Jepika House, Krishan Nagar, Delhi-51, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1976.

[No. S. 35019(427)/77-PF. II]

क्रा० प्रा० 4047.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बरीना केबल इंडस्ट्रीज, 308/3, शाबजादा बाग, रोहतक रोड, नई दिल्ली-35, नामक स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019(428)/77-पी० एफ० II]

एस० एस० सहस्रानामन, उप सचिव,

S.O. 4047.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Darina Cable Industries, 308/3, Shabzada Bagh, Old Rohtak Road, New Delhi-35, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1976.

[No. S. 35019(428)/77-PF. II]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 14

क्रा० क्र० 4048.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 36 के अनुसरण में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के

कर्मचारी राज्य

31 मार्च, 1976 को समाप्त

व्यय

पिछला वर्ष (1974-75)	लेखा शीर्ष	राशि	जोड़
रुपए		रुपए	रुपए
	1 बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को हितलाभ		
	क चिकित्सा हितलाभ		
24,98,12,608	(1) चिकित्सा उपचार तथा प्रभूति सुविधा आदि की व्यवस्था पर होने वाले खर्च में निगम के शेयर के रूप में राज्य सरकारों आदि को अदायगियां	30,80,17,039	
	घटाएं—		
	वर्ष के दौरान चिकित्सा देख-रेख की बाबत राज्य सरकारों को ऐसी अदायगियां जो पूंजीगत निर्माण/चिकित्सा आरक्षित निधि में अन्तरिम की गईं		
24,98,12,608		30,80,17,039	
1,51,80,638	(2) चिकित्सा उपचार तथा देखरेख तथा प्रभूति सुविधाएं (निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए गए खर्च)	1,94,95,306	
26,49,93,244	जोड़—क-चिकित्सा हितलाभ		32,75,12,345
	ख नकद हितलाभ		
11,35,35,831	(1) बीमारी हितलाभ	12,81,80,389	
1,14,66,000	(2) विस्तारित बीमारी हितलाभ	1,40,17,842	
86,03,288	(3) प्रभूति हितलाभ	1,02,64,653	
	(4) अपंगता हितलाभ		
2,07,65,636	(क) अस्थायी	248,54,977	
3,42,19,000	(ख) स्थायी (पंजीकृत मूल्य)	5,42,40,000	
93,97,000	(5) आश्रितजन हितलाभ (पूंजीगत मूल्य)	1,16,99,000	
8,96,653	(6) अस्पष्ट हितलाभ	8,96,585	
19,88,74,388	जोड़—ख-नकद हितलाभ		
	ग--अन्य हितलाभ		24,41,52,346
74,890	(क) अपंग बीमा कृत व्यक्तियों के पुनर्वास पर व्यय	33,683	
2,44,176	(क) चिकित्सा मंडल तथा अपील अधीकरण	3,15,771	
	(ग) बीमा-कृत व्यक्तियों को अदायगियां		
1,14,139	1. सवारी खर्च तथा/या मजदूरी की हानि	1,36,509	
--	2. परिवार नियोजन के अन्तर्गत प्रसांगिक व्यय	--	
--	(घ) सहायता अनुदान	--	
2,25,623	(ङ) विविध	2,35,864	
6,58,728	जोड़—ग--अन्य हितलाभ		7,21,817
46,45,26,360	बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को कुल हितलाभ		57,23,86,508
	2. प्रशासन व्यय		
	(क) अधीक्षण		
69,556	1. निगम, स्थायी समिति, क्षेत्रीय बोर्ड आदि	57,683	
1,81,013	2. प्रधान अधिकारी	2,30,286	
36,64,180	3. अन्य अधिकारी	45,15,561	
1,97,92,448	4. लिपिक वर्गीय स्थापना	2,38,73,028	
35,21,247	5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	43,07,210	
79,34,854	6. आकस्मिक व्यय	98,82,613	
3,51,63,298	जोड़--क--अधीक्षण		4,28,66,371
	ख--फील्ड कार्य		
9,87,722	1. अधिकारी	9,02,917	
1,99,03,554	2. लिपिक वर्गीय स्थापना	2,34,96,864	
33,81,517	3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	38,10,214	
21,55,958	4. आकस्मिक व्यय	24,51,084	
2,64,28,751	जोड़--ख--फील्ड कार्य		3,06,61,079
52,61,18,409	भाग ले जाया गया जोड़		64,59,13,958

दिसम्बर 2 1977

वर्ष 1975-76 संबंधी परीक्षित लेखे तथा उनके संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्टें भ्राम सूचना के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बीमा निगम

वर्ष का भ्राम व्यय लेखा

		भ्राम	
पिछला वर्ष (1974-75)	लेखा शीर्ष	राशि	जोड़
रुपए		रुपए	रुपए
	1 अंशदान		
60,34,74,995	नियोजको तथा कर्मचारियों का शेयर	73,15,86,339	
2,16,80,542	केवल नियोजको का शेयर	1,78,07,427	
1,00,74,058	केवल कर्मचारियों का शेयर	1,00,09,537	
63,52,29,595	कुल अंशदान		75,94,03,303
	निगम द्वारा चिकित्सा हितलाभ पर प्रारंभिक रूप से किये गये व्यय में राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्रों का शेयर]	9,04,702	
22,50,000			9,94,702
	— सहायता अनुदान, अन्य राजस्व शीर्ष		
3,47,90,454	व्याज तथा लाभांश	4,29,03,524	
1,55,75,398	सुआवजे	64,48,911	
	किराया रेट तथा कर		
5,58,488	(1) निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	6,91,664	
1,82,59,511	(2) अस्पताल, औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टर्स	2,47,78,048	
93,042	शुल्क, जुर्माना तथा जल्सी	1,69,145	
29,63,122	विविध	17,47,435	
7,22,40,015	अन्य राजस्व शीर्षों का जोड़		7,67,38,727

70,97,19,610 भ्राम ले जाया गया जोड़

83,71,36,732

पिछला वर्ष (1974-75)	लेखा शीर्ष	राशि	गोड़
रुपये		रुपये	रुपये
52,61,18,409	पीछे से लाया गया जोड़		64,59,13,058
	ग—अन्य खर्च		
2,81,330	1. विविध खर्च	2,72,245	
29,282	2. बीमा न्यायालय	3,05,080	
26,133	3. प्रचार तथा विज्ञापन खर्च	22,127	
61,046	4. बैंक लेखे रखने के व्यय	69,319	
1,29,950	5. सेवा परीक्षा शुल्क	1,39,635	
96,818	6. छुट्टी तथा पेंशन भ्रमण	1,22,199	
2,14,695	7. कार्यालय भवन/स्टाफ कारों का मूल्य ह्रास	2,53,606	
4,99,829	8. कार्यालय/भवनों की मरम्मत व अनुरक्षण	6,28,474	
	9. सेवा-निवृत्ति हितलाभ		
42,65,343	(क) निगम के कर्मचारियों के लिये पेंशन आरक्षित निधि	40,51,493*	
2,22,357	(ख) क० रा० बी० निगम भविष्य निधि में निगम का भ्रमण	2,51,088	
15,92,389	(ग) क० रा० बी० निगम भविष्य निधि में दिया गया भ्याज	19,46,119	
—	(घ) निवेश की बसूली पर हानि	—	
(-) 29,59,007	(ङ) घटायें भविष्य निधि बकायों के निवेश पर प्राप्त भ्याज	(-) 39,13,674	
12,250	10. अनुकम्पा आरक्षित निधि	29,240	
	11. भविष्य निधि जमा राशि से जुड़ी बीमा निधि	50,000	
4,506	12. विविध	8,104	
6	13. हानियाँ	—	42,35,055
44,76,927	जोड़—ग—अन्य खर्च		
6,60,68,976	जोड़ शीर्ष 2—प्रशासन व्यय		7,77,62,505
	3. अस्पताल एवं औषधालय		
24,83,087	1. चिकित्सालय इमारतों का मूल्य ह्रास	23,92,287	
71,00,034	2. अस्पतालों/औषधालयों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	69,91,495	
95,83,121	जोड़ शीर्ष 3—अस्पताल एवं औषधालय		93,83,782
	4. पूंजीगत निर्माण/आपात आरक्षित निधि		
6,35,22,960	1. पूंजीगत निर्माण	7,59,40,330	
2,12,03,639	2. आपात आरक्षित निधि	2,03,32,720	
8,47,26,599	जोड़ शीर्ष 4—पूंजीगत निर्माण/आपात आरक्षित निधि		9,62,73,050
62,49,05,056	राजस्व लेखा पर कुल व्यय		75,58,05,845
8,48,14,554	व्यय से अधिक धाय सुलन पत्र में ले लाई गई		8,13,30,887
70,97,19,610	कुल जोड़		83,71,36,732

* इसमें निदेशक (चिकित्सा दिल्ली के कार्यालय के कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी देयता की बाबत 4,74,182 रुपये की वह राशि शामिल है जो

नई दिल्ली

दिनांक 31 मई, 1976

पिछला वर्ष (1974-75)	लेखा पीछे	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
70,97,19,610	पीछे से लाया गया जोड़		83,71,36,732

70,97,19,610 कुल जोड़

83,71,36,732

विस्ती प्रशासन के साथ शेयर योग्य व्यय के रूप में “(क) (11) चिकित्सा हितलाभ के अन्तर्गत सम्मिलित है।

हस्ताक्षरित (पी० एल० गुप्ता)
 वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
 कर्मचारी राज्य बीमा निगम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
31 मार्च, 1978 की स्थिति का तुलन पत्र

पिछला वर्ष (1974-75)	व्ययार्थ	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
	व्यय से अधिक आय का अतिशेष		
58,13,76,353	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	66,61,90,907	
8,48,14,554	वर्ष के दौरान संचयन	8,13,30,887	
66,61,90,907		74,75,21,794	
---	घटायें—पिछले वर्ष के संचयन से आपात प्रारक्षित निधि में अन्तर्गत राशि	---	
66,61,90,907			74,75,21,794
	पूँजीगत निर्माण प्रारक्षित निधि		
14,01,15,495	आदि शेष	21,04,24,339	
---	व्यय से अधिक आय के अतिशेष के अन्तर्गत राशि	---	
6,35,22,960	जोड़ वर्ष में की गई धन व्यवस्था	7,59,40,330	
67,85,884	निवेश पर प्राप्त ब्याज	1,13,02,800	
---	घटायें—वर्ष में की गई अदायगियाँ	---	
21,04,24,339			29,76,67,469
	म्हार्ड (आंशिक तथा पूर्ण अर्पणता हितबद्ध प्रारक्षित निधि)		
10,01,29,732	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	11,61,23,653	
3,42,19,000	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	5,42,40,000	
76,42,100	निवेश से प्राप्त ब्याज	99,05,014	
1,35,172	निवेशों की वसूली पर लाभ	---	
14,21,26,004	इस शीर्ष का आगे ले जाया गया जोड़	18,02,68,867	
(-) 2,60,02,351	घटायें—वर्ष के दौरान की गई अदायगियाँ	(-) 2,96,42,742	
11,61,23,653			15,06,25,925
	आश्चिन्तों के हितलाभ		
	प्रारक्षित निधि		
4,86,32,421	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	5,71,34,491	
93,97,000	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	1,16,99,000	
41,00,346	निवेशों से प्राप्त ब्याज	51,98,646	
1,17,785	निवेशों की वसूली पर लाभ	---	
6,22,47,552		7,40,32,137	
(-) 51,13,061	घटायें—वर्ष के दौरान की गई अदायगियाँ	(-) 57,96,685	
5,71,34,491			6,82,35,452
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि		
2,19,38,188	पिछले तुलनपत्र के अनुसार जोड़े—वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	2,53,87,089	
65,23,706	(1) कर्मचारियों का अंशदान	78,78,103	
2,22,357	(2) निगम का अंशदान	2,51,088	
15,92,389	(3) कर्मचारी तथा निगम के शेयरों पर ब्याज	19,05,150	
5,16,519	(4) मंहगाई भत्ता जमा राशि	18,59,349	
3,07,93,159	इस शीर्ष पर आगे ले जाया गया जोड़	3,72,80,779	
1,04,98,73,390	आगे ले जाया गया जोड़		1,26,40,50,640

सर्वकारी राज्य बीमा निगम
31 मार्च 1976 की स्थिति का तुलन पत्र

पिछला वर्ष (1974-75)	परिमर्पतिता	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
	भूमि व भवन (निगम के पूर्ण स्वामित्व में)		
	(क) निगम को कार्यालयों के लिए भवन		
1,31,76,888	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,38,46,193	
6,69,305	वर्ष के दौरान परिवर्धन	21,42,814	
1,38,46,193		1,59,89,007	
	(ख) अस्पताल तथा प्रौद्योगिक		
21,80,26,815	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	23,74,66,984	
1,94,40,169	वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,46,70,535	
23,74,66,984		26,21,37,519	
	(ग) अस्पतालों आदि के लिए उपकरण		
25,84,885	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	25,84,885	
—	वर्ष के दौरान परिवर्धन	—	
25,84,885		25,84,885	
25,38,98,062			28,07,11,411
	भूमि व भवन (निगम तथा राज्य सरकारों के संयुक्त स्वामित्व में) निगम का शेष		
	(क) अस्पताल तथा प्रौद्योगिक		
9,47,201	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	9,47,201	
—	वर्ष के दौरान परिवर्धन	(-) 70,074	
9,47,201		8,77,127	
	(ख) अस्पतालों आदि के लिये उपकरण		
49,680	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	49,680	
—	वर्ष के दौरान परिवर्धन	—	
49,680		49,680	
9,96,81			9,26,807
	(i) पूंजीगत व्यय के लिये की गई राशि		
6,00,06,749	पिछले तुलनपत्र के अनुसार जोड़े वर्ष के दौरान की गई अदायगियां	5,46,25,154	
(-) 53,81,595	घटायें समायोजन तथा वसूलियां	(-) 33,70,626	
5,46,25,154		5,12,54,528	
	(ii) पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि में से की गई राशि		
4,47,37,262	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	6,81,80,436	
3,96,28,100	जोड़ें—वर्ष के दौरान की गई अदायगियां	6,00,01,868	
(-) 1,61,84,926	घटायें—समायोजन तथा वसूलियां	(-) 2,58,85,723	
6,81,80,436		10,22,96,581	
12,28,05,590			15,35,51,109
	स्टाफ कार		
3,90,759	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,43,407	
52,648	जोड़ें—वर्ष के दौरान की गई अदायगियां	60,110	
4,43,407			5,03,517
37,81,43,940	आगे से आया गया जोड़		43,56,92,844

पिछला वर्ष (1974-75)	विवरण	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,04,98,73,390	पीछे से लाया गया जोड़	—	1,26,40,50,840
3,07,93,159	उप शीर्ष का पीछे से लाया गया जोड़	3,72,80,779	
	घटाएँ—वर्ष के दौरान की गई अदायगियां		
	भ० नि०—6505037		
(—) 49,48,378	मं० भत्ता—719502	(—) 72,24,539	
2,58,44,781		3,00,56,240	
	घटाएँ—निम्नलिखित में अन्तर्गत राशि :—		
(—) 4,57,692	(1) पेंशन आरक्षित निधि	(—) 36,114	
—	(2) बाबा न की गई जमा राशि	—	
2,53,87,089			3,00,20,126
	भविष्य निधि जमा राशि से जुड़ी बीमा निधि		
—	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	—	
—	वर्ष में की गई धन-व्यवस्था	50,000	
—	घटाएँ—वर्ष के दौरान की गई अदायगियां	—	
			50,000
	निगम के कार्यालयों के लिये भवनों (स्टाक क्वार्टरों सहित) की मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
14,78,806	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	17,92,087	
1,80,130	वर्ष में की गई धन-व्यवस्था	2,08,084	
1,33,151	निवेशों से प्राप्त ब्याज तथा लाभ	1,77,665	
17,92,087			21,77,836
	अस्पतालों भवनों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
1,59,32,411	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,98,23,149	
24,83,087	वर्ष में की गई धन-व्यवस्था	23,92,287	
13,98,485	निवेशों से प्राप्त ब्याज	19,29,190	
9,166	निवेशों की बसूली पर हानि या लाभ	—	
1,98,23,149			2,41,44,626
	स्टाक कारों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
2,84,404	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3,43,962	
34,565	वर्ष में की गई धन-व्यवस्था	45,522	
24,993	निवेशों से प्राप्त ब्याज	33,476	
3,43,962			4,22,960
	निगम के कार्यालय भवनों (स्टाक क्वार्टरों सहित) की मरम्मत व अनुरक्षण आरक्षित निधि		
28,44,143	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	32,69,903	
4,99,829	वर्ष में की गई धन-व्यवस्था	6,28,474	
1,56,253	निवेशों से प्राप्त ब्याज	2,07,034	
246	निवेशों की प्राप्ति पर लाभ	—	
35,00,471		41,05,411	
(—) 2,30,568	घटाएँ—वर्ष के दौरान की गई अदायगियां	(—) 2,11,833	
32,69,903			38,93,578
	अस्पताल भवनों की मरम्मत व अनुरक्षण आरक्षित निधि लेख		
3,47,42,825	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	4,38,57,162	
71,00,034	वर्ष में की गई धन-व्यवस्था	69,911,495	
228	निवेशों की बसूली पर लाभ	—	
4,43,37,515	इस शीर्ष का धागे ले जाया गया जोड़	5,44,37,765	
1,10,04,89,580	धागे ले जाया गया जोड़		1,32,47,59,766

पिछला वर्ष (1974-75)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
37,81,43,910	पीछे से लाया गया जोड़		43,56,92,844
41,038	निगम के कार्यालय भूखण्डों को स्थायी पेशगी	51,011	
10,063	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	6,840	
	जोड़ें—वर्ष के दौरान की गई अदायगियां		
51,101		57,851	
(—) 90	घटाएं—वर्ष के दौरान की गई वसूलियां	(—) 1,195	
51,011			56,856
	निगम के कर्मचारियों को स्थानान्तरण पर वेतन की पेशगी		
18,734	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	17,586	
83,804	जोड़ें—वर्ष के दौरान की गई अदायगियां	1,06,651	
1,02,538		1,24,237	
(—) 84,952	घटाएं—वर्ष के दौरान की गई वसूलियां	(—) 96,422	
17,586			27,815
	निगम के कर्मचारियों को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ते की पेशगी		
83,149	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	91,711	
1,06,507	जोड़ें—वर्ष के दौरान की गई अदायगियां	1,22,047	
1,89,556		2,13,758	
(—) 97,945	घटाएं—वर्ष के दौरान की गई वसूलियां	(—) 1,44,777	
91,711			68,981
	निगम के कर्मचारियों को वाहन खरीदने के लिये पेशगी		
9,62,131	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	10,07,452	
5,79,740	जोड़ें—वर्ष के दौरान की गई अदायगियां	5,81,031	
15,41,871		15,88,483	
(—) 5,34,419	घटाएं—वर्ष के दौरान की गई वसूलियां	(—) 6,47,039	
10,07,452			9,41,444
	निगम के कर्मचारियों को विविध पेशगियां (स्वीटार पेशगी)]		
3,63,551	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2,49,430	
5,07,497	जोड़ें—वर्ष के दौरान की गई अदायगियां	5,90,115	
8,71,048		8,39,545	
(—) 6,21,618	घटाएं—वर्ष के दौरान की गई वसूलियां	(—) 5,69,906	
2,49,430			2,69,639
	गृह निर्माण पेशगी		
2,23,703	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	32,96,614	
14,87,537	जोड़ें—वर्ष के दौरान की गई अदायगियां	19,34,700	
36,11,240		52,31,314	
(—) 3,14,626	घटाएं—वर्ष के दौरान की गई वसूलियां	(—) 5,58,417	
32,96,614			46,72,897
	राज्य सरकारों की ओर से प्रशिक्षण अदायगियां		
6,107	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	6,779	
6,191	जोड़ें—वर्ष के दौरान की गई अदायगियां	13,389	
(—) 5,519	घटाएं—वर्ष के दौरान की गई वसूलियां	(—) 5,405	
6,779			14,763
38,28,64,523	आगे से आया गया जोड़		44,17,45,039

पिछला वर्ष (1974-75)	विवरण	राशि	जोड़
		रुपये	रुपये
1,10,04,89,580	पीछे से लाया गया जोड़		1,32,47,59,766
4,43,37,515	हम शीर्ष का पीछे से लाया गया जोड़	5,44,37,765	
(—) 4,80,353	बटाएँ—वर्ष में की गई अदायगियाँ	(—) 24,24,882	
4,35,57,162			5,20,12,883
	निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन आरक्षित निधि		
4,13,37,616	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	4,96,82,756	
46,59,136	वर्ष में की गई धन-व्यवस्था	45,25,675	
36,87,266	निवेशों से प्राप्त ब्याज	49,44,749	
51,960	निवेशों की वसूली पर लाभ	—	
4,97,35,978		5,91,53,180	
(—) 5,10,914	बटाएँ वर्ष में की गई अदायगियाँ	(—) 6,73,813	
4,92,25,064		5,84,79,367	
	जोड़—कर्मचारी राज्य बीमा		
4,57,692	निगम भविष्य निधि से अंतरित राशि	36,114	
4,96,82,756			5,85,15,481
	निगम के कर्मचारियों के लिए अनुकम्पा आरक्षित निधि		
10,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	10,000	
12,250	वर्ष में की गई धनव्यवस्था	29,240	
22,250		39,240	
(—) 12,250	बटाएँ—वर्ष में की गई अदायगियाँ	(—) 29,240	
10,000			10,000
	आपात आरक्षित निधि		
5,63,56,000	पिछले वर्ष के संवयन से	8,22,60,672	
2,12,03,639	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	2,03,32,720	
47,01,033	निवेशों पर प्राप्त	74,22,703	
	बटाएँ—धाय से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व लेखों में अंतरित राशि		
8,22,60,672			11,00,16,095
	प्रतिभूतियों की जमा राशि		
2,40,402	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3,91,910	
3,19,799	जोड़—वर्ष में जमा की गई राशि	2,82,672	
5,60,201		6,74,582	
(—) 1,68,291	बटाएँ—वर्ष के दौरान बापिम की गई राशि	(—) 2,90,742	
3,91,910			3,83,840
	अन्य पार्टियों को देय बिलों से कटौती		
38,214	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	73,830	
6,89,878	जोड़—वर्ष में जमा की गई राशि	8,58,697	
7,28,092		9,32,527	
(—) 6,54,262	बटाएँ—वर्ष में की गई अदायगियाँ	(—) 9,05,833	
73,830			26,694
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि में अदा की जमा राशि		
8,366	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	5,795	
(—) 653	जोड़—वर्ष में जमा की गई राशि	784	
7,713		6,579	
(—) 1,918	बटाएँ—वर्ष में की गई अदायगियाँ	—	
5,795			6,579
1,27,67,71,705	घाते से जाया गया जोड़		1,54,57,31,338

पिछला वर्ष (1974-75)	परिमर्पसिया	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
38,28,64,523	पीछे से लाया गया जोड़ अस्पतालों/औषधालयों, निगम कार्यालयों तथा स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत व अनुसूक्षण के लिए राज्य सरकारों/राज्य लोक निर्माण विभागों आदि को दी गई राशि (क) निगम कार्यालय		44,17,45,039
8,38,038	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	9,35,419	
2,23,982	जोड़—वर्ष में की गई अदायगियां	7,73,304	
10,62,020		17,08,723	
(—) 1,26,601	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां/समायोजन	(—) 78,892	
9,35,419			16,29,831
	(ख) अस्पताल/औषधालय/भनेकियां		
65,04,827	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	78,49,227	
13,45,175	जोड़—वर्ष में की गई अदायगियां	38,55,943	
78,49,992		1,17,05,170	
(—) 765	घटाएं—वर्ष के दौरान प्राप्तियां	(—) 2,60,718	
78,49,227			1,14,44,452
	विविध पेशगियां		
12,32,435	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	18,42,317	
10,11,002	जोड़—वर्ष में की गई अदायगियां	10,45,288	
22,43,437		28,87,605	
(—) 4,01,120	घटाएं—वर्ष के दौरान प्राप्तियां	(—) 10,97,088	
18,42,317			17,90,517
	राज्य सरकारों/अन्य पार्टियों को कर्जे		
2,60,33,333	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3,02,99,999	
54,00,000	जोड़—वर्ष में की गई अदायगियां	23,58,500	
3,14,33,333		3,26,58,499	
(—) 11,33,334	घटाएं—राज्य सरकारों द्वारा वापिस की गई राशि	(—) 15,33,333	
3,02,99,999			3,11,25,166
	प्रेषण		
(—) 66,76,000	नकद प्रेषण		
1,34,97,14,531	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	8,48,061	
	जोड़—वर्ष में समायोजित	1,57,08,83,966	
1,34,30,38,531		1,57,17,32,027	
(—) 1,34,21,98,470	घटाएं—वर्ष में समायोजित जमा	(—) 1,57,15,33,028	
8,48,061			1,98,999
	अन्य प्रेषण विविध लेखा		
3,786	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	(—) 1,28,536	
5,91,67,305	जोड़—वर्ष के दौरान जमा	7,00,90,766	
5,91,71,091		6,99,62,230	
(—) 5,92,99,627	घटाएं—वर्ष के दौरान जमा	(—) 6,98,63,584	
(—) 1,28,536			98,646
42,45,11,010	आगे ले जाया गया जोड़		48,80,32,650

पिछला वर्ष (1974-75)	देयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,27,67,71,705	पीछे से लाया गया जोड़		1,54,57,31,338
	परिवार नियोजन परियोजना के लिए अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन से जमा राशि		
--	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	--	
--	जोड़-वर्ष में जमा राशि	5,00,000	
--	घटाएँ—परिवार नियोजन		
--	परियोजना की अवाधगियां	(-) 5,00,000	
--	विविध जमा राशि		--
17,8९,767	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	20,19,046	
10,93,435	जोड़—वर्ष में प्राप्त जमा राशि	59,10,770	
--			
28,82,202		79,29,816	
(-) 8,63,156	घटाएँ—वर्ष में वापिस की गई राशि	(-) 61,54,912	
--			
20,19,046			17,74,904

1,27,87,90,751 आगे ले जाया गया जोड़

1,54,75,06,242

पिछला वर्ष (1974-75)	परिस्थितियाँ	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
42,45,11,010	पीछे से लाया गया जोड़ लागत पर निवेश (1) स्थायी (आंशिक तथा पूर्ण) अपगता हितलाभ आरक्षित निधि		48,80,32,650
10,01,27,929	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	11,61,23,101	
2,62,78,175	जोड़—वर्ष में किया गया निवेश	3,45,95,000	
12,64,06,104		15,07,18,101	
(-) 1,02,83,003	घटाएँ—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर बसूली	(-) 95,000	
11,61,23,101			15,06,23,101
4,86,31,507	(2) आश्रित जन हितलाभ आरक्षित निधि पिछले तुलन पत्र के अनुसार	5,71,32,292	
1,59,91,400	जोड़—वर्ष में किया गया निवेश	1,11,03,000	
6,46,22,907		6,82,35,292	
(-) 74,90,615	घटाएँ—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर बसूली	---	
5,71,32,292			6,82,35,292
2,19,18,000	(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2,48,70,000	
61,63,200	जोड़—वर्ष में किया गया निवेश	37,22,000	
2,80,81,200		2,85,92,000	
(-) 32,11,200	घटाएँ—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर बसूली	(-) 2,35,000	
2,48,70,000			2,83,57,000
14,76,509	(4) निगम कार्यालयों की इमारतों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मूल्यह्रास आरक्षित निधि पिछले तुलन पत्र के अनुसार	17,91,509	
3,15,000	जोड़—वर्ष में किया गया निवेश	3,85,000	
17,91,509		21,76,509	
---	घटाएँ—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर बसूली	---	
17,91,509			21,76,509
---	(5) अस्पतालों तथा परीक्षा केंद्रों में उपकरणों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि पिछले तुलन पत्र के अनुसार	---	
---	जोड़—वर्ष में किया गया निवेश	---	
---		---	
---	घटाएँ—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर बसूली	---	
---		---	
1,58,04,359	(6) अस्पताल भवनों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1,98,22,525	
47,23,225	जोड़—वर्ष में किया गया निवेश	43,20,000	
2,05,27,584		2,41,42,525	
(-) 7,05,059	घटाएँ—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर बसूली	---	
1,98,22,525			2,41,42,525
2,83,735	(7) स्टाफ कारों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3,42,735	
89,100	जोड़—वर्ष में किया गया निवेश	80,000	
3,72,735		4,22,735	
(-) 30,100	घटाएँ—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर बसूली	---	
3,42,735			4,22,735
64,45,93,172	आगे से लाया गया जोड़		76,19,89,812

पिछला-वर्ष (1974-75)	देयताएँ	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,27,87,90.751	पीछे से लाया गया जोड़		1,54,75,06,242

1,27,87,90,751

आगे ले जाया गया जोड़

1,54,75,06,242

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लेखाओं का

मैंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1975-76 के पूर्वोक्त लेखाओं तथा 31 मार्च, 1976 की स्थिति के तुल्य पत्र की जाच की है तथा मैंने आपत्तियों के अधीन से प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में ये लेखा तथा तुल्य पत्र सही ढंग से बानये गये हैं तथा मुझे दी गई अधिकतम सूचना तथा स्पष्टीकरण गई दिल्ली विभाग 31 मई, 1976

पिछला वर्ष (1974-75)	परिमर्पणियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
64,45,93,172	पीछे से लाया गया जोड़		76,19,89,812
	(8) निगम के कार्यालयों की इमारतों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मरम्मत व अनुरक्षण		
	आरक्षित निधि		
19,29,994	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	23,00,240	
5,67,400	जोड़—वर्ष में किया गया निवेश	(—) 37,000	
24,97,394		22,63,240	
(—) 1,97,154	घटाएँ—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर बसूली	—	
23,00,240			22,63,240
	(9) अस्पताल भवनों की मरम्मत व अनुरक्षण आरक्षित निधि		
2,81,37,050	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3,59,47,278	
78,24,800	जोड़—वर्ष में किया गया निवेश	46,15,000	
3,59,61,850		4,05,62,278	
(—) 14,572	घटाएँ—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर बसूली	—	
3,59,47,278			4,05,62,278
	(10) निगम के कर्मचारियों के लिए पेशन आरक्षित निधि		
4,12,31,581	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	4,96,58,541	
1,81,68,200	जोड़—वर्ष में किया गया निवेश	88,54,000	
5,93,99,781		5,85,12,541	
(—) 97,41,240	घटाएँ—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर बसूली	—	
4,96,58,541		5,85,12,541	
	(11) पूंजीगत निर्यात आरक्षित निधि		
8,20,28,000	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	11,30,28,000	
8,10,00,000	जोड़—वर्ष में किया गया निवेश	2,73,30,000	
(—) 5,00,00,000	घटाएँ—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर बसूली	—	
11,30,28,000			14,03,58,000
	(12) आपात आरक्षित निधि		
5,60,00,000	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	8,20,00,000	
2,60,00,000	जोड़—वर्ष में किया गया निवेश	2,80,00,000	
—	घटाएँ—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर बसूली	—	
8,20,00,000			11,00,00,000
	सामान्य रोकड़ शेष		
23,25,00,000	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	30,79,37,000	
19,54,37,000	जोड़—वर्ष में किया गया निवेश	22,63,63,000	
42,79,37,000		53,43,00,000	
(—) 12,00,00,000	घटाएँ—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर बसूली	(—) 16,60,00,000	
30,79,37,000		36,83,00,000	
13,72,174	रोकड़ शेष	16,61,888	
4,19,54,346	बैंकों के पास रोकड़	6,38,58,483	
4,33,26,520		6,55,20,371	
35,12,63,520	कुल रोकड़ शेष		43,38,70,371
1,27,87,90,751	कुल जोड़		1,54,75,06,242

(पी० एल० गुप्ता)

बिजली इस्तेमालकर्ता तथा मुख्य सेवा अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम

वर्ष 1975-76 का लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

यह सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये जिनकी मुझे आवश्यकता थी। लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई के अनुसार, तथा निगम की पुस्तकों में दिखाये गये रूप में निगम के कार्यकलापों की सही तथा स्पष्ट स्थिति बसति है :

(के० पी० रंगा स्वामी) महा लेखाकार केन्द्रीय राजस्व

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वर्ष 1975-76 की सेवा-परीक्षा रिपोर्ट

1. सामान्य —

(i) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना अक्टूबर, 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत हुई थी। कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1951, 1966 तथा 1975 द्वारा यथा-संशोधित यह अधिनियम मौसमी कारखानों को छोड़ कर, उन सभी कारखानों पर लागू होता है जिनमें विद्युत शक्ति का प्रयोग होता है और 20 या इससे अधिक व्यक्ति मजदूरी पर काम करते हैं या करने थे। 1000/- रुपये तक मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारी योजना के अन्तर्गत आते हैं।

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(5) के अन्तर्गत योजना का धीरे-धीरे आगे विस्तार किया जा रहा है ताकि संस्थापनाओं के नीचे दिए गए नये वर्गों के कर्मचारियों को शामिल किया जा सके।

(क) कम विद्युत शक्ति का प्रयोग करने वाले ऐसे कारखाने जिनमें 10 से 19 व्यक्ति काम करते हैं तथा विद्युत शक्ति का प्रयोग न करने वाले ऐसे कारखाने जिनमें 20 या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं; तथा

(ख) ऐसी दुकानें, मिनेमा, थियेटर, रेस्तरां, होटल, सड़क-परिवहन, तथा समाचार-पत्र संस्थापनाएँ जिनमें 20 या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। योजना का विस्तार आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा दिल्ली और पाँचवें संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों पर संस्थापनाओं के नये वर्गों के लिए किया गया है। इस योजना में संस्थापनाओं के नये वर्गों को मिलाकर 31 मार्च, 1976 तक कुल 51.50 लाख कर्मचारी शामिल थे जबकि पिछले वर्ष के अंत में 50.50 लाख कर्मचारी थे।

(iii) वर्ष 1975-76 के दौरान अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार 6940 कारखानों पर किया गया था तथा इनमें काम करने वाले लगभग 8.25 लाख कर्मचारियों को योजना में शामिल किया गया था। 31 मार्च, 1976 को अधिनियम के अधीन आए गए कारखानों की संख्या 34384 (32,404 कार्यान्वयन क्षेत्रों में और 1980 गैर कार्यान्वयन क्षेत्रों में) थी। इनमें 58.75 लाख कर्मचारी (कार्यान्वयन क्षेत्रों में 51.50 लाख कर्मचारियों सहित, कार्य करते हैं।

(iv) वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 की बाबत निगम की आय व्यय का विश्लेषण नीचे दिया गया है —

आय	1974-75	1975-76	व्यय	1974-75	1975-76
	(लाख रुपये में)			(लाख रुपये में)	
कर्मचारियों एवं नियोजकों का शेयर	6,035	7,316	1. बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को हितलाभ		
केवल नियोजकों का अंशदान	217	178			
कर्मचारियों का अंशदान	101	100	(क) चिकित्सा हितलाभ		
कुल अंशदान	7,353	7,594	(1) चिकित्सा उपचार आदि पर किए गए खर्चों के लिए निगम के शेयर के रूप में राज्य सरकारों आदि को प्रदायगी	2,498	3,080
निवेश से प्राप्त व्याज तथा लाभांश	348	429			
चिकित्सा लाभ पर शुरू में निगम द्वारा किए गए व्यय में राज्य सरकार का शेयर	22	10	(ii) प्रत्यक्ष रूप से किए गए निगम द्वारा चिकित्सा उपचार तथा देखरेख एवं प्रसूति हितलाभ खर्च	152	195

विविध (किराया, रेंट तथा कर को शामिल करने हुए)	374	338	(ख) बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके प्राथितो को प्रत्यक्ष रूप से भिगम द्वारा दिए गए नकद एवं अन्य हित-साध	1,995	2,449
			2 प्रशासनिक खर्च		
			(क) अधीक्षण	352	429
			(ख) क्षेत्रीय कार्य	264	307
			(ग) अन्य खर्च	045	042
			3 अस्पताल एवं औषधालय	096	094
			4 पूंजीगत निर्माण (भारक्षण निधि)	635	759
			5 भ्रमण भ्रमण निधि	212	203
			6 म्यु के मुकाबले आय का प्रति-शेष	848	813
	7,097	8,371		7,097	8,371

2. वार्षिक लेखे/उत्पन्न लेखे .

31 मार्च, 1976 को विभिन्न विविध मदों पर बैंकों तथा अन्य फुटकर क्रेडिटों द्वारा दिए गए गलत क्रेडिटों की सूचक 17.75 लाख रुपये की शेष जमा राशि "उत्पन्न-लेखा—विविध जमा" के अन्तर्गत असमायोजित पड़ी हुई थी। नियम ने बताया है कि 30 जून, 1976 को यह शेष केवल 13.48 लाख रुपये रह गया है।

3. पेशगियाँ .—

- (i) राज्य-सरकार तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अस्पताल, औषधालय तथा अन्य इमारतें बनाने तथा परियोजनाओं के लिए पूंजीगत स्वरूप के अस्पताल उपस्कर खरीदने के लिए दी गई राशियों में से 31 मार्च, 1976 को 1535.51 लाख रुपये (वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है) की राशि असमायोजित रही।

वर्ष जिसमें पेशगी दी गई	31-3-1976 को असमायोजित रही राशि
	(लाख रुपयों में)
1966-67 तक	256.97
1967-68 "	118.53
1968-69 "	95.29
1969-70 "	45.20
1970-71 "	55.28
1971-72 "	83.02
1972-73 "	66.64
1973-74 "	58.61
1974-75 "	279.53
1975-76 "	476.44
	1535.51

- (ii) सरकारी विभागों, अर्ध-सरकारी संगठनों तथा प्राइवेट पार्टियों को लेखन सामग्री की पुस्त, वर्दी, विधि प्रभाग, स्थान किराये पर लेने के लिये किराया प्रादि के लिये दी गई राशियों में से 31 मार्च, 1976 को 17.91 लाख रुपये (वर्ष विवरण नीचे दिया गया है) की राशि असमायोजित रही।

वर्ष जिसमें पेशगी दी गई	31-3-76 को असमायोजित रही राशि
	(लाख रुपयों में)
1966-67 तक	1.04
1967-68 "	0.71
1968-69 "	2.61
1969-70 "	1.05
1970-71 "	2.15
1971-72 "	0.63
1972-73 "	0.98
1973-74 "	0.44
1974-75 "	4.49
1975-76 "	3.81
	17.91

- (iii) राज्य सरकारों/राज्य लोक निर्माण विभागों आदि को पूर्णतः निगम के स्वामित्व में वाले अपने अस्पतालों/प्रौद्योगिकी तथा शौचालयों की मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिये दी गई राशियों में से 31 मार्च, 1976 को 130.74 लाख रुपये (वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है) की राशि असमायोजित रही:—

वर्ष जिसमें पेसगी दी गई	31 मार्च, 1976 को असमायोजित रही राशि (लाख रुपयों में)
1966-67 तक	2.86
1967-68	4.19
1968-69	2.00
1969-70	4.33
1970-71	2.26
1971-72	8.78
1972-73	18.56
1973-74	26.38
1974-75	13.26
1975-76	48.12
	130.74

4. प्रसदान का बकाया :

मार्च, 1976 में कर्मचारियों और नियोजकों से 31 मार्च, 1975 तक के बकाया प्रसदान निम्न प्रकार थे (सितम्बर, 1975 में 30-9-1974 तक देय होने वाले प्रसदानों के बकाया की स्थिति भी तालिका में दिखाई गई है) :—

	30-9-74 तक बकाया	31-7-75 तक बकाया
	(लाख रुपयों में)	
नियोजकों का विशेष प्रसदान	925.16	874.10
कर्मचारियों का प्रसदान	321.63	313.25
नियोजकों तथा कर्मचारियों का संयुक्त प्रसदान (1-7-73 से आरंभ)	287.89	354.55
	1534.68	1541.90

प्रसदान की प्रदायगी न करते वाले 2044 कारखानों में से, (सितम्बर, 1976) 427 कारखानों में प्रत्येक को और 0.50 लाख रुपये से अधिक देनदारी थी। 31 मार्च, 1976 को निरीक्षण न किए जा सकें कारखानों की संख्या 4733 थी। नियोजकों के खिलाफ 32.08 लाख रुपये (वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है) की डिगिरियां (31 मार्च, 1976) निष्पादन के लिए गेच रह गई थीं।

वर्ष	(लाख रुपयों में)
1964-65	5.05
1965-66	0.85
1966-67	3.01
1967-68	3.22
1968-69	8.62
1969-70	3.44
1970-71	1.14
1971-72	0.89
1972-73	2.24
1973-74	0.37
1974-75	2.15
1975-76	1.30
	32.08

5. बकाया राशियाँ :

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत चिकित्सा हितसाम/मुविधायी पर होने वाला व्यय निगम तथा राज्यों के बीच अनुपात में शेयर किया जाता है। निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक व्यय भी राज्य-सरकारों द्वारा वहल किया जाता है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में शुरूआत में सारा खर्च निगम द्वारा किया गया था तथा बाद में दिल्ली प्रशासन से उसका दावा किया गया था। 31 मार्च, 1976 तक दिल्ली प्रशासन से 103.21 लाख रुपये की राशि वसूल की गई, जो इस प्रकार है :—

	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	जोड़
	(लाख रुपये में)				
व्यय की छाठवीं शेयर	—	—	—	20.54	20.54
अधिकतम सीमा से अधिक व्यय	—	33.23	25.33	18.08	76.64
बकाया राशियाँ	6.03	—	—	—	6.03
	6.03	33.23	25.33	38.62	103.21

6. "खाता" प्रदायगी :

बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा हितसाम के व्यय की बाबत निगम के शेयर के रूप में राज्य-सरकारों को की गई 'खाता' प्रदायगियों में से वर्ष 1969-70 से 1974-75 तक की अवधि से सम्बन्धित 3284.23 लाख रुपये (विवरण नीचे दिया गया है) की राशि का सन्नायोजन किया जाना बाकी था (30 सितम्बर, 1976)।

वर्ष	बकाया राशि
	(लाख रुपये में)
1969-70	32.23
1970-71	27.05
1971-72	177.79
1972-73	148.10
1973-74	825.75
1974-75	1973.31
	3284.23

7. अधिचिकित्सा हितसाम :

निगम प्रति वर्ष बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को दिये जाने वाले चिकित्सा हितसामों पर व्यय की बाबत प्रति कर्मचारी अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। नीचे तालिका में पिछले चार वर्षों के दौरान स्वीकार्य व्यय से अधिक व्यय बिखलाया गया है :

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी निर्धारित अधिकतम सीमा	स्वीकार्य व्यय	आन्तरिक व्यय	अधिक व्यय
			(रुपये)	(प्राक्छे लाख रुपये में)	
1972-73	115000	60	69.00	86.08	17.08
1973-74	120000	67	80.40	115.28	34.88
1974-75	132000	85	112.20	141.28	29.08
1975-76	156800	95	164.64	185.64	21.00

टिप्पणी :—वर्ष 1975-76 के दौरान स्वीकार्य व्यय के मुकाबले 15.68 लाख रुपये की वृद्धि अधिकतम सीमा के ऊपर औपेक्षिक तथा वसावों के लिए प्रतिरिक्त व्यवस्था के कारण है।

“निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक व्यय की जाँच अपयुक्त सजुरी के साथ नहीं की गई है तथा उसे नियमित नहीं किया गया है। यह भी देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष में निर्धारित अधिकतम सीमा 1975-76 वर्ष की छोड़कर पिछले वर्ष के प्रीमियम प्राप्ति के मुकाबले काफी कम थी।

[सं० जी-25012/1/77-एच० धार्ज०]

एम० एम० गह्वरनाथन, उप-सचिव

New Delhi, the 14th December, 1977

S.O. 4048.—In pursuance of section 36 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the audited accounts for general information.

EMPLOYEES' STATE
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

EXPENDITURE

Previous Year (1974-75)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
	1. Benefits to Insured Persons and their families		
	A. Medical Benefits.		
24,98,12,608	(i) Payments to State Governments etc., as Corporations Share of their expenses on providing medical treatment and maternity facilities etc.	30,80,17,039	
	Deduct :—Payments to State Govts. towards medical care during the year transferred to the Capital Construction/Medical Reserve Fund.		
24,98,12,608		30,80,17,039	
1,51,80,636	(ii) Medical treatment and Care and Maternity facilities (expenses incurred direct by the Corporation)	1,94,95,306	
26,49,93,244	Total A—Medical Benefits		32,75,12,345
	B—Cash Benefits		
11,35,36,831	(1) Sickness Benefit	12,81,80,389	
1,14,56,000	(2) Extended Sickness Benefit	1,40,17,842	
86,03,268	(3) Maternity Benefit	1,02,64,553	
	(4) Disablement Benefit		
2,07,65,636	(a) Temporary	2,48,54,977	
3,42,19,000	(b) Permanent (Capitalised Value)	5,42,40,000	
	(5) Dependants' Benefit (Capitalised Value)	1,16,99,000	
93,97,000	(6) Funeral Benefit	8,95,585	
8,96,653			
19,88,74,388	Total B—Cash Benefits		24,41,52,346
	C—Other Benefits		
74,890	(a) Expenditure on the Rehabilitation of Disabled Insured Persons	33,683	
2,44,176	(b) Medical Boards and Appeal Tribunals	3,15,771	
	(c) Payments to Insured Persons		
1,14,139	(i) Conveyance Charges and/or loss of wages	1,36,509	
	(ii) Incidental Charges under family planning		
	(d) Grants-in-aid		
2,25,523	(e) Miscellaneous	2,35,854	
6,58,728	Total C—Other Benefits		7,21,817
46,45,26,360	Total Benefits to Insured Persons and their families		57,23,86,508
	2. Administration Expenses		
	A—Superintendence		
69,556	1. Corporation, Standing Committee, Regional Boards etc	57,683	
1,81,013	2. Principal Officers	2,30,286	
36,64,180	3. Other Officers	45,15,551	
1,97,92,448	4. Ministerial Establishment	2,38,73,028	
35,21,247	5. Class IV Servants	43,07,210	
79,34,854	6. Contingencies	98,82,613	
3,51,63,298	Total A—Superintendence		4,28,66,371
	B—Field Work		
9,87,722	1. Officers	9,02,917	
1,99,03,554	2. Ministerial Establishment	2,34,96,864	
33,81,517	3. Class IV Servants	38,10,214	
21,55,958	4. Contingencies	24,51,084	
2,64,28,751	Total B—Field Work		3,06,61,079
52,61,18,409	Total Carried Over		64,59,13,958

of the Employees' State Insurance Corporation, together with audit report thereon, for the year 1975-76, are hereby published

INSURANCE CORPORATION
FOR YEAR ENDED 31ST MARCH, 1976

Previous Year (1974-75)		Heads of Account	Amount	Total
Rs			Rs	Rs
	1	Contributions		
60,34,74,995		Employer's and Employees' Shares	73,15,86,339	
2,16,80,542		Employers' Share only	1,78,07,427	
1,00,74,058		Employees' Share only	1,00,09,517	
63,52,29,595		Total Contributions		75,94,03,303
22,50,000		State Government/Union Territories shares towards medical benefits initially incurred by the Corporation	9,94,702	
				9,94,702
		Grants-in-Aid		
		Other Heads of Revenue		
3,47,90,454		Interest and Dividends	4,29,03,524	
1,55,75,398		Compensations	64,48,911	
		Rents, Rates and Taxes		
5,58,488		(i) Offices of the Corporation (including Staff Quarters)	6,91,664	
1,82,59,511		(ii) Hospitals, Dispensaries and Staff Quarters	2,47,78,048	
93,042		Fees, Fines and Forfeitures	1,69,145	
29,63,122		Miscellaneous	17,47,435	
7,22,40,015		Total of Other Heads of Revenue		7,67,38,727
70,97,19,610		Total Carried Over		83,71,36,732

Previous Year (1974-75)	Heads of Account	Amount	Total
Rs		Rs.	Rs.
52,61,18,409	Total Brought Forward		64,59,13,958
	C—Other Charges		
2,81,330	1. Legal Charges	2,72,245	
29,282	2. Insurance Courts	3,05,080	
26,133	3. Publicity and Advertisement Charges	22,127	
61,046	4. Charges for maintaining Banking Accounts	69,319	
1,29,950	5. Audit Fees	1,39,635	
96,818	6. Leave and Pension Contribution	1,22,199	
2,14,695	7. Depreciation of Office Building/Staff Cars	2,53,606	
4,99,829	8. Repairs and Maintenance of Office Buildings	6,28,474	
	9. Retirement Benefits		
42,65,343	(a) Pension Reserve Fund for the Employees of the Corporation	40,51,493*	
	(b) Corporations' Contribution towards Employees' State Insurance Corporation Provident Fund	2,51,088	
2,22,357	(c) Interest paid to ESIC Provident Fund	19,46,119	
15,92,389	(d) Loss on realisation of Investment		
(—)29,59,007	(e) Less Interest realised on investment of Provident Fund Balances	(—)39,13,674	
12,250	10. Compassionate Reserve Fund	29,240	
	11. Provident Fund Deposit—Linked Insurance Fund	50,000	
4,506	12. Miscellaneous	8,104	
6	13. Losses		
44,76,927	Total C—Other Charges		42,35,055
6,60,68,976	Total Head 2—Administration expenses		7,77,62,505
	3. Hospitals and Dispensaries		
24,83,087	1. Depreciation of Hospital Buildings	23,92,287	
71,00,034	2. Repairs and Maintenance Hospitals/Dispensaries	69,91,495	
95,83,121	Total Head 3—Hospitals and Dispensaries		93,83,782
	4. Capital Construction/Emergency Reserve Fund		
6,35,22,960	1. Capital Construction	7,59,40,330	
2,12,03,639	2. Emergency Reserve Fund	2,03,32,720	
8,47,26,599	Total Head 4—Capital Construction/Emergency Reserve Fund		9,62,73,050
62,49,05,056	Total Expenditure on Revenue Account		75,58,05,845
8,48,14,554	To excess of income over Expenditure carried over to Balance Sheet		8,13,30,887
70,97,19,610	Total carried over		83,71,36,732

*This excludes Rs. 4,74,182/- pertaining to pensionary liability of the employees of D.M.D. office which is included

New Delhi

Dated 31st May, 1976

Previous Year (1974-75)	Assets	Amount	Total
70,97,19,610	Total Brought Forward		83,71,36,732

70,97,19,610	GRAND TOTAL	83,71,36,732
--------------	-------------	--------------

under "A (ii) Medical Benefits" being shareable expenditure with Delhi Administration.

(P. L. Gupta)
Financial Adviser & Chief Accounts Officer
Employees' State Insurance Corporation

EMPLOYEES' STATE
Balance Sheet as on

Previous Year (1974-75)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
58,13,76,353	Balance of Excess of Income over expenditure	66,61,90,907	
8,48,14,554	As per last Balance Sheet	8,13,30,887	
	Accumulations during the year		
66,61,90,907		74,75,21,794	
	LESS Amount transferred to Emergency Reserve Fund from Last Years' Accumulation		
66,61,90,907			74,75,21,794
14,01,15,495	Capital Construction Reserve Fund Opening Balance	21,04,24,339	
	Amount transferred from Balance of Excess of Income over Expenditure		
6,35,22,960	ADD Provision made during the year	7,59,40,330	
67,85,884	Interest received on Investments	1,13,02,800	
	LESS Payments made during the year		
21,04,24,339			29,76,67,469
	Permanent (Partial and Total) Disablement Benefit Reserve Fund		
10,01,29,732	As per last Balance Sheet	11,61,23,653	
3,42,19,000	Provision made during the year	5,42,40,000	
76,42,100	Interest received from Investments	99,05,014	
1,35,172	Gain on realisation of Investments		
14,21,26,004		18,02,68,667	
(—)2,60,02,351	LESS Payments made during the year	(—)2,96,42,742	
11,61,23,653			15,06,25,925
	Dependants' Benefit Reserve Fund		
4,86,32,421	As per last Balance Sheet	5,71,34,491	
93,97,000	Provision made during the year	1,16,99,000	
41,00,346	Interest received from Investments	51,98,646	
1 17,785	Gain on realisation of Investments		
6,22,47,552		7,40,32,137	
(—)51,13,061	LESS Payments made during the year	(—)57,96,685	
5,71,34,491			6,82,35,452
	Employees' State Insurance Corporation Provident Fund		
2,19,38,188	As per last Balance Sheet	2,53,87,089	
	ADD amount credited during the year		
65,23,706	(i) Employees' Subscription	78,78,103	
2,22,357	(ii) Corporation's Contribution	2,51,088	
15,92,389	(iii) Interest on (Employees' and Corporation's Shares)	19,05,150	
5,16,519	(iv) D.A. Deposits	18,59,349	
3,07,93,159	Total Carried over of this head	3,72,80,779	
1,04,98,73,390	Total Carried over		1,26,40,50,640

INSURANCE CORPORATION

31 March 1976

Previous Year (1974-75)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
	Lands and Buildings (wholly owned by the Corporation).		
	(a) Buildings for Offices of the Corporation		
1,31,76,888	As per last Balance Sheet	1,38,46,193	
6,69,305	Additions during the year	21,42,814	
1,38,46,193		1,59,89,007	
	(b) Hospitals and Dispensaries.		
21,80,26,815	As per last Balance Sheet	23,74,66,984	
1,94,40,169	Additions during the year	2,46,70,535	
23,74,66,984		26,21,37,519	
	(c) Equipments for Hospitals etc.		
25,84,885	As per last Balance Sheet	25,84,885	
..	Additions during the year	..	
25,84,885		25,85,885	
25,38,98,062			28,07,11,411
	Lands and Building (Jointly owned by the Corporation and State Governments) Corpora- tions Share		
	(a) Hospitals and Dispensaries.		
9,47,201	As per last Balance Sheet	9,47,201	
..	Additions during the year	(—)70,074	
9,47,201		8,77,127	
	(b) Equipments for Hospitals etc.		
49,680	As per last Balance Sheet	49,680	
..	Additions during the year	..	
49,680		49,680	
9,96,881			9,26,807
	Suspense (i) Amount Advanced for Capital Expenditure.		
6,00,06,749	As per last Balance Sheet	5,46,25,154	
..	ADD Payments made during the year	..	
(—)53,81,595	LESS Adjustments and Recoveries	(—)33,70,626	
5,46,25,154		5,12,54,528	
	(ii) Amount advanced from Capital Construction Reserve Fund.		
4,47,37,262	As per last Balance Sheet	6,81,80,436	
3,96,28,100	ADD Payments made during the year	6,00,01,868	
(—)1,61,84,926	LESS Adjustments and Recoveries	(—)2,58,85,723	
6,81,80,436		10,22,96,581	
12,28,05,590			15,35,51,109
	Staff Cars.		
3,90,759	As per last Balance Sheet	4,43,407	
52,648	ADD Payments made during the year	60,110	
4,43,407			5,03,517
7,81,43,940	Total Carried Over		43,56,92,844

Previous Year (1974-75)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,04,98,73,390	Total Brought Forward		1,26,40,50,640
3,07,93,159	Total Brought Forward of the Sub-Head	3,72,80,779	
	LESS Payments made during the year.		
	PF : 6505037		
(—)49,48,378	DA : 719502	(—)72,24,539	
2,58,44,781		3,00,56,240	
	LESS amount transferred to:—		
(—)4,57,692	(i) Pension Reserve Fund	(—)36,114	
	(ii) Unclaimed deposit		
2,53,87,089			3,00,20,126
	Provident Fund Deposit linked Insurance Fund		
	As per last Balance Sheet		
	Provision made during the year	50,000	
	LESS Payments made during the year		
			50,000
	Depreciation Reserve Fund of Buildings for the Offices of the Corporation (including Staff Quarters)		
14,78,806	As per last Balance Sheet	17,92,087	
1,80,130	Provision made during the year	2,08,084	
1,33,151	Interest and gain received from investments	1,77,665	
17,92,087			21,77,836
	Depreciation Reserve Fund of Hospital Buildings		
1,59,32,411	As per last Balance Sheet	1,98,23,149	
24,83,087	Provision made during the year	23,92,287	
13,98,485	Interest received from Investments	19,29,190	
9,166	Loss or Gain on realisation of Investments		
1,98,23,149			2,41,44,626
	Depreciation Reserve Fund of Staff Cars.		
2,84,404	As per last Balance Sheet	3,43,962	
34,565	Provision made during the year	45,522	
24,993	Interest received from investments	33,476	
3,43,962			4,22,960
	Repairs & Maintenance Reserve Fund of Buildings for the Offices of the Corporation (including Staff Quarters).		
28,44,143	As per last Balance Sheet	32,69,903	
4,99,829	Provision made during the year	6,28,474	
1,56,253	Interest received from Investments	2,07,034	
246	Gain on realisation of Investments		
35,00,471		41,05,411	
(—)2,30,568	LESS Payments made during the year	(—)2,11,833	
32,69,903			38,93,578
	Repairs & Maintenance Reserve Fund Accounts of Hospital Buildings.		
3,47,42,825	As per last Balance Sheet	4,38,57,162	
71,00,034	Provision made during the year	69,91,495	
24,94,428	Interest received from Investments	35,89,108	
228	Gain on realisation of Investments		
4,43,37,515	Total Carried over of this Head	5,44,37,765	
1,10,04,89,580	Total Carried over		1,32,47,59,756

Previous Year (1974-75)	Assets	Amount	Total
		Rs.	Rs.
37,81,43,940	Total Brought Forward		43,56,92,844
	Permanent Advance to the Heads of Offices of the Corporation.		
41,038	As per last Balance Sheet	51,011	
10,063	ADD Payments made during the year	6,840	
51,101		57,851	
(—)90	LESS Recoveries made during the year	(—)1,195	
51,011			56,656
	Advance of Pay on transfer to the Employees of the Corporation		
18,734	As per last Balance Sheet	17,586	
83,804	ADD Payments made during the year	1,06,651	
1,02,538		1,24,237	
(—)84,952	LESS Recoveries made during the year	(—)96,422	
17,586			27,815
	Advance of T.A. on transfer to the Employees of the Corporation.		
83,149	As per last Balance Sheet	91,711	
1,06,507	ADD Payments made during the year	1,22,047	
1,89,556		2,13,758	
(—)97,945	LESS Recoveries made during the year	(—)1,44,777	
91,711			68,981
	Advance for the purchase of Conveyance to the Employees of the Corporation.		
9,62,131	As per last Balance Sheet	10,07,452	
5,79,740	ADD Payments made during the year	5,81,031	
15,41,871		15,88,483	
(—)5,34,419	LESS Recoveries made during the year	(—)6,47,039	
10,07,452			9,41,444
	Miscellaneous Advances to the Employees of the Corporation. (Festival Advances)		
3,63,551	As per last Balance Sheet	2,49,430	
5,07,497	ADD Payments made during the year	5,90,115	
8,71,048		8,39,545	
(—)6,21,618	LESS Recoveries made during the year	(—)5,69,906	
2,49,430			2,69,639
	House Building Advance.		
21,23,703	As per last Balance Sheet	32,96,614	
14,87,537	ADD Payments made during the year	19,34,700	
36,11,240		52,31,314	
(—)3,14,626	LESS Recoveries made during the year	(—)5,58,417	
32,96,614			46,72,897
	Advance Payments on behalf of State Governments		
6,107	As per last Balance Sheet	6,779	
6,191	ADD Payments during the year	13,889	
12,298		20,168	
(—)5,519	LESS Recoveries made during the year	(—)5,405	
6,779			14,763
38,28,64,523	Total Carried over		44,17,45,039

Previous Year (1974-75)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,10,04,89,580	Total Brought Forward		1,32,47,59,766
4,43,37,515	Total Brought Forward of this Head	5,44,37,765	
(—)4,80,353	Less Payments made during the year	(—)24,24,882	
4,38,57,162			5,20,12,883
	Pension Reserve Fund for the Employees of the Corporation		
4,13,37,616	As per last Balance Sheet	4,96,82,756	
46,59,136	Provision made during the year	45,25,675	
36,87,266	Interest received from Investments	49,44,749	
51,960	Gain on realisation of Investments	..	
4,97,35,978		5,91,53,180	
(—)5,10,914	Less Payments made during the year.	(—)6,73,813	
4,92,25,064		5,84,79,367	
4,57,692	ADD Amount transferred from ESIC Provident Fund	36,114	
4,96,82,756			5,85,15,481
	Compassionate Reserve Fund for the Employees of the Corporation.		
10,000	As per last Balance Sheet	10,000	
12,250	Provision made during the year	29,240	
22,250		39,240	
(—)12,250	Less Payments made during the year	(—)29,240	
10,000			10,000
5,63,56,000	Emergency Reserve Fund From Last Year's Accumulation	8,22,60,672	
2,12,03,039	Provision made during the year	2,03,32,720	
47,01,033	Interest realised on Investment	74,22,703	
..	LESS amount transferred to the Revenue		
	Account for meeting the Excess of Expenditure over the Income		
8,22,60,672			11,00,16,095
	Deposits of Securities.		
2,40,402	As per last Balance Sheet	3,91,910	
3,19,799	ADD Deposits during the year	2,82,672	
5,60,201		6,74,582	
(—)1,68,291	Less Deposits repaid during the year	(—)2,90,74	
3,91,910			3,83,840
	Deduction from Bills Payable to other Parties.		
38,214	As per last Balance Sheet	73,830	
6,89,878	ADD amount Credited during the year	8,58,697	
7,28,092		9,32,527	
(—)6,54,262	LESS Payments made during the year	(—)9,03,833	
73,830			26,694
	Unclaimed Deposits in the ESIC Provident Fund.		
8,366	As per last Balance Sheet	5,795	
(—)653	ADD Amount Credited during the year	784	
7,713		6,579	
(—)1,918	Less Payments made during the year.	..	
5,795			6,579
1,27,67,71,705	Total Carried Over		1,54,57,31,338

Previous Year (1974-75)	Assets	Amount	Total
		Rs.	Rs.
38,28,64,523	Total Brought Forward.		44,17,45,039
	Amount advanced to State Govt./State P.W.D etc. towards Repairs and Maintenance of Hospitals/Dispensaries, Offices of the Corporation and Staff Quarters.		
	(a) Offices of the Corporation.		
8,38,038	As per last Balance Sheet.	9,35,419	
2,23,982	ADD Payments made during the year	7,73,304	
10,62,020		17,08,723	
(—)1,26,601	LESS Recoveries/Adjustments made during the year	(—)78,892	
9,35,419			16,29,831
	(b) Hospitals/Dispensaries/Annexes.		
65,04,817	As per last Balance Sheet	78,49,227	
13,45,175	ADD Payments made during the year	38,55,943	
78,49,992		1,17,05,170	
(—)765	LESS Receipts during the year	(—)2,60,718	
78,49,227			1,14,44,452
	Miscellaneous Advances.		
12,32,435	As per last Balance Sheet.	18,42,317	
10,11,002	ADD Payments made during the year.	10,45,288	
22,43,437		28,87,605	
(—)4,01,120	LESS Receipts during the year	(—)10,97,088	
18,42,317			17,90,517
	Loans to State Governments/Other Parties		
2,60,33,333	As per last Balance Sheet	3,02,99,999	
54,00,000	ADD Payments made during the year	23,58,500	
3,14,33,333		3,26,58,499	
(—)11,33,334	LESS amount refunded by State Governments	(—)15,33,333	
3,02,99,999			3,11,25,166
	Remittances.		
	Cash Remittances.		
(—)66,76,000	As per last Balance Sheet	8,48,061	
1,34,97,14,531	ADD Debits adjusted during the year	1,57,08,83,966	
1,34,30,38,531		1,57,17,32,027	
(—)1,34,21,90,470	LESS credits adjusted during the year	(—)1,57,15,33,028	
8,48,061			1,98,999
	Other Remittances, Exchange Account		
3,786	As per last Balance Sheet	(—)1,28,536	
5,91,67,305	ADD Debits during the year	7,00,90,766	
5,91,71,091		6,99,62,230	
(—)5,92,99,627	LESS Credits during the year	(—)6,98,63,584	
(—)1,28,536			98,646
42,45,11,010	Total Carried Over		48,80,32,650

Previous Year (1974-75)	Liabilities	Amount	Total
		Rs.	Rs.
1,27,67,71,705	Total Brought Forward		1,54,57,31,338
	Deposits from I.L.O. for Family Planning Project.		
	As per Last Balance Sheet		
	ADD : Deposits during the year	5,00,000	
	LESS : Payments to the Family Planning Project	(—)5,00,000	
	Miscellaneous Deposits	—	
17,88,767	As per Last Balance Sheet	20,19,046	
10,93,435	ADD : Deposits received during the year	59,10,770	
28,82,202		79,29,816	
(—)8,63,156	LESS : Deposits repaid during the year	(—)61,54,912	
20,19,046			17,74,904

1,27,87,90,751	Total Carried Over	1,54,75,06,24 2
----------------	--------------------	-----------------

Previous Year (1974-75)	Assets	Amount	Total
		Rs.	Rs.
42,45,11,010	Total Brought Forward		48,80,32,650
	Investments at Cost :		
	(1) Permanent (Partial and Total)		
	Disablement Benefit Reserve Fund :		
10,01,27,929	As per last Balance Sheet	11,61,23,101	
2,62,78,175	ADD : Investments made during the year	3,45,95,000	
12,64,06,104		15,07,18,101	
(-)-1,02,83,003	LESS : Realisation on Maturity or Sale of Investments	(-)-95,000	
11,61,23,101			15,06,23,101
	(2) Dependants' Benefit Reserve Fund :		
4,86,31,507	As per last Balance Sheet	5,71,32,292	
1,59,91,400	ADD : Investments made during the year	1,11,03,000	
6,46,22,907		6,82,35,292	
(-)-74,90,615	LESS : Realisation on Maturity or Sale of Investments	
5,71,32,292			6,82,35,292
	(3) Employees' State Insurance Corporation Provident Fund :		
2,19,18,000	As per last Balance Sheet	2,48,70,000	
61,63,200	ADD : Investments made during the year	37,22,000	
2,80,81,200		2,85,92,000	
(-)-32,11,200	LESS : Realisation on Maturity or Sales of Investments	(-)-2,35,000	
2,48,70,000			2,83,57,000
	(4) Depreciation Reserve Fund of Buildings for the Offices of the Corporation (Including Staff Quarters) :		
14,76,509	As per last Balance Sheet	17,91,509	
3,15,000	ADD : Investments made during the year	3,85,000	
17,91,509		21,76,509	
..	LESS : Realisation on Maturity or Sale of Investments	
17,91,509			21,76,509
	(5) Depreciation Reserve Fund of Equipments in Hospital and Examination Centres :		
..	As per last Balance Sheet	
..	ADD : Investments made during the year	
..		..	
..	LESS : Realisation on Maturity or Sale of Investments	
..		..	
	(6) Depreciation Reserve Fund of Hospital Buildings :		
1,58,04,359	As per last Balance Sheet	1,98,22,525	
47,23,225	ADD : Investments made during year	43,20,000	
2,05,27,584		2,41,42,525	
(-)-7,05,059	LESS : Realisation on Maturity or Sale of Investments	
1,98,22,525			2,41,42,525
	(7) Depreciation Reserve Fund of Staff Cars :		
2,83,735	As per last Balance Sheet	3,42,735	
89,100	ADD : Investments made during the year	80,000	
3,72,835		4,22,735	
(-)-30,100	LESS : Realisation on Maturity or Sale of Investment	
3,42,735			4,22,735
64,45,93,172	Total Carried Over		76,19,89,812

Previous Year (1974-75)	Liabilities	Amount	Total
		Rs.	Rs.
1,27,87,90,751	Total Brought Forward		1,54,75,06,242

Previous year 1974-75	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
64,45,93,172	Total Brought Forward		76,19,89,812
	(8) Repairs and Maintenance Reserve Fund of Buildings for the Offices of the Corporation (including Staff Quarters) :		
19,29,994	As per last Balance Sheet	23,00,240	
5,67,400	ADD : Investments during the year	(—)37,000	
24,97,394		22,63,240	
(—)1,97,154	LESS : Realisation on Maturity or Sale of Investments	..	
23,00,240			22,63,240
	(9) Repairs and Maintenance Reserve Fund of Hospital Buildings :		
2,81,37,050	As per last Balance Sheet	3,59,47,278	
78,24,800	ADD : Investments made during the year	46,15,000	
3,59,61,850		4,05,62,278	
(—)14,572	LESS : Realisation on Maturity or Sale of Investments	..	
3,59,47,278			4,05,62,278
	(10) Pension Reserve Fund for the Employees of the Corporation :		
4,12,31,581	As per last Balance Sheet	4,96,58,541	
1,81,68,200	ADD : Investments made during the year	88,54,000	
5,93,99,871		5,85,12,541	
(—)97,41,240	LESS : Realisation on Maturity or Sale of Investments	..	
4,96,58,541			5,85,12,541

73,24,99,231 Total Carried over 86,33,27,871

Previous Year (1974-75)	Liabilities	Amount	Total
		Rs.	Rs.
1,27,87,90,751	Total Brought Forward		1,54,75,06,242

1,27,87,90,751	GRAND TOTAL	1,54,75,06,242
----------------	-----------------------	----------------

AUDIT

I have examined the foregoing accounts for the year 1975-76 and the Balance Sheet as on 31st March, 1976 of the Employees' in the Audit Report appended, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and the Balance Sheet are mation and explanations given to me and as shown by the books of the Corporation.

Previous Year (1974-75)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
73,24,99,231	Total Brought Forward		86,33,27,871
	(11) Capital Construction Reserve Fund.		
8,20,28,000	As per last Balance Sheet	11,30,28,000	
8,10,00,000	ADD Investments during the year	2,73,30,000	
(—)5,00,00,000	Deduct—Realisation on Maturity or Sale of Investments		
11,30,28,000			14,03,58,000
	(12) Emergency Reserve Fund.		
5,60,00,000	As per last Balance Sheet	8,20,00,000	
2,60,00,000	ADD Investments during the year	2,80,00,000	
	Deduct—Realisation on Maturity or Sale of Investments		
8,20,00,000			11,00,00,000
	General Cash Balance.		
23,25,00,000	Investment as per last Balance Sheet	30,79,37,000	
19,54,37,000	ADD Investments made during the year	22,63,63,000	
42,79,37,000		53,43,00,000	
(—)12,00,00,000	LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments	(—)16,60,00,000	
30,79,37,000		36,83,00,000	
13,72,174	Cash in Hand	16,61,888	
4,19,54,346	Cash with Bankers	6,38,58,483	
4,33,26,520		6,55,20,371	
35,12,63,520	Total Cash Balance		43,38,20,371
1,27,87,90,751	GRAND TOTAL		1,54,75,06,242

(P. L. GUPTA)
Financial Adviser and Chief Accounts Officer,
Employees' State Insurance Corporation.

CERTIFICATE

State Insurance Corporation and obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Corporation according to the best of my infor-

Sd/-
(K. P. RANGASWAMI,
Accountant General,
Central Revenues.

New Delhi,
Dated 10th June, 77.

Administrative cost compared with Benefits paid etc.

	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76
I. Total Administrative cost	3,71,91,289	4,77,39,056	4,40,34,287	7,34,57,795	6,60,68,976	7,77,62,505
II. (i) Employees' & Employer's share	20,37,86,214	60,34,74,995	73,15,86,339
(ii) Employer's Special Contribution	29,55,06,981	33,34,80,630	39,61,61,207	21,41,95,502	2,16,80,542	1,78,07,427
(iii) Employees' Contribution	16,49,66,819	17,70,05,192	19,16,27,812	22,76,57,964	1,00,74,058	1,00,09,537
Total Contributions	46,04,73,800	51,04,85,822	58,77,89,019	64,56,39,680	63,52,29,595	75,94,03,303
III. Total outgoings (Expenditure on Revenue Accounts)	44,74,00,835	47,61,40,297	47,23,75,970	59,90,70,572	62,49,05,056	75,58,05,845
IV. Total Benefits	36,68,88,880	38,16,11,406	37,13,48,489	45,14,88,325	46,45,25,360	57,23,86,508
Ratio of Administrative cost to :—						
II.	8.08%	9.35%	7.50%	7.72%	10.40%	10.24%
III.	8.31%	10.03%	9.32%	8.32%	10.57%	10.29%
IV.	10.14%	12.51%	11.86%	11.04%	14.22%	13.59%

Note :—IV does not include share of benefit expenditure borne by the State Governments.

AUDIT REPORT ON EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION FOR THE YEAR 1975-76

1. General.

(i) The Employees' State Insurance Corporation was set up in October, 1948 under the Employees' State Insurance Act, 1948. The Act, as amended by the Employees' State Insurance (Amendment) Acts of 1951, 1966 and 1975 applies to all Factories, other than seasonal factories, which use power and where 20 or more persons are or were employed for wages. All employees getting monthly remuneration upto Rs.1000 are covered under the scheme.

(ii) The Scheme is further being extended gradually to cover employees in the following new classes of establishments under section 1(5) of the Employees' State Insurance Act, 1948:

- (a) smaller power using factories employing 10—19 persons and non-power using factories employing 20 or more persons, and
- (b) shops, cinemas, theatres, restaurants, hotels, road transport and newspaper establishments employing 20 or more persons.

The Scheme has been extended to the new classes of establishments at different centres in the States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Haryana, Karnataka, Kerala, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal and Union Territories of Delhi and Pondicherry. The total coverage including new classes of establishments as on 31st March, 1976 stood at 51.50 lakhs employees as against 50.50 lakhs employees at the end of the previous year.

(iii) During 1975-76, the provisions of the Act were extended to 6,940 factories covering about 8.25 lakhs employees. The number of factories covered by the Act on 31st March, 1976 was 34,384 (32,404 in implemented areas and 1,980 in non-implemented areas) having 58.75 lakhs employees (including 51.50 lakhs in implemented areas).

(iv) An analysis of the income and expenditure of the Corporation for 1974-75 and 1975-76 is given below :

INCOME	1974-75 (lakhs of rupees)	1975-76	EXPENDITURE	1974-75 (lakhs of rupees)	1975-76
Employees' and Employer's share	6,035	7,316	1. Benefits to insured persons and their families.		
Employers' contribution only	217	178	A. Medical Benefits.		
Employees' contribution	101	100	(i) Payments to State Government etc. as Corporation share of their expenses on providing medical treatment etc.	2,498	3,080
Total contributions	6,353	7,594			
Interest and Dividends from investment.	348	429	(ii) Medical treatment and care and maternity benefits expenses incurred directly by the Corporation.	152	195

INCOME	1974-75 (lakhs of rupees)	1975-76	EXPENDITURE	1974-75 (lakhs of rupees)	1975-76
State Governments share towards medical benefits initially borne by the Corporation.	22	10	B. Cash and other benefits to insured persons and their dependents paid directly by the Corporation.	1,995	2,449
Miscellaneous including rents, rates and taxes.	374	338	2. Administrative Expenses.		
			A. Superintendence	352	429
			B. Field Work	264	307
			C. Other Charges	045	042
			3. Hospital and Dispensaries	096	094
			4. Capital construction (Reserve Fund)	635	759
			5. Emergency Reserve Fund	212	203
			6. Excess of income over expenditure.	848	813
	7,097	8,371		7,097	8,371

2. Annual accounts—Suspense Accounts.

A credit balance of Rs. 17.75 lakhs representing erroneous credits afforded by the banks and other sundry credits on various miscellaneous items was lying unadjusted under "Suspense account—Miscellaneous Deposits" as on 31st March, 1976. The Corporation has stated that this Balance as on 30th June 1976 is Rs. 13.48 lakhs only

3. Advances.

(i) Out of the amounts advanced to State Governments and Central Public Works Department for construction of hospitals, dispensaries and other buildings and for purchase of hospital equipments of capital nature for projects, Rs. 1535.51 lakhs (year-wise break up given below) remained unadjusted on 31st March, 1976.

Year in which advance paid.		Remaining unadjusted as on 31st March, 1976.
		(lakhs of rupees)
Upto	1966-67	256.97
	1967-68	118.53
	1968-69	95.29
	1969-70	45.20
	1970-71	55.28
	1971-72	83.02
	1972-73	66.64
	1973-74	58.61
	1974-75	279.53
	1975-76	476.44
		1,535.51

(ii) Out of amounts advanced to the Government department, semi-government organisations and private parties on account of supply of stationery, liveries, law charges, rent for hiring accommodation, etc., Rs. 17.91 lakhs (year-wise details given below) remained unadjusted on 31st March, 1976.

Year in which advance paid		Remaining unadjusted as on 31st March, 1976
		(rupees in lakhs)
Upto	1966-67	1.04
	1967-68	0.71
	1968-69	2.61
	1969-70	1.05
	1970-71	2.15
	1971-72	0.63
	1972-73	0.98
	1973-74	0.44
	1974-75	4.49
	1975-76	3.81
		17.91

(iii) Out of amounts advanced to the State Governments/State Public Works Departments etc. towards repairs and maintenance of hospitals/dispensaries and office buildings wholly owned by the Corporation, Rs. 130.74 lakhs (year-wise details given below) remained unadjusted on 31st March, 1976.

	Year in which advance paid	Remaining unadjusted as on 31st March, 1976.
		(rupees in lakhs)
Upto	1966-67	2.86
	1967-68	4.19
	1968-69	2.00
	1969-70	4.33
	1970-71	2.26
	1971-72	8.78
	1972-73	18.56
	1973-74	26.38
	1974-75	13.26
	1975-76	48.12
		130.74

4. Arrears of contribution.

In March, 1976 arrears of contribution due from the employees and employers upto 31st March 1975 were as follows (The position in September, 1975 of arrears of contribution which became due upto 30th September 1974 is also indicated in the table).

	Due upto 30-9-74	Due upto 31-3-75
	(Lakhs of rupees)	
Employers' Special Contribution	925.16	874.10
Employees' Contribution.	321.63	313.25
Employers' + Employees' combined contribution (started w.e.f. 1-7-1973)	287.89	354.55
	1534.68	1541.90

Out of 2044 factories defaulting in the payment of contribution, 427 factories were in default (September 1976) for more than Rs. 0.50 lakhs each. Number of factories remaining uninspected stood at 4733 as on 31st March, 1976.

Decees for Rs. 32.08 lakhs (year-wise details given below) remained to be executed (31st March, 1976) against employers.

Upto	Lakhs of rupees
1964-65	5.05
1965-66	0.85
1966-67	3.01
1967-68	3.22
1968-69	8.62
1969-70	3.44
1970-71	1.14
1971-72	0.89
1972-73	2.24
1973-74	0.17
1974-75	2.15
1975-76	1.30
	32.08

5. Outstanding dues.

Under the provisions of Employees' State Insurance Corporation Act, the expenditure on medical benefits/facilities is shareable in the ratio of 7 : 1 between the Corporation and the States. Expenditure in excess of prescribed ceiling is also to be borne by the States. In the Union Territory of Delhi the expenditure was initially borne by the Corporation and then claimed from the Delhi Administration. Rs. 103.21 lakhs were recoverable from the Delhi Administration upto 31st March, 1976 as under :—

	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	Total
	(Figures in lakhs of rupees)				
1/8th share of expenditure	20.54	20.54
Expenditure in excess of ceiling	33.23	25.33	18.08	76.64
Outstanding arrears.	6.03	6.03
TOTAL	6.03	33.23	25.33	38.62	103.21

6. "On Account" payments.

Out of "On Account" payments made to State Governments as Corporation's share towards cost of medical benefits to insured persons and their families, Rs. 3284.23 lakhs (detailed below) relating to the year 1969-70 to 1974-75 were awaiting adjustments (30th September 1976).

Yes	Balance Outstanding
	(Rupees in lakhs)
1969-70	32.23
1970-71	27.05
1971-72	177.79
1972-73	148.10
1973-74	925.75
1974-75	1973.31
	3284.23

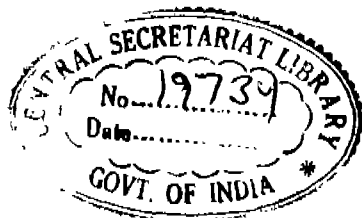
Medical benefits.

The Corporation fixes each year, a ceiling per employee towards expenditure on medical benefits given to the insured persons and their families. The following table shows the excess over permissible expenditure during the last four year.)

Year	No. of employees.	Ceiling per employee per annum.	Permissible expenditure.	Actual expenditure.	Excess expenditure.
		(rupees)	(Figures in lakhs of rupees)		
1972-73	1,15,000	60	69.00	86.08	17.08
1973-74	1,20,000	67	80.40	115.28	34.88
1974-75	1,32,000	85	112.20	141.28	29.08
1975-76	1,56,800	95	164.64	185.64	21.00

*Note : Increase of Rs. 15.68 lakhs over the permissible expenditure during 1975-76 is due to extra provision for drugs and medicines over and above the ceilings.

The excess expenditure over the prescribed ceiling has not been examined and regularised under appropriate sanction. It is also seen that ceiling prescribed in each year was considerably less than the average expenditure of the previous year except for 1975-76.



Sd/-

K. P. RANGASWAMI,
Accountant General,
Central Revenues

[No. G-25012/1/77-HI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

